समय-समय पर उनकी कार्यकुशलता के आधार पर प्रोन्नति देने की घोषणा की गई थी और पचास रुपया प्रति प्रोन्नति पश्चात् लाभ का आश्वासन दिया गया था। परन्तु हुआ कुछ भी नहीं। जहां आकस्मिक एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा के 40 दिन पूरे होने पर स्थायीकरण की व्यवस्था है। इनको साल दो साल कार्य करने के पश्चात् भी इस सुविधा से वंचित कर हजारों की छंटनी कर दी गई है। इस संदर्भ में विभागीय एवं गैर विभागीय नियुक्तियों में उम्र सीमा को शिथिल रखते हुए छंटनी से पूर्व स्थायी नियोजन, कार्यरत समेकित वेतन भोगियों को न्यूनतम वेतन एवं अन्य सुविधाएं, छंटनीग्रस्त व्यक्तियों का नियोजन तथा छंटनीकाल से नियोजन तक विशेष भत्ता एवं स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमता और नेत्र ज्योति का ध्यान रखते हुए न्यूनतम कर्म सीमा की समाप्ति की इनकी चार सूत्री मांगें सरकार से हैं। मैं सरकार से इन कर्मचारियों की जायज मांगों को मानकर इनकी समस्या सुलझाने का अनुरोध करता हूं। (इति)

(viii) Need for austerity in Government expenditure.

SHRI KAMAL NATH (Chhindwara): There is great urgency to cut down Government expenditure at every level including ostentatious spending by the public undertakings and our missions abroad. Very few people seem to be aware of the cost of Government of India, which has been rising at geometric progression. Between 1952 and 1978, one fourth of India's net national income was spent on Government. And, of every rupee earned during that period, nearly 17 paise were spent on just paying salary to the Government employees. Even today, every fifth telephone in the country is installed in some Government building and 60 per cent of passenger cars are owned by Government.

The importance of austerity, therefore, cannot be overstated. The public undertakings are the worst offenders in this respect. It is necessary that foreign trips should be curtailed and wasteful expenditure on buildings be stopped. The worst tendency in Government and in Public sector undertakings is to recruit more people than are optimum. To employ people than necessary is not a mark of health but a kind of concealed unemployment or under-employment. Expenses incurred by Trade and Diplomatic Missions abroad also require trimming. There are a number of Tea Board Offices and Tourist Offices abroad doing nothing.

All Government expenses must be 'muscle' and not 'fat'! Trimming of Government expenses at all levels will save about 500 crores. The Government must appoint a Commission with a time-bound programme to recommend ways of cutting down expenses.

14.33 hrs.

MOTION FOR ADJOURNMENT

Deteriorating situation in Punjab arising out of extremists' activities and failure of Government to settle the issues.

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि सभा अब स्थगित हो।"

मान्यवर, अकाली आन्दोलन को प्रारम्भ हुए लगभग एक वर्ष हो रहा है। पंजाब में आज जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनके सम्बन्ध में हमारी पार्टी के नेता माननीय चौधरी चरण सिंह अपने विचार सदन के सामने रखेंगे। मैं अनुरोध करता हूं कि आप उनको यह अवसर प्रदान करें।

श्री चरण सिंह (बागपत) : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष महोदय : मैं एक निवेदन कर लूं—जो-जो नेता इस विवाद में आज भाग ले रहे हैं मैं उनसे इतनी ही प्रार्थना की कि वे समय का अपने हिसाब से ध्यान रखते हुए चलें।

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर (दुर्गापुर) : कितना समय दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : जितना समय बाकी है, सारा आपका है।

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब की स्थिति पर अपने विचार पहले भी प्रकट कर चुका हूं, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा, जितना जरूरी है उतना ही बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा चाहता हूं कि कोई समय निर्धारित कर लें। इस समय 2 बज कर 34 मिनट हुए हैं, क्या सात बजे या आठ बजे तक रखें ?

श्री मनीराम बागड़ी : 9 बजे तक रखें।

अध्यक्ष महोदय : 8 बजे तक रख लेते हैं। आठ बजे मोशन पुट हो जाएगा।

श्री चरण सिंह (बागपत) : अध्यक्ष महोदय, हमारी बदकिस्मती यह है कि रूलिंग पार्टी या शासक दल जो समस्या स्वयं पैदा करता है, उस को दूसरे पर डालने की कोशिश करता है। मसलन, असम की समस्या को ही आप ले लीजिए। जब से देश स्वतंत्र हुआ है, तब से बंगलादेश के लोगों का असम में घुसने का सिलसिला बराबर चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सन् 1961 तक बंगलादेश से दो मिलियन, 20 लाख आदमी असम में घुस चुके थे। मुझे अफसोस है कि माननीय प्रधान मंत्री इस समय यहां नहीं हैं जबकि इतना महत्वपूर्ण यह विषय है। उनको यहां आने का सौजन्य दिखाना चाहिए था। खैर, मुझे इसलिए यह कहने की जरूरत पड़ी क्योंकि जब मेरी उनसे इस सिलसिले में बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने यह कहा था कि असम का मसला तो जनता पार्टी के जमाने में पैदा हुआ और जनता पार्टी ने इसे तब हल क्यों नहीं किया। यह बात जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए उन्होंने कही थी कि जब मैं थोड़े दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर था, तो फिर आपने क्यों नहीं इसको हल किया। अब सन् 1947 की यह समस्या थी और मेरे सामने यह अक्तूबर 1979 में आती है और उसमें सवाल यह था कि कौन सिटीजन है और कौन फोरेनर है। उसके लिए एक छोटा-सा कानून बना था या शासकीय आदेश यह था कि जो आदमी दूसरे को फोरेनर बतलाता है, वह मेजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन फाइल करे और फोरेनर प्रूव करने का भार उस पर होगा। अब इस काम को करने के लिए बहुत से मेजिस्ट्रेट चाहिए थे और बहुत से लोग इस बारे में शिकायत करने वाले चाहिए थे और हमारे पास उस समय इतना समय नहीं था। हमको जनवरी से पहले इलैक्शन करवाने थे और वहां पर 14 पार्लियामेंट की सीटें थीं। उनमें से 2 ऐसी सीटें थीं, जिनमें यह प्रश्न नहीं उठता था। इसलिए हमने 2 में इलैक्शन करवा कर 12 को मुल्तवी करा दिया क्योंकि हमारे पास केवल 2-3 महीने ही डिस्पोजल पर थे लेकिन कहा यह जाता है कि यह मसला जनता पार्टी के जमाने में पैदा हुआ और जब हमारे पास पावर थी और इलैक्शन हुआ था तो इसको मुल्तवी क्यों करा दिया। वाकया यह है, मैं आपके जरिए माननीय होम मिनिस्टर को बतलाना चाहता हूं, इस समस्या से जिन महकमों का सम्बन्ध है मसलन एक्स्टरनल मिनिस्ट्री का जो महकमा है, उससे वे मालूम करवा लें और यह बात उनके आफिशियल रिकार्डस में होगी और वह क्या है। मैं फिर दोहराता हूं कि सन् 1947 से ले कर सन् 1961 तक, 14 साल के अन्दर बंगलादेश से 20 लाख से ज्यादा आदमी असम में आ चुके थे।

इसी तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी बराबर अब कहती फिरती हैं कि डिवीजिव फोर्सेज बढ़ती जा रही है और विरोधी पक्ष जो है, अभी उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग में 3 दिन हुए कहा था, वह बजाए इसके कि मसले के सुलझाने में मदद करे, वह स्थिति को खराब कर रहा है और बढ़ा रहा है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जानबूझकर गलतफहमी पैदा करना प्रधान मंत्री जी को कहां शोभा देता है। माननीय होम मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हुए हैं, वे हमको बाद में बतलाएंगे कि किस तरीके से

अपोजीशन पार्टीज इसको एग्रावेट कर रही हैं और यह प्राब्लम कैसे पैदा हुई और किसने पैदा की और कब पैदा हुई। हमारी बहनजी इसमें बहुत होशियार हैं और हममें से कोई भी इस मामले में उनका मुकाबला नहीं कर सकता कि खुद की जिम्मेवारी को दूसरे पर डाला जाए। बावजूद इसके कि 35 वर्ष इस देश को आजाद हुए हो गए। 66 परसेन्ट आदमी अभी भी इललिटरेट हैं और वे कुछ नहीं जानते हैं। जो मास मीडिया से सुना और प्रधानमंत्री जो एक बात कह रही हैं, वह जरूर सही होगी, ऐसा वे सोचते हैं। तो इस तरह का प्रोपेगेन्डा चलता है।···(**व्यवधान**)··· मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और जब आपका मौका आए, तब आप बोलें। बीच में इस तरह से करने से कोई फायदा नहीं है। आप कहें, तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : आप देश की जनता के हित में बोल रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप शान्ति से बैठिए और आराम से सुनिए। जब आपका मौका आएगा, तब आप अपनी बात कहिए। बीच में टोका-टाकी अच्छी नहीं है।

आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप क्या कर रहे हैं?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री चरण सिंह : मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीया प्रधान मंत्री जी बरावर कह रही हैं कि डिवाईसिव फोर्सिज बढ़ रही हैं और हमें इन डिवाईसिव फोर्सिज का मुकाबला करना है। यह कहने का उनका मंशा यह है कि ये डिवाईसिव फोर्सिज अपोजिशन पार्टीज ने बढ़ाई हैं।

यह उन्होंने कब से कहना शुरू किया? यह उन्होंने तब से कहना शुरू किया जबकि पंजाब के सिलसिले में उन्होंने अपोजिशन पार्टीज के सभी लोगों को बुलाया था। मैंने उस वक्त उनसे खुल कर बातें की थीं। मैंने उनसे कहा था कि इन डिवाईसिव फोर्सेज के पीछे आपकी गल्ती रही है, आपकी गवर्नमेंट की गल्ती रही है, आप और आपकी पार्टी बराबर गवर्नमेंट में रही हैं, सिवाय दो-तीन सालों को छोड़कर। ये डिवाईसिव फोर्सिज किसने बढ़ाई हैं? माननीय जवाहरलाल जी ने यह बराबर कहा कि ये कास्ट, रिलीजन, यानी धर्म और जाति और भाषा भी एक हिन्दुस्तानी को दूसरे हिन्दुस्तानी के नजदीक लाने के बजाए एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। ये कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, लिंगुएइज्म किसने बढ़ाए हैं?

कांस्टीच्युएंट असेम्बली में 30 मई, 1948 को, महात्मा जी के मर्डर के बाद एक रिजोल्युशन पास हुआ था। उसे श्री अनन्तशयनम आयंगर ने जो कि हमारी लोकसभा के इंडीपेंडेंस के बाद स्पीकर रहे हैं, पेश किया था। माननीय जवाहरलाल जी ने, उस समय के प्रधान मंत्री ने उसका बाकायदा समर्थन किया था। मैं आपकी इजाजत से वह रिजोल्यूशन पढ़ कर सुना देता हूं जो कि पास हुआ था—

> "Whereas it is essential for the proper functioning of democracy and the growth of national unity and solidarity that communalism should be eliminated from Indian life, this Assembly is of the opinion that no communal organization which, by its constitution or by exercise of discretionary powers vested in any of the organs, admits or excludes from its membership persons on grounds of religion, race and caste or any of them, should be permitted to engage in any activities other than those essential for the religious, cultural, social and educational needs of the community, and that all steps, legislative and administrative, necessary to prevent such activities should be taken."

इसके बारे में कानून बनना चाहिए था, शासकीय आदेश जारी होने चाहिए थे कि कोई भी

कम्युनल आरगेनाइजेशन, जिसकी मेम्बरशिप एक धर्म के मानने वालों या किसी एक बिरादरी के मेम्बरान तक महदूद हो अपने रिलीजन के लिए, सोशल रिफार्म के लिए, सांस्कृतिक कामों के लिए, अपनी कम्युनिटी की शैक्षणिक उन्नति के लिए तो काम कर सकती है लेकिन उसको पोलिटिकल क्षेत्र में काम करने के लिए रोक लगानी चाहिए, कानूनी रूप से निषिद्ध किया जाना चाहिए था। इस प्रकार के शासकीय आदेश जारी कर के किया जाना चाहिए था। यह रिजोल्युशन कांस्टीच्युएंट असेम्बली द्वारा महात्मा जी के मरने के दो महीने बाद पास किया गया था।

अब मैं आपके जरिए से माननीय होम मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा, मैंने इंदिरा जी से भी पूछा था, उस समय उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, शायद इन दिनों में उन्होंने इसका कोई जवाब ढूंढ़ लिया हो, होम मिनिस्टर उनसे भी पूछ कर बता दें कि इस पर अब तक अमल क्यों नहीं हुआ ? इसमें किसी मजहब विशेष से ताल्लुक नहीं है। न इसमें सिख, ईसाई, या मुसलमान का जिक्र करने की ज़रूरत थी। इसमें एक जनरल ला बनाने की बात थी जो कि नहीं बनाया गया। इसके उलटे साऊथ में जो पार्टी देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थी, उस वक्त हमारे लीडर्स ने देश का बटवारा इसलिए माना था कि इससे देश में शांति हो जाएगी, कम्युनलिज्म कम हो जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी 1947 के पहले जो हवा थी, वह आज तक ठीक नहीं हुई है, उसके बावजूद वह पार्टी जिसके साऊथ में मोहम्मद कोया साहब लीडर थे, वह मुस्लिम कम्युनिटी की पार्टी उनकी लीडरशिप मे बराबर फंक्शन करती रही।

मेरे पास रेफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पार्लियामेंट में कई बार सवाल उठा कि मुस्लिम लीग साउथ में कोलिशन कर रही है, उसको क्यों नहीं रोका। पंडित जी ने जवाब दिया कि यह पहले वाली मुस्लिम लीग नहीं है। फिर मैंने इंदिरा जी से पूछा जो 1959 में प्रेसीडेंट ए० आई०सी०सी० थीं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनती है जबकि मुझे यह मालूम हुआ है कि चंडीगढ़ में ए०आई०सी०सी० की बैठक में यह राय जाहिर की थी कि किसी तरह से कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए। लेकिन हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री और उस वक्त के प्रेसीडेंट आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की राय दूसरी थी और यह कोलिशन गवर्नमेंट बनी। कौन जिम्मेदार है कम्युनलिज्म बढ़ाने के लिए अगर कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है तो ?

सन् 1967 या 68 में रबात कांफ्रेंस में मुस्लिम देशों की कांफ्रेंस में शामिल होने के लिए हमने अपना मिनिस्टर भेजा। पाकिस्तान के नुमाइन्दे ने आपत्ति उठाई कि हिन्दुस्तान मुस्लिम देश नहीं है। आपको क्या हक है यहां आने का ? वहां से निकाले गए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : आपने जब प्राइम मिनिस्टर शिप का दावा किया था और प्रेसीडेंट आफ इंडिया को जो दस्तावेज पेश किया था उसमें आपने मुस्लिम लीग से, मुझसे दस्तखत हासिल किए थे···(**व्यवधान**)···आज आप ऐवान को फैक्ट्स के सिलसिले में गुमराह करने जा रहे हैं। (**व्यवधान**)

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : कांस्टीट्वेंट असेंबली का रेजोल्यूशन उस दिन आपके सामने पड़ा था जब आप प्राइम मिनिस्टर थे। आप ही लागू कर देते।

श्री चरण सिंह : कोलिशन गवर्नमेंट बनी या नहीं बनी ? कांग्रेस के साथ नहीं बननी चाहिए थी।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप प्राइम मिनिस्टर क्यों बने ? हमसे दस्तखत क्यों लिए ? (**व्यवधान**)

मैं उस वक्त बंबई में था। खासतौर पर मुझे बुलाया गया कि मैं दस्तखत करूं ताकि ये प्राइम मिनिस्टर बनें। आज इनकी हिम्मत कैसे हो रही है नेशन को गुमराह करने की। (**व्यवधान**)

شری جی ایم بنات والا : آپ پرائم منسٹر کیوں بنے ؟ ہم سے دستخط کیوں کرائے ؟ (انٹرپشن)

میں اس وقت بمبئی میں تھا۔ خاص طور پر مجھے بلایا گیا کہ میں دستخط کروں تاکہ یہ پردھان منتری بنیں آج ان کی ہمت کیسے ہو رہی ہے نیشن کو گمراہ کرنے کی ... (انٹرپشن)

श्री चरण सिंह : नाराज न हों। नाराज हम भी होना जानते हैं।

श्री बूटा सिंह : चौधरी साहब, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपने कोलिशन किया। (**व्यवधान**)

श्री चरण सिंह : आप क्यों बोल रहे हैं। आप भी उसी लाइन पर चलना चाहते हैं ? (**व्यवधान**)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मुस्लिम लीग देश की गद्दार थी जिसने देश का बंटवारा करवाया।

श्री चरण सिंह : मेरी पार्टी में भी 7 मुस्लिम मेम्बर हैं। सवाल हिन्दू या मुसलमान का नहीं है, सवाल कम्युनलिज्म का है। पार्टीशन कम्युनल बेसिस पर हुआ या नहीं हुआ, टू नेशन थ्यूरी पर हुआ या नहीं हुआ ? (**व्यवधान**)

साम्प्रदायिक पार्टी वह है जो बिरादरी विशेष या धर्म विशेष के आधार पर बनी हो और राजनीति में काम करती हो। अगर आपने कोई वोट श्री राजनारायण के कहने से दे दिए तो शुक्रिया।

(**व्यवधान**)

शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। आपके साथ हमारी कोई कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनी।

कंस्टिट्युएंट असेम्बली में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था वह क्या गलत था ? उसको पेश किया था अयंगार साहब ने और उसको स्पोर्ट किया था पंडित जवाहर लाल नेहरू ने···

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : आर. एस. एस. के बारे में बोलिये।

श्री चरण सिंह : आर. एस. एस. का क्या सवाल है। मुझे जो बोलना है बोलूंगा।—अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो आप में से एक भी नहीं बोल सकेगा। यह क्या तरीका है। क्या यह जरूरी है कि आपके कहे मुताबिक मैं बोलूं ?

श्री मनीराम बागड़ी : इनमें से कोई नहीं बोल सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : जब वक्त आए आप में से भी जो कुछ बोलना चाहे, बोल सकता है। अब उनको बोलने दीजिए।

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिकता के सिलसिले में जो कदम उठाने चाहिए थे नहीं उठाए गए। मैं जानना चाहता हूं कि कंस्टिट्युएंट असेम्बली में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, जो रेजोल्यूशन उसने अपनी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में पास किया था और प्राइम मिनिस्टर ने उसके हक में स्पीच दी थी उस पर अमल क्यों नहीं हुआ ? अगर उसपर अमल किया जाता तो आज देश जिस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, खड़ा नहीं हुआ होता।

जहां तक कास्ट की बात है हिन्दू सोसायटी ढाई हजार कास्ट्स में बंटी हुई है। ऊंच नीच का सवाल भी है। इसी की वजह से वह स्ट्रांग नेशन नहीं बन सकी है। स्ट्रांग कम्युनिटी भी नहीं बन सकती है। यह मुझसे छोटा है क्योंकि इसकी यह कास्ट है, यह जो भावना कास्ट सिस्टम की वजह से पैदा हुई है, उसकी वजह से देश को गुलाम भी होना पड़ा है। जीवित रहना है तो इसको हमें मिटाना होगा। यह डिविसिव फोर्स है इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। इसको मिटाने के लिए हमने

कुछ नहीं किया। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं परसनल बात नहीं कहना चाहता हूं कि मैं किस तरह से इस पर अमल करता हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि 22 मई 1957 को मैंने पंडित जवाहर लाल नेहरू को एक बहुत लम्बा खत लिखा था। कास्ट सिस्टम की वजह से ही हमारे देश का विभाजन भी हुआ और सैंकड़ों बरस हमें गुलामी देखनी पड़ी। कास्ट सिस्टम के लिए कोई लेजिस्लेटिव सैंक्सन नहीं है। हमारी सोसाइटी धीरे-धीरे इसकी वजह से तक्सीम होती गई। महात्मा बुद्ध के जमाने से बराबर कोशिशें होती रही हैं कि कास्ट सिस्टम को मिटाया जाए। लेकिन ये मिटी नहीं। कास्ट कब रेलेवेंट होती है। दोस्ती में, पेशे में, व्यूज में कास्ट रेलेवेंट नहीं होती है। पेशे में, मिलने जुलने में, दोस्ताने में, साथ मिलकर काम करने में कास्ट रेलेवेंट नहीं होती है। बच्चों की मैरेज के वक्त यह रेलेवेंट हो सकती है। यह रेलेवेंट तब होती है, बिरादरी रेलेवेंट तब होती है जब लड़के लड़की की शादी होती है और कहा जाता है कि हम अपनी बिरादरी में करेंगे, लड़की वालों को लड़का और लड़के वालों को लड़की पसन्द है तो वे कह सकते हैं कि हम अपनी कास्ट में करेंगे। मैंने जो लम्बा खत पंडित जो को लिखा था उसमें मैंने मश्विरा दिया था कि आप अंतरजातीय विवाह प्रदेशों में बड़ी नौकरियों के लिए अनिवार्य कर दें। जितनी हमारी सर्विसिस हैं उनमें केवल पांच प्रतिशत गजेटिड आफिसर्स हैं। आल इन्डिया सर्विसिज के उम्मीदवारों के लिए इन्टर लिंग्विस्टिक विवाह लाजिमी कर दें। (**इंटरप्शंस**) जितने हमारे समाज सुधारक हुए हैं सबने जातपात की प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हमारे लड़के लड़कियां स्कूल कालेजों में जब तक पढ़ते हैं वह बिरादरी की भावना से ऊपर होते हैं, वे इन टर्म्ज में नहीं सोचते हैं, उनमें इस तरह का खयाल नहीं होता है।

15.00 hrs

लेकिन जब शादी का वक्त होता है तब बिरादरी प्रासंगिक हो जाती है। तो जातपात हमारी जिन्दगी में रेलीवेंट है विवाह के संबंध में। जब तक वहां कुल्हाड़ा नहीं चलेगा जातपात की प्रथा नहीं मिटेगी। मैंने पंडित जी को एक लंबा खत लिखा लेकिन उससे पंडित जी राजी नहीं हुए। मैं यहां विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने यह युक्ति दी कि विवाह अपनी पसंद का सवाल है और उसको रेगूलेट करने के लिए कानून नहीं बनना चाहिए। मैं पूछता हूं कौन सा देश या कर्म है जहां विवाह को रेगूलेट करने के लिए कानून नहीं बना हुआ है? हमारे यहां हिन्दू कानून में तो पीढ़ियों तक का बन्धन है। अगर देश को मजबूत करना चाहते हैं तो जातपात को समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन नहीं राजी हुए पंडित जी। उलटे हमारे यहां के नेताओं ने अपनी बिरादरियों की सभा में जाना शुरू कर दिया और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंडित जी कश्मीरी पंडितों की कानफ्रेंन्सों में जाते थे। इस बात का मैंने अपनी किताब में तारीख आदि तक का हवाला दे रखा है।

श्री भीकूराम जैन (चांदनी चौक): अध्यक्ष जी, पंजाब का मसला है और अभी तक चौधरी साहब ने पंजाब को रेफर नहीं किया।

MR. SPEAKER : Mr. Jain, why are you getting upset about things unnecessarily ?

SHRI BHIKU RAM JAIN : There is no reference to Punjab.

MR. SPEAKER : The opposition is referring to the divisive forces in the country.

SHRI BHIKU RAM JAIN : We are discussing Punjab.

MR. SPEAKER : It is leading to that. Something will be mentioned about that. I think so. This is related to that. Do not be impatient.

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये जैन साहब को बताना चाहता हूं कि माननीया प्रधान मंत्री बराबर कह रही हैं कि विघटनकारियों···

(व्यवधान)

MR. SPEAKER : It is very bad. It is very improper on the part of hon. Members to interrupt like this. But when others interrupt them, they cry out. What is this ?

श्री चरण सिंह : असम का, पंजाब का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री बराबर कहती हैं कि डिवीजिव फोर्सेज बढ़ रहे हैं और विरोधी दल विघटनकारी शक्तियों को बराबर बढ़ा रही हैं। डिवीजिव फोर्सेज को बढ़ाने के बारे में मैं पंडित जी की बात बता चुका हूं और बता रहा हूं कि इन शक्तियों को रूलिंग पार्टी ने बढ़ाया है। जिम्मेदारी आपकी है, नकल दूसरी पार्टियों ने भी की है। लेकिन रास्ता आपने दिखाया है। दूसरों ने नकल की है।

(व्यवधान)

अगर आप नहीं बोलने देते तो मैं गारन्टी करता हूं कि मेरे दोस्त आपको नहीं बोलने देंगे। मैं बैठ जाता हूं।...

(व्यवधान)

माननीय सेठी साहब बैठे हुए हैं जिनका यह महकमा है, मैं उनसे अपील करता हूं कि वह अपने मेंबरान को रोकें। अगर नहीं रोकते हैं तो मैं तो बैठ जाता है, लेकिन फिर आप भी नहीं बोल सकेंगे। क्या मतलब हुआ आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं ? अपने साथियों को कहिए। क्या यह वाकया नहीं है कि इन्दिरा देवी जी ने अनेक बार यह कहा कि डिवीजिव फोर्सेज सर उठा रहे हैं ? क्या उनका सर उठने के लिए विरोधी पक्ष जिम्मेदार है ? मैं कहना चाहता हूं कि अपोजीशन जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी एक तरह से हर पार्टी की है, लेकिन रूलिंग पार्टी ने यह रास्ता दिखाया है। हमको वोट चाहिए हर कीमत पर चाहे धर्म को अपील करके, चाहे सम्प्रदाय और चाहे बिरादरी को अपील करनी पड़े, चाहे बिरादरी के अन्दर गोत्र को अपील करनी पड़े। तो जिम्मेदारी शासकदल की है और मिसाल दे रहा हूं कि पंडितजी ने भी यह गलतियां की हैं।

उसका नतीजा दूसरों पर क्या हुआ ? स्वभावतः दूसरे लोगों ने नकल की। मैं एक सज्जन का नाम नहीं लेना चाहता, अच्छे आदमी हैं, पड़ोस के एम०पी० हैं, जिन्होंने अपनी बिरादरी की एक कांफ्रेंस में शरकत की। यह भी नहीं कि आल इंडिया कास्ट कांफ्रेंस हो। उन्होंने अपने सूबे के एक जिले की, एक तहसील की अपनी बिरादरी कांफ्रेंस की अध्यक्षता की। आखिर, हम कहां जा रहे हैं, बांटेंगे लोगों को, घृणा फैलायेंगे जो कि सर्विसेज में हो रहा है ? मैं कहना नहीं चाहता कि किस सीमा तक बिरादरीवाद से काम लिया जा रहा है। तो क्या हम इस प्रकार अपने राष्ट्र को मजबूत बनायेंगे ?

(व्यवधान)

बेशक, आप शोर मचाकर मेरे लिए नामुमकिन कर सकते हैं कि मैं न बोलूं, लेकिन आखिर समस्याओं का हल कौन सोचेगा, कौन करेगा ?

अब सवाल भाषा का आता है। कांस्टीटुएंट असेम्बली में पास हुआ कि हिन्दी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे तमिलनाडु के लोगों को उसमें कठिनाई थी, उन्होंने एतराज किया, लेकिन एतराज तो होते ही हैं।

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul) : The whole of South, not only in Tamil Nadu.

श्री चरण सिंह : तमिलनाडु का एतराज था, औरों का नहीं। तमिलनाडु का एतराज तो कुछ समझ में आता है, क्योंकि उनकी भाषा में संस्कृत-निष्ठ शब्द नहीं थे, लेकिन तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में तो 40 से 70 प्रतिशत शब्द सीधे संस्कृत के थे। उसमें इतनी कठिनाई नहीं थी। तमिलनाडु की कठिनाई को हम मानते है लेकिन सवाल यह है कि अगर एक राष्ट्र बनाना है तो एक ही भाषा होगी। आप तमिल को मान लीजिए, जैसे कि मेरे एक मित्र ने कहा, तो फिर तेलुगु को भी मानिए। तो विघटन की तरफ जब

आदमी चलता है, एक टैंडेंसी को एक तरफ मान लेता है तो धीरे-धीरे उस तरफ बढ़ता जाता है। दो ही भाषाएं नहीं, फिर 12 होंगी, उससे ज्यादा होंगी।

दुनिया में एक ही मुल्क है जो बाई-लिंगुअल है और वह कनाडा है। फ्रांसीसी और इंग्लिश भाषा दोनों राष्ट्र भाषाएं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलो दो नहीं तीन होंगी।

श्री चरण सिंह : मैं समझता था कि सभी पढ़े-लिखे लोग बैठे होंगे, शरीफ लोग।

प्रो० मधु दंडवते : नहीं साहब, आप इल्जाम लगा रहे हैं उन पर।

श्री चरण सिंह : माफ कीजिए, लेकिन यह कोई तरीका नहीं हुआ। इस तरह से आप देश की समस्या हल नहीं कर सकते। मेरी राय जाहिर करने से आप मुझे रोक नहीं सकते। अगर आप यह करेंगे तो इस सदन को चलाना ना-मुमकिन हो जाएगा।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि केनेडा एक अपवाद है परन्तु उनकी दोनों भाषाओं की लिपी एक है। मैं फ्रेंच नहीं जानता, इंगलिश थोड़ी सी जानता हूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि फ्रांसीसी भाषा और इंगलिश भाषा की लिपि एक है।

अध्यक्ष महोदय : छोटा कीजिए।

श्री चरण सिंह : मैं छोटा ही करूंगा, मगर इतना वक्त तो उसमें से काट दीजिए जितना मेरे मित्रों ने व्यवधान करके बरबाद किया है।

अध्यक्ष महोदय : वह मैंने काट दिया।

श्री चरण सिंह : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अभी एक डैलीगेशन चीन में गया और वहां सब ने अंग्रेजी बोली। चीनियों ने पूछा कि आपकी कोई राष्ट्र भाषा है या नहीं ? किसी के पास कोई जवाब नहीं था।

मुझे मालूम नहीं कि आपमें से कौन गया था। इतना बड़ा राष्ट्र है, बिना एक भाषा के बन्धन के कैसे शक्तिशाली बनेगा ? नहीं बन सकेगा।

संविधान की धाराओं के खिलाफ एक भाषा सम्बन्धी कानून 1967 में मंजूर होता है कि इंगलिश को एसोसिएटेड लैंगुएज मान लिया जाए। और लिख दिया जाता है कि जो लोग एतराज करते हैं, जब तक वह राजी नहीं होंगे। कोई समय की सीमा इसके लिए रखी गई। आसानी से मसला हल हो सकता था। नहीं हो सकता था तो संस्कृत को राष्ट्र भाषा मान लिया जाता। मैं तो इसके लिए भी तैयार हूं कि आनेवाली सारी पीढ़ियों को जैनरेशन को तमिल सिखा दीजिए अगर तमिल से मसला हल होता है तो। लेकिन डिवीजव फोर्सिज़ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।

इसमें भी गलती हमारे नेतृत्व की रही है। मैंने पहले अर्ज किया था कि 66 में जो आवाज उठी कि हरियाणा और पंजाब की तकसीम होनी चाहिए, उधर एक एडवोकेट थे रोहतक के जो कहते थे कि कांग्रेस की नीति के अनुसार दिल्ली एक प्रदेश बनना चाहिए। कांग्रेस संगठन के अन्दर एक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अलग थी। मैं जब लखनऊ चुनकर गया 1937 में असेम्बली में गया तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मेरा नाम मंजूर किया था। कोई ताल्लुक मेरा लखनऊ से नहीं था। उन वकील साहब ने लिखा कि पंजाब और हरियाणा बहुत छोटी-छोटी स्टेट बन रही हैं।

हरियाणा पंजाब से भी छोटा है और कांग्रेस के लीडर्स का पहले से ही निर्णय है एक दिल्ली प्रदेश बनाने का। यह डिवीजन की बात मेरी जहनियत में नहीं आती। मैंने जो उनको उत्तर भेजा उसकी एक कापी इंदिरा जी को भी भेज दी थी। उसमें मैंने लिखा था कि पंजाब और हरियाणा की तकसीम जिस आधार पर हो रही है आने वाले

वक्त में मैं देखता हूं कि उससे समस्याएं पैदा होंगी। वह खत मेरे पास रखा है लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूं। गलती हुई उस वक्त तकसीम करने में। चलिए, हो गई। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि आनन्दपुर साहब के प्रस्ताव में सिख नेशन का जिक्र है, ऐसा नहीं है, सन 68 में ही, इससे पहले हो चुका था। क्योंकि उसके बाद में तो जब एक रास्ता खुल गया तो खुल गया। और यह कौन सा तरीका है कि हमारे स्वर्गीय संत फतेहसिंह जी ने कहा कि हम जल मरेंगे या आत्मदाह कर लेंगे या अनशन करेंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती ? यह कोई तरीका मसलों को हल करने का नहीं है। इसके सामने अगर आप समर्थन करते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं है।

तकसीम हुई, और फिर मतालबा खालिस्तान का हो गया। 66 में तकसीम होती है और 68 में खालिस्तान की डिमांड होती है। मेरे पास वह रेजोल्युशन रखा है। जो पेपर्स में रिपोर्ट निकली थी, मैं अपने पुराने पेपर्स आजकल देख रहा हूं, उस में वह रिपोर्ट है,पूरा पेज है, उस में नाम भी लिखा है लीडर्स का। तो सन् 68में यह बात उठाई गई। आनन्दपुर साहब में उसके बाद आवाज उठी है। उस में सिख कौम की बात कही गई है और आगे 'कौम'' की परिभाषा की गई है। यह कहा गया है कि उस क्षेत्र में सिख कौम की पोजीशन होगी और जो माननीय तोहरा साहब हैं जो शिरोमणि अकाली दल के प्रेसीडेंट हैं उन्होंने आनन्दपुर साहब रेजोल्यूशन की ताईद में जो स्पीच दी थी जो कल के टाईम्स आफ इंडिया में निकली है जिसमें चार लेखों की एक सेरीज निकली है जो आज काललूड हुई है उस स्पीच को आप पढ़ लीजिए। उसमें कहा है कि भारत वर्ष एक फैडरल कौम होगा और हर यूनिट को दूसरे देश से सन्धि करने का, ट्रीटी करने का हक होगा। कहीं दुनिया में ऐसा फेडरेशन नहीं है। बस, यह नहीं कहा है कि 25 नेशन होगी बजाय एक नेशन के। इतनी गर्म और तर्कहीन स्पीच है, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि यहां तोहरा साहब नहीं हैं, लेकिन मैं उनके मुंह पर भी कह सकता हूं, इतनी वाइल्ड और गैर-जिम्मेदारी की स्पीच है कि कोई लीडर दे ही नहीं सकता। यह होता गया, होता चला गया।

अब सन् 70 में एक कमीशन बैठा, शाह कमीशन पंजाब और हरियाणा के मामले को तय करने के लिए। उसकी एक रिपोर्ट आती है, वह नहीं मानी जाती। तो फिर कमीशन क्यों बैठाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज थे। सारे ही जज हमारे अच्छे होते हैं, तभी जाकर वह सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। लेकिन शाह साहब एक बड़े यशस्वी और योग्यता के व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने जो फैसला किया उस फैसले को नहीं माना गया—क्यों—क्योंकि हमारे अकाली दल के दोस्तों का, सिखों का दबाव था। क्योंकि उनका एक शक्तिशाली संगठन था। यह अकाली दल शुरू में एक गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के रूप में आया था।

खरड़ तहसील जो हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र थी, अगर भाषा के आधार पर तकसीम हुई थी तो क्यों नहीं हरियाणे को दे दिया गया ? चण्डीगढ़ को भी उन्होंने कहा था कि हरियाणे को मिलना चाहिए। फाजिल्का और अबोहर की बात छोड़ दीजिए। वह खरड़ तहसील और आसपास के जो और गांव हैं वह सब पंजाब को दे दिए गए उसी वक्त। और चण्डीगढ़ के लिए यह तय हुआ कि कुछ दिनों के बाद हरियाणे वाले अपनी राजधानी बनाएंगे, गवर्नमेंट आफ इंडिया उसके लिए रुपया देगी, उसके बाद क्या होगा कि वह पंजाब को दे दिया जाएगा। क्यों ? कमीशन फिर क्यों बैठाया ?

आप जो निर्णय लेंगे, या हम लोग यहां जो निर्णय करेंगे, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जो निर्णय लेंगे उसमें हमारे सामने बजाय सच्चाई या जनहित, राजनीति आ जाएगी। आम तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना कम हो उतना अच्छा है। लेकिन कमीशन में एक जज ने अपनी ईमानदारी, अकल और काबलियत के साथ

सब बातों की देखकर एक फैसला दे दिया। उस फैसले को आप नहीं मानते हैं तो कमीशन बैठाने का फायदा क्या है? आज चंडीगढ़ के लिए यह डिमांड है कि चंडीगढ़ सारा पंजाब को जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? अगर मैं यह कहूं कि शाह कमीशन की रिपोर्ट पर अमल होना चाहिए और चंडीगढ़ हरियाणे के पास रहना चाहिए और खरड़ तहसील भी हरियाणे को दी जानी चाहिए तो मैं जानना चाहूंगा कि कौन सी गलती करता हूं या हरियाणा वाले यह डिमांड करें तो कौन सी गलती करेंगे?

शाह कमीशन उनके रिश्तेदार नहीं थे। शाह गुजरात के रहने वाले थे। वे जज थे, वह एक निष्पक्ष व्यक्ति थे। उनका किसी के साथ कोई मोह नहीं था। फिर उनकी बात क्यों नहीं मानी गई? उसको तो माना नहीं और एक समस्या खुद पैदा कर ली और अब दोष दे रहे हैं विरोधी पक्ष को। किस तरह से हमको दोष दे रहे हैं? जिस तरह से खुद मामला उठाया है उसको अब हल नहीं करना चाहते हैं। मसलन भिंडरावाले के लिए हमने लिखकर भी भेजा, पिछली बार भी जिक्र किया था और बहनजी के मुंह पर भी मैंने कह दिया था कि भिंडरावाले के खिलाफ एक वारन्ट है और वे गुरुद्वारे में चले जाते हैं। पुलिस वाले जाकर उनसे हाथ जोड़कर पूछते हैं कि हुजूर कब पेश होंगे? ऐसे चलेगी कोई गवर्नमेन्ट? वे अपनी पसन्द की जगह पर और अपनी पसन्द के समय पर एक जगह, शायद मेहता चौक में प्रवेश हो गए जहां पर दो लाख आदमी इकट्ठा होते हैं। भिंडरावाले बड़े अच्छे आदमी होंगे, मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए, कभी बात नहीं की लेकिन उस रोज उनका कद जो था वह दो फीट और ऊंचा हो गया। उन पर वारन्ट था, सही या गलत, वे अपने को जिस तरह से पेश करते हैं उसको गवर्नमेन्ट भी मान लेती है। मैंने इन्दिराजी से कहा क्या यह आपकी बिना रजामन्दी हो गया? कुछ दिन पहले भिन्डरा-वाले कांग्रेस वर्कर थे, पिछले एलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस का काम किया था। वे यहां दिल्ली में भी आते हैं और बम्बई में भी घूमे लाइसेंस्ड या अनाइसेंस्ड हथियार लेकर। यहां पर दिल्लीं में अनलाइसेंस्ड आर्म लेकर आते हैं और एक से ज्यादा बसें लेकर आते हैं। एक बस तो आई ही थी, शायद दो-तीन भी हों। चीफ मिनिस्टर, श्री दरबारा सिंह श्री जैल सिंह को लिखते हैं जिसकी कापी शायद प्राइम मिनिस्टर को भी भेजी होगी कि दे अनलाइसेंस्ड आर्म लेकर दिल्ली आ रहे हैं लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। मैंने इन्दिरा जी से कहा कि यह नामुमकिन है कि आपको इस बात का पता न हो जिसके इतने पोलिटिकल इंप्लीकेशन्स हो सकते हैं। यह सब आपकी आंखों के नीचे हो रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, देहली की सैर करके लौट जाते हैं। यह कैसी शान्ति-व्यवस्था है? इसमें हमारी जिम्मेदारी कहां आती है?

अब रही बात गुरुद्वारों की कि वहां से कोई गिरफ्तार नहीं किया जायेगा? क्यों नहीं किया जायेगा? क्या दुनिया में कोई भी ऐसी मिसाल है? गुरुद्वारों की पवित्रता तो तब नष्ट होती है जबकि एक अपराधी को वहां पर आश्रय दिया जाता है न कि जब पुलिस जोकि आपकी बनाई हुई है वह वहां पर किसी को गिरफ्तार करने के लिए जायेगी। लेकिन इसको भी इन्दिराजी मान लेती हैं कि गुरुद्वारा अपवित्र हो जायेगा? क्यों? मैं सेठीजी से जानना चाहूंगा और वे अगर अभी जवाब दे दें तो मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन मुझे मालूम है कि इसमें उनका कुसूर नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि अगर गुरुद्वारे में छिपे हुए लोग सात दिन में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो हम पुलिस को लेकर वहां जायेंगे। अगले रोज लोंगोवाल बयान देते हैं कि लाखों सिक्ख इकट्ठे हो जायेंगे और गुरुद्वारों में कोई पुलिस घुस नहीं पायेगी। फिर भिंडरावाले सिख सैनिकों से अपील करते हैं, सिख अफसरों और जवानों से कि आपको हमारी मदद करनी चाहिए, अपनी कौम की मदद करनी चाहिए। अकालियों की ओर से प्रोटेस्ट किया जाता है और उसके बाद

सरकार अपने आदेश को स्वयं रद्द कर देती है। क्या दुनिया में कोई गवर्नमेन्ट नाम की कोई भी संस्था है जो शान्ति-व्यवस्था के मामले में एक फैसला करे और दूसरी पार्टी धमकी दे तो वह पीछे हट जाए? दुनिया में ऐसी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। आप मुझे माफ करेंगे, आप देश का शासन चलाने की योग्यता नहीं रखते। अगले रोज जब मैंने लोंगोवाल का बयान पढ़ा तो उस वक्त मैं आपको फोन करने वाला था लेकिन फिर मैंने सोचा फोन करना मुनासिब नहीं होगा। मैं खुद आपके पास आने वाला था लेकिन वह बात जाहिर होती, खुफिया नहीं रहती और दूसरे यह कि मुझे क्या हक है आपको मश्विरा देने का? क्या आल्टिमेटम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तभी वह आल्टिमेटम होता है? इन्दिराजी कहती हैं वह आल्टिमेटम नहीं था। क्यों नहीं था अल्टिमेटम? जब एक हफ्ते का समय निश्चित किया जाता है कि इसके अन्दर अमुक नहीं किया जायेगा तो हम स्वयं करेंगे। लफ्ज अल्टिमेटम तो जब दो देशों में युद्ध होता है तभी इस्तेमाल किया जाता है और यह भी हमेशा नहीं।

अल्टीमेटम का आशय है कि हमारी जमीन खाली कर दो, वरना दवाव से हम ले लेंगे। मैं यह नहीं मानता हूं कि यह आर्डर आपने कैंसिल किया है। बहैसियत मैम्बर कैबिनेट के आप खामोश रहने की कृपा कीजिएगा, लेकिन वह आर्डर मैंने बहन जी से कहा था कि उन्होंने कैंसिल किया है। एक दूसरा अल्टीमेटम अकालियों ने दे दिया कि 17 तारीख तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तो हम रेल रोकेंगे और सड़कें भी रोकेंगे। आपने उनका अल्टीमेटम मान लिया और कहा कि हम उस रोज मोटर चलने नहीं देंगे और रेल भी नहीं चलने देंगे। जब आप अल्टीमेटम देते हैं तो उनके लीडर्स आपको धमकी देते हैं और आप दुम दबाकर भाग जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट है या मजाक है?

जहां तक सवाल स्वर्ण मन्दिर अथवा गोल्डन टैम्पिल की सीमा का है, वह बहुत बढ़ गई है। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, गुरुनानक निवास पहले उस सीमा में नहीं था। यह बात मान भी ली जाए, जोकि उचित नहीं है, कि मन्दिर में, गुरुद्वारों में और गिरजाघर में मुल-जिमों को पकड़ने के लिए भी पुलिस नहीं आएगी तो दोनों के आदमी चले जाएं, पुलिस के आदमी हों और आपके भी आदमी हों, लेकिन इसके लिए भी अकाली दल तैयार नहीं है। श्री बलवन्त सिंह सन्धु जो खालिस्तान कागज पर बना हुआ है, उसके प्रैजिडेंट हैं, वह वहां से गायब हो गये। कहने का मतलब यह है कि चाहे गुरुद्वारे की बात हो या पुलिस की बात हो, साफ जाहिर है कि आप इस चीज को जिन्दा रखना चाहते हैं। एक बयान मैंने पहले भी दिया था, जब हिन्दुओं के साथ अन्याय हो रहा था, जबरदस्ती उनको मुसलमान बनाया जा रहा था या और ज्यादती की जा रही थी, उस वक्त काश्मीर से हिन्दू आए थे गुरुतेग बहादुर के पास कि आप हमारी मदद कीजिए। हमारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उनकी शाहदत की दुनिया में बे-मिसाल है। उस जमाने में हर हिन्दू परिवार यह अपना फर्ज समझता था और अपने जवान बेटे को कहता था कि जाओ गुरु के शिष्य बन जाओ। आज वह कहते हैं कि हमारा मजहब दूसरा है। किस तरह से आज उनका मजहब दूसरा है। गुरुग्रन्थ में कहीं यह लव्ज आया है कि हम हिन्दू नहीं हैं। गुरुग्रन्थ में कबीर जैसे बहुत से सन्तों की वाणियां हैं, श्री रामचन्द्र और श्रीकृष्ण के नामों का अनेक बार जिक्र आया है। गुरुगोविन्द सिंह जी ने यह कहीं नहीं कहा है कि हम हिन्दू नहीं हैं। दुर्गा भवानी की स्तुति में उन्होंने बहुत सी रचनायें की हैं, जिनको हम लोग गाया करते थे। अपने राजनैतिक हित की वजह से मैंने कोई बात नहीं की। आज कहते हैं कि नहीं स्वार्थ नहीं है। मैंने यह गुस्ताखी की है कि हिन्दू और सिख दोनों की हड्डी और मांस एक हो। हम हिन्दू और सिख एक हैं। यह करेंगे, वह करेंगे, अब करें जो कुछ करना है। समस्या यह है कि यह समस्या कौन हल करेगा।

अध्यक्ष महोदय : वाइंड-अप कीजिए ।

श्री चरण सिंह : मैं जानता हूं कि मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया है । दस मिनिट जो इन्होंने खराब किए हैं, वह घटा दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने गिन लिए हैं, मैं गिन कर बैठा हूं । जल्दी कीजिए ।

श्री चरण सिंह : मैं अर्ज यह कर रहा था—

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया (अमृतसर) : बनियों वाली बात कर दी ।

श्री चरण सिंह : बनियों वाली बात नहीं । जाटों को बनिए छोटे समझते हैं । ये सब सिख हो गए हैं और तुम्हारी जान को आ गए हैं ।

(व्यवधान)

मैंने अपनी किताब में 1891 की सैंसस रिपोर्ट का हवाला दिया है । सन् 1891 में पंजाब में 40 परसेंट मुसलमान थे और 1931 में 40 साल के बाद मुसलमान भाइयों की तादाद 52 परसेंट हो गई । इसलिए पाकिस्तान बनता है । सैन्सस कमिश्नर ने 1931 में सवाल उठाया था कि मुसलमान 40 से 52 प्रतिशत कैसे हो गए, हिन्दू 44 से 30 परसेंट कैसे रह गये और सिख 8 से 14 परसेंट कैसे हो गये ? खुद कहता है कि ब्राह्मण, राजपूत और खत्री जो खेती करने वाली बिरादरियां थीं, उनको अपने से छोटा या नीचा समझते थे ।

उदाहरणार्ण, जाट और सैनी को और जो अछूत माने जाते थे, उदाहरणार्थ, चमार और चूड़ों को, उन सब उनको नीच समझते थे, इसलिए वे सारे सिख और मुसलमान हो गये । इसलिये फर्क पड़ता गया और इस मुल्क का एक दिन बंटवारा हुआ, लेकिन हिन्दू फिर भी कोई सबक नहीं सीख सका । मेरी पीढ़ी के जितने लोग थे वे महाराणा प्रताप और शिवाजी पर गर्व करते थे, गुरु गोविन्द सिंह पर गर्व करते थे । लेकिन आज क्या हो रहा है, हर चीज को बिरादरी की दृष्टि से देखा जाता है । मेरे सम्बन्ध में जो टिप्पणी होती हैं उनमें भी बिरादरी का जिक्र आता है, जबकि मेरे लिए वह अर्थहीन है और उसका कोई जवाब भी मेरे पास नहीं है क्योंकि हिन्दू होने के नाते किसी न किसी बिरादरी में पैदा होना था, इसलिए मैं भी एक बिरादरी में पैदा हुआ । इसका कोई इलाज नहीं है । विन्सेन्ट स्मिथ ने लिखा है कि—

Punjab is the home of Jats.

अपने विद्यार्थी जीवन में जब मैंने यह शब्द पढ़े तो मेरी समझ में नहीं आये । बाद में मालूम हुआ कि पंजाब में जाट सबसे बड़ी बिरादरी थी और जाटों में से ही अधिकतर सिख बने थे । मेरे भाई बूटा सिंह जी, मुझे मालूम नहीं है, वह कौन से सिख हैं, जाट सिख हैं या कोई और सिख हैं । शायद स्पैरो साहब भी जाट सिख होंगे । कहने का मतलब यह है कि आज भी 50 से 60 परसेन्ट सिख जाट हैं और वे सिख क्यों हुए, मजहब में कोई फर्क नहीं है, वह अटल जी की मेहरबानी थी···

(व्यवधान)

अब भुगतो इसको ।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह मसला हमारी गलती से, हमारे पुरखों की गलती से पैदा हुआ है । हमारा समाज सबसे बदतर है, दुनिया में कहीं भी सोशल सिस्टम इतना खराब नहीं है । 1941 में मेरे एक साथी थे, जो मुजफ्फरनगर के थे और मेरठ जेल में हमारे साथ कैद थे, हम दोनों एक ही बैरक में थे । उनके पास एक किताब थी—"एक्सपैन्सन आफ इंग्लैंड ।" यह सर जेम्स सीली की लिखी हुई थी । उसमें एक अध्याय में उसने कहा था—1883 में उसने कैम्ब्रिज में व्याख्यान दिया जिसमें वह कहता है—हाऊ वी कान्कर्ड इण्डिया । अर्थात हमने हिन्दुस्तान को कैसे पराजित किया । उसमें उसने यह कहा है—हम जिस वक्त हिन्दुस्तान की विजय कर रहे थे, उस

वक्त हम कैनाडा में हार रहे थे, अमरीका में हार रहे थे। उस वक्त सिर्फ 1 लाख 20 हजार थल सेना हमारे पास थी। उस वक्त जो लड़ाई हो रही थी उसमें हमने यूरोपियन महाद्वीप में उसमें हमने अपने मित्रों को सेना की मदद नहीं दी, क्योंकि हमारे पास कुल 1 लाख 20 हजार फौज थी, केवल नौ सेना की सहायता दी। वह कहता है—क्या वजह है कि हमने इतना बड़ा देश जैसे भारतवर्ष जिसका इतना बड़ा क्षेत्रफल, इतनी प्राचीन संस्कृति, के देश को, इतनी बड़ी आबादी के देश को आसानी से जीत लिया? 1773 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पास कुल 54 हजार फौज थी, जिसमें 9 हजार अंग्रेज थे और 45 हजार हिन्दुस्तानी थे। 1808 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पास 1 लाख 60 हजार सैनिकों की फौज थी जिसमें 25 हजार अंग्रेज थे और पांच गुना से ज्यादा हिन्दुस्तानी सैनिक थे, यानी 1 लाख 35 हजार हिन्दुस्तानी थे। 1857 में दो लाख 80 हजार की फौज थी जिसमें केवल 45 हजार अंग्रेज थे और 2 लाख 35 हजार हिन्दुस्तानी थे। 84 परसेन्ट फौजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी की फौज में हिन्दुस्तानी थे जो उन विदेशियों की तरफ से अपने भाइयों से लड़े। उस वक्त जो लड़ाई हुई अपने भाइयों की फौज अपने भाइयों से लड़ी। हिन्दुस्तानियों ने हिन्दुस्तानियों से लड़कर इस मुल्क को गुलाम बनाया।

आपकी इजाजत हो तो एक बात बूटासिंह जी से कहता हूं। वह कहते हैं—हम बड़े बहादुर हैं।

मैं तसलीम किये लेता हूं लेकिन अगर हिस्ट्री की दो-चार बातें बतला दूं तो शायद दूसरे आदमियों की राय बदलने लगे। 1852 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी पंजाब को जीत लेती है। महाराजा रणजीत सिंह के बाद जो हमारी संस्कृति है, वह सामने आई—और भाई-भाई आपस में लड़े। 1847 में लड़ाई शुरु हुई और 1852 में उसका फैसला हुआ। अब 1857 में अंग्रेज कम्पनी का हिन्दुस्तानी सेना विद्रोह करती है तो मैं ऐसा समझता हूं कि अगर उस वक्त सिख सेनानी उसकी मदद करते, तो देश शायद उसी वक्त आजाद हो जाता। लेकिन हमारे पुरखे सिख सिपाही इलाहाबाद में जाकर अंग्रेजों की मदद करते हैं अपने भाइयों के खिलाफ। मैं इसके लिए सिखों को दोष नहीं दे रहा हूं क्योंकि अंग्रेजों की फौज में 84 प्रतिशत चले आ रहे हिन्दुस्तानी थे और उनमें सिख भी शामिल थे। लिहाजा यह जो धारणा है कि हमारे सिख भाइयों में कोई विशेष बहादुरी है इनमें विशेष ब्रेवरी है और वह कोई देश के विशेष रक्षक रहे हैं, यह गलत है और मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह एक मुगालता है और इधर कुछ राजनैतिक नेतागण सिख भाईयों को प्रसन्न करने के लिए इस तरह के भाषण का प्रयोग करते हैं।

the bravest people etc. If they are defenders of the country, we are also defenders of the country. The other people also are as brave as Buta Singhji and Sparraw Saheb.

इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं, अगर वे उनकी अपनी कठिनाइयां हैं, उनकी अपनी मजबूरियां है यह मैं समझता हूं, कि वे इस मसले को जल्दी हल करें लेकिन इसके साथ ही साथ मैं सदन के सब सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हमको तो यह लग रहा है कि हमारी बहन जी इसको जारी रखेंगी, उस समय तक जब तक कि अगला इलेक्शन न हो जाए क्योंकि उनका मंशा राजकुमार को गद्दी पर बैठाने का है। केवल यह चीज इसमें आ जाती है (**व्यवधान**) अब ऐसा जमाना आ गया है कि यह काम होने वाला नहीं हैं और वंश-विशेष का राज, डाइनेस्टी रूल चलने वाला नहीं है।

···(**व्यवधान**)···

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस मसले को देश के इन्ट्रैस्ट को देखकर हल किया जाएगा

और देश के इन्ट्रेस्ट को अपने इन्ट्रेस्ट से ऊपर रखा जाएगा और डाइनेस्टी रूल वाली बात नहीं होने वाली है।···(**व्यवधान**)···

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद): चौधरी साहब का भाषण खत्म हो गया है लेकिन मैं चौधरी साहब से यह कहना चाहता हूं कि आप तो बड़े आदमी हैं, आप ऐसी छोटी बातें क्यों करते हैं।

MR. SPEAKER : Mr. Bhatia.

SHRI BUTA SINGH : Since Choudhuri Charan Singh mentioned me by name, I would like to clarify a few points on the history which he had traversed.

SHRI R.L. BHATIA (Amritsar): I would reply to that. Don't worry.

श्री चरण सिंह : मैं आपके घर आ जाऊंगा, तब बतला दीजिए।···(**व्यवधान**)···

श्री कमालुद्दीन अहमद (बारंगल) : चौधरी साहब की बातें सुनने के बाद, मैं उनको एक चीज सुनाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बाद में सुना दीजिए।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैं चौधरी साहब को सुनाना चाहता हूं :

कमर तसवीह पढ़ते आ रहे हैं, सुबे मयखाना
कोई देखे तो समझे ये बड़े अल्लाह वाले हैं।

इनकी बुरी स्पीच को इक्सपंज कर दिया जाए।···(**व्यवधान**)···

SHRI G.M. BANATWALLA (Ponnani) : In the interest of the integrity of the country, his speech should be expunged.

SHRI BUTA SINGH : I would very humbly request Choudhuri Charan Singh himelf to think a hundred times over what he has said about the Sikh community ; if he thinks fit, he may reconsider it and come to you with corrections.

SHRI G.M. BANATWALLA : Better expunge it in the interest of the integrity of the country.

···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है···(**व्यवधान**)···आप आपस में मत बोलिए। मैं यह कह रहा था कि कोई ऐसा शब्द स्पीच में नहीं है जो कि किसी जाति के लिए कहा गया हो।···(**व्यवधान**)···

आपस में मत बोलिए।

Nothing of what they say is to be recorded.

मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई बात जाति विशेष या सम्प्रदाय विशेष के खिलाफ नहीं बोली गई है। मेरे ख्याल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने तो यह कहा है कि हम एक हैं, हमारा रिश्ता एक है, हमारा खून एक है। अगर और कोई बात होगी तो वह देख ली जाएगी। श्री भाटिया।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : स्पीकर साहब, पेश्तर इसके कि मैं चौधरी साहब की बातों का जवाब दूं, मैं एक दरख्वास्त इस रूवान के मेम्बरों से करना चाहता हूं। वह यह है कि पंजाब का मसला एक बड़ा गंभीर मसला है। इसके हल के लिए पंजाब के लोग आपकी तरफ ध्यान लगाये बैठे हैं कि यह जो देश का सबसे बड़ा फोरम है इसमें इस बात का जिक्र होगा और इस पर बहस होगी और यहां इसके लिए सुझाव आयेंगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त देश के लीडरों से यह है—चाहे इधर के लीडर बैठे हों, चाहे उधर बैठे हों—कि इस मसले को पोलिटिकलाइज्ड न करके, इस मसले को हल करने की तरफ ले जाएं।

मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका कोई हल निकालें ताकि पंजाब के लोग यह महसूस करें कि वाकई देश के लीडर पंजाब के मसले को सही मायनों में हल करना चाहते हैं।

चौधरी साहब ने बहुत सी बातें कहीं। 1948 से लेकर, भविष्य में गद्दी पर कौन बैठेगा उस तक का जिक्र किया लेकिन काम की बातें उन्होंने नहीं कही। बल्कि दो बातें उन्होंने ऐसी कहीं जिनका जवाब देना जरूरी है। एक तो उन्होंने भिण्डरावाले के रोल और कांग्रेस के कनेक्शन का जिक्र किया। दूसरे उन्होंने यह कहा कि इस सारी बात की जिम्मेदारी सरकार पर आती है। तीसरी बात उन्होंने 1857 में सिख फौजों के अंग्रेजी फौजों की मदद करने की कही। उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा।

जहां तक सरकार के रोल का ताल्लुक है उसका तो जवाब मैं बाद में दूंगा आया कि इसकी सरकार पर जिम्मेदारी पड़ती है या नहीं। जहां तक भिण्डरावाले का ताल्लुक है, उसके बारे में मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि वह एक फण्डामेंटलिस्ट है और अपने मजहब पर अमल करना चाहता है, सिखिज्म का प्रचार करना चाहता है। इसलिए वह निरंकारियों के खिलाफ है क्योंकि निरंकारियों ने अपने ग्रंथ में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिनसे कि सिख इख्तिलाफ करते हैं। दूसरे निरंकारी अपने गुरु को अवतार समझते हैं। सिख इसका खण्डन करते हैं। उन्होंने बहुत बार उनको समझाया और उन दोनों में आपस में झगड़े भी हुए।

निरंकारियों और इन लोगों के बीच में पहला झगड़ा 1970 में हुआ जबकि पंजाब में अकालियों का शासन था। दूसरी बार 1978 में झगड़ा हुआ। उस वक्त भी पंजाब में अकालियों की हुकूमत थी। जब अकालियों की सरकार पंजाब में थी तो उस वक्त भिण्डरावालां की उन्होंने कोई मदद नहीं की जिस पर भिण्डरावालां की अकालियों से नाराजगी थी कि उनकी सरकार के होते हुए भी निरंकारियों से उनका झगड़ा होता है और सरकार उनकी कोई मदद नहीं करती है। इसलिए भिण्डरावालां ने अकालियों से नाराज होकर 1980 के इलेक्शन में अकालियों के खिलाफ अपने केन्डीडेट खड़े किए ताकि वह इस बात का उनसे बदला ले सके कि वे उसकी मदद नहीं करते हैं। बस यही बात है जिससे कि आपको यह ख्याल पैदा हो जाता है कि चूंकि भिण्डरावालां ने 1980 में अकालियों की मुखाल्फत की थी और उसका फायदा कांग्रेसियों को पहुंचा था तो इसलिए वह कांग्रेस के साथ कनेक्शन रखता है। (व्यवधान) कांग्रेस को उससे इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा था, डायरेक्टली कांग्रेस का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। न यह पहले था न आज है। मैं यह बात साफ कह देना चाहता हूं कि चूंकि वह उस वक्त अकालियों के खिलाफ था इसलिए यह बात की जाती है। आज वह अकालियों के साथ है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब के मसले को बहुत से लोग सही नहीं समझते हैं। बहस करते हैं। अखबारों में बढ़-चढ़ कर बातें निकलती हैं। मैं उनको जरा साफ करना चाहता हूं।

पंजाब का मसला यह है कि अकालियों ने यह मांग रखी कि हमको पंजाबी सूबा मिलना चाहिए। 1966 में उनको लिंग्विस्टिक प्राविंस मिल गया। 1967 में पहली बार यह पार्टी पावर में आई। फिर 1969 में और 1977 में पावर में आई, लेकिन तीनों बार जब वह पावर में आई तो उसने ऐसी पालिसी अख्तियार की कि लोग उनसे हटना शुरू हो गए। मैं बताना चाहता हूं कि अकाली पार्टी कम्युनल है और बड़े जमींदारों को रिप्रजेंट करती है। न तो शहरी लोगों और न हरिजनों से जुड़ी है। सिर्फ जाटों से जुड़ी है।

श्री मनीराम बागड़ी : जाटों को क्यों बदनाम कर रहे हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मेरा मतलब

बड़े जमींदारों से है। मैं बड़े जमींदार कह देता हूं। कम्युनल होने की वजह से लोग हटते गए। वाजपेयी जी ने 1967 में, 1969 और 1977 में उनको गवर्नमेंट बनाने में मदद की थी। इनकी वजह से ही वे लोग पावर में आए थे। कभी इन्होंने उनको छोड़ दिया और कभी उनकी मदद की। उसके बाद सूरतेहाल यह हुई कि उन्होंने यह समझ लिया कि एक एरिया हमको मिल गया है जहां सदा हम पावर में आएंगे। जब वे पावर में नहीं आए तो फ्रस्टेशन हुआ। 1980 में 117 विधानसभा सीटों में केवल 37 सीटें और पार्लियामेंट की 13 सीटों में से केवल एक सीट उनको मिली। इससे फ्रस्टेशन हुआ कि हमने एक एरिया कार्वआउट किया और वहां भी पावर में नहीं आ सके। दूसरी बात यह हुई कि 1971 की सेंसस में सिक्ख 58 परसेंट थे जो 1981 में 52 परसेंट रह गए। इसका कारण यह है कि पंजाबी मोबाइल हैं। ये लोग बाहर काम के लिए जाते रहे और पंजाबियों की तादाद कम होती गई। जहां तक हिन्दुओं का ताल्लुक है तो पंजाबी लेबर कम होने की वजह से यू. पी. और बिहार से लेबर आती गई। इस तरह से हिन्दुओं की संख्या बढ़ी और सिक्खों की कम हो गई। क्योंकि सिक्ख बाहर जाते रहे। अब इसके साथ एक और प्राब्लम आ गई कि पंजाब में सी. पी. आई., सी. पी. एम और बी. जे. पी. ने उनका साथ दिया। इस वजह से भी लोग उनसे अलग हट गए। तो जहां फ्रस्टेशन और आइसोलेशन आ गया तो एक्स्ट्रीमिज्म पैदा हो गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक्सट्रीमिज्म का तरीका अख्तियार करके ताकत और बल के जरिए ये पावर में आना चाहते हैं। वे 1967 में, 1969 में और 1977 में पावर में रहे, उस वक्त कभी भी इन्होंने रावी-व्यास का जिक्र नहीं किया।

15.43 hrs.

[DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI *in the Chair*]

कभी चण्डीगढ़ का जिक्र नहीं किया। कभी पंजाबी स्पीकिंग एरियाज का जिक्र नहीं किया और न कोई और डिमांड रखी। लेकिन जब-जब वे पावर में नहीं रहे तब तक ये सवालात उठाए गए।

अब सवाल यह है कि ये जो मांगें हैं ये दो तरह की हैं। एक तो रेलिजियस और दूसरी पोलीटिकल। जहां तक रेलिजियस मांगों का ताल्लुक है वे केवल अकाली पार्टी की डिमांड्स हैं और बाकी हम सब पंजाबियों की सम्मिलित हैं। हम समझते हैं कि उनका हल निकलना चाहिए। चार जो रिलिजस डिमांड्ज थीं उनको लेकर सवाल यह पैदा हुआ कि ये सारी इकट्ठी मानी जाएं या अलग-अलग। तब फैसला हुआ कि पैकेज डील हो ताकि बार बार डिमांड्ज को बढ़ाते न जाएं, पलटते न जाएं। इस वास्ते पैकेज डील होना चाहिये। पंजाब के एमपीज ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर साहिबा से कहा कि आपको इनकी रिलिजस डिमांड्ज फौरन मान लेनी चाहिये। वे मान ली गई। अब इसका क्या रिएक्शन होता है? जब हमने उनकी रिलिजस डिमांड्ज मान लीं तो उनको खुश होना चाहिये था, अगर अकाली डिमाड्ज पर सिरीयस होते तो उनको खुश होना चाहिये था लेकिन लोंगवाल साहब ने गोल्डन टेम्पल में स्पीच दी जिसमें उन्होंने यह कहा :

It is a big fraud.

यह उनका रिएक्शन था। मतलब साफ है। इन डिमांड्ज के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। वह तो पावर चाहते हैं। डिमांड्ज मान भी लेंगे तो भी पावर वे मांगते रहेंगे।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Why don't you implement the demands ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : हम तैयार हैं। रेडियो वाले ही हमने भेजे। बात एक घंटे की तय हुई। अब वे कहते हैं कि तीन घंटे चाहिये। कल को मुस्लिम लीग के भाई बैठे हैं, ये भी कह सकते हैं कि हम भी नमाज पढ़ते हैं, हमको भी तीन चार घंटे दीजिये, हरिजन भाई भी हैं और अगर इस तरह से बढ़ाते चले गए तो रेडियो तो सारा

दिन यही काम करता रहेगा। दूसरी बात पैमेंट की भी है। लेकिन वे पैमेंट नहीं दे रहे हैं।

चौधरी साहब ने कहा कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इस मामले में। यह ठीक बात है। हमने उनकी चार रिलिजस मांगें मान ली हैं। इसके बाद फिर भी मीटिंगे हुई हैं, दूसरी बातों को भी थ्रेश आउट किया गया है। जहां तक इंटर स्टेट रिलेशंज का ताल्लुक है, सरकारिया कमिशन बिठाने की घोषणा कर दी गई है। जहां तक रावी व्यास वार्टज का ताल्लुक है, उसके लिए एक ट्रिब्यूनल स्थापित करने की बात भी हम लोगों ने मान ली है। इसको वे अब नहीं मान रहें हैं और उसको दूसरी शक्ल में पेश कर रहे हैं।

सरदार स्वर्ण सिंह को भी हमने भेजा। उसके बाद श्री अमरीद्र सिंह जो एम. पी. हैं वह भी आते जाते रहे। अपोजीशन लीडर्ज को भी हमने इनवाल्व किया। सरदार सुरजीत सिंह, अपोजीशन लीडर्ज भी बातचीत करते रहे हैं। हमारी तरफ से किसी भी स्टेज पर बात करने में कोई कमी नहीं रही है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है, रजामंद हैं। उन्होंने कह दिया कि हमको चिट्ठी नहीं आयी, चिट्ठी आएगी तो हम दिल्ली आएंगे। हमारी तरफ से प्रेस्टीज की कोई बात नहीं। सेठी जी ने उनको पत्र लिख दिया। पत्र लिख दिया तो फिर उन्होंने बी टीम भेज दी दिल्ली। अगर वे सीरियस होते, बातचीत करना चाहते और बातचीत से समस्या को हल करना चाहते, तो लोंगोवाल खुद क्यों नहीं आते, बी टीम को क्यों भेज देते हैं? फिर उसके बाद यह कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी को अमृतसर आना पड़ेगा। हम दिल्ली नहीं आएंगे। हमने कहा कि दिल्ली नहीं आना चाहते तो कोई और जगह आ जाओ। चंडीगढ़ चुन लो। वह चुन ली गई। सेठी साहब होम मिनिस्टर चंडीगढ़ गए। कैबिनेट सब कमेटी गई, उनसे बातचीत हुई। हमारी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। हमारी कोशिशों में कोई फर्क नहीं आया है। सेठी साहब ने फिर अपील की है, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस ने फिर अपील की है, दरबारा सिंह जी ने फिर अपील की है, राज्य सभा में कल फिर उनसे अपील की गई है कि आएं और बातचीत करें और बातचीत के जरिये मसला तय हो। लेकिन वह नहीं आते हैं तो उसका कोई कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि पोलिटिकल पावर वे चाहते हैं। उनकी डिमाड्ज पूरी हों या न हों, इससे उनको मतलब.....

श्री चरण सिंह: अकाली लोग अगर नहीं मानते हैं तो वहेस्यित गवर्नमेंट के आपका कोई फर्ज होता है या नहीं होता है?

श्री रघुनंदन लाल भाटिया: आपने ठीक कहा है। जब बातचीत चल रही थी और वे नहीं मान रहे थे तो हमारे अपोजीशन में बैठे हुए कुछ साथियों ने मश्विरा दिया था कि गवर्नमैंट यूनिलेटरली डिक्लेयर कर दे। तीन प्रोपोजल्ज के बारे में सेठीजी ने यूनिलेटली डिक्लेयर कर भी दिया है। चंडीगढ़ के बारे में भी कह दिया है। उसके बावजूद भी वे नहीं मान रहे हैं। अब जो भी तरीका होगा उसको हम तय करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।

वे पोलिटिकल पावर चाहते हैं। इसके अलावा वे बार-बार अपनी बात से फिर जाते हैं। वह इनडिसाइसिव भी हैं और डिवीजन भी है उनमें, इसीलिये भी देरी लग रही है। जहां तक शिफ्ट का सवाल है तो पहले सवाल पैदा हुआ कि हमारी किरमाण 6 इंच की है इस पर क्यों एतराज किया जाता है? जब मैं गोल्डन टैम्पिल में मत्था टेकने गया तो उनके लीडर्स ने 6 इंच की किरमाण दे दी और कहा इस पर क्या एतराज होगा? मैंने कहा मुझे दे दीजिये मैं आपको पेश कर दूंगा। जब इन्दिरा जी को 6 इंच की किरमाण दिखाई तो कहा कोई एतराज नहीं है। वह बात मान ली गई। लेकिन क्या आज अकाली 6 इंच की किरमाण मानने के लिये तैयार हैं? नहीं। वह कहते हैं बड़ी किरमाण चाहिये। इस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं।

सरदार सुरजीत सिंह ने मिल मिलाकर यह बात तय की कि चंडीगढ़ का झगड़ा रह गया है, बाकी सब शर्तें तो मान ली गई, चंडीगढ़ को डिवाइड कर दो। अकाली इसको मान गये। लेकिन बाद में मुकर गये। बलवन्त सिंह और श्री बादल ने माना लेकिन बाद में बलवन्त सिंह यह कह कर छूट गये कि यह उनकी पर्सनल ओपीनियन थी। पहली बात जब 3 जून को यहां सारे अपोजीशन लीडर्स की मीटिंग हुई जो आपका कम्युनिके देखा उसमें ऐसा लगा कि अकालियों ने रावी-व्यास वाटर के लिये ट्रिब्यूनल के लिये मान लिया। लेकिन आज लौंगोवाल की चिट्ठी आयी है सारे पार्लियामेंट के मेम्बरान को जिसमें वह कहते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जायेंगे। इसलिये आपकी सारी मेहनत बेकार गई। अकालियों को किसी पर भरोसा नहीं है।

अब सवाल पैदा है कि अपोजिशन का क्या रोल है? मैं समझता हूं हमने अकालियों से बातचीत करके, प्यार और मेहनत करके उनको मनाया, उनकी बहुत सी डिमान्ड्स मान ली हैं और उन पर सहमत हैं, एक, दो बातें रह गई हैं क्योंकि वह इन्टर स्टेट का झगड़ा है इसलिये किसी की जमीन हम दूसरों को नहीं दे सकते हैं। वह मसला दूसरी स्टेट से बात करके उनको मनाकर ही मसला हल हो सकता है। उससे थोड़ा समय जरूर लग रहा है। लेकिन मैं पूछता हूं कि अपोजीशन वालों ने क्या किया इस मामले में? तो पहले जब अकालियों ने यह डिमान्ड्स पेश की थी तो अपोजीशन का रीऐक्शन निगेटिव था, लेकिन धीरे-धीरे जब एक-एक करके वहां पहुंचे, उन्होंने इनको सरौपे दिये तो इन्होंने अपनी राय बदलनी शुरू की। स्वामी जी तो एक दिन में ही सारा सिक्खों का मसला जान गये और उनका हल भी निकाल लिया। तो वह हमसे ज्यादा जानते हैं। और इनको वहां कोई बन्दूक या तलवार भी दिखाई गई थी। बहरहाल यह उनके अपने व्यूज हैं। हमारे सी० पी० आई० के दोस्तों ने कह दिया कि रिलीजस डिमान्ड्स उनकी क्यों मानी? आप तो सैक्कूलर पार्टी हैं। आज यह भी हमको कोस रहे हैं।

इसी तरह 30 जून को जो इनकी मीटिंग हुई थी उसमें जैसा मैंने कहा वह बात जो मानी गई थी ट्रिब्यूनल की उससे भी वह फिर गये है। यह सब बातें अकालियों को ऐनकरेज कर रही हैं। वह चिट्ठी लिख देते हैं डराने की, चौधरी साहब को भी चिट्ठी आयी थी, और माननीय वाजपेयी जी बोले ही नहीं, एक दफा पठानकोट में थोड़ा सा बोले थे, उसके बाद चुप हैं। दो बार इस सदन में पंजाब पर बहस हुई तो वह नहीं बोले। तो इनको यह डर है कि भिन्डरावाला इनको भी चिट्ठी लिख दें। हमारा तो ख्याल है कि आप भी पंजाब के मसले को हल नहीं कर सकते हैं। आप इसको पोलिटिक्लाइज करना चाहते हैं। यही बदकिस्मती है पंजाब के लोगों की जो आज सफर कर रहे है। अगर आप चाहते, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि अपोजिशन वालों को इन्वाल्व किया जाये तो आप उनको समझा सकते थे, उनको कह सकते थे कि यह बात गलत है, यह गलत नहीं है। उस पर हम भी सुनने को तैयार थे लेकिन चूंकि आपने वह रौल अख्त्यार कर लिया जिससे पंजाब का मसला सुलझा नहीं, उलझा है।

बात यह है कि पंजाब के मसले में जहां आपने मदद नहीं की वहां पोजीशन इसीलिये भी उलझी कि इसमें बाहर की ताकतों का भी दखल है। पाकिस्तान को ले लीजिये। पाकिस्तान में पहले जब सिख जत्थे यात्रियों के जाते थे तो उनकी आवभगत नहीं की जाती थी, लेकिन आजकल उनकी खूब आवभगत की जाती है। वहां तम्बू, कनातें लगाकर जलसे किये जाते हैं, बड़ी-बड़ी स्पीचें की जाती हैं, आदर मान किया जाता है, उनके लीडरों को गिफ्ट दिये जाते हैं और जिया साहब, जो कि इतने बिजी आदमी हैं, उनको भी फुरसत मिल जाती है कि उनके दो-चार लीडरों को दावत देते हैं, खाना देते हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। इसके अलावा वहां के प्रेस का रोल भी इंडिया के खिलाफ बड़ा होस्टाइल है। वह कह रहे हैं कि

हिन्दू तो हमारे पुराने दुश्मन हैं, सिख और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, दोनों के कामन एनीमी हिन्दू हैं। यह वहां के अखबार वाले लिख रहे हैं, फिर भी आप कहें कि पाकिस्तान का कोई दखल नहीं है तो यह·····

श्री अब्दुल रशीद काबली : अखबार का नाम दीजिये।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आपके सामने अभी पेश करूंगा, मेरे पास है।

इसके अलावा अमरीका का भी दखल है। अमेरिका की यू० एन० डेलीगेट विंग क्लब ने सरकुलर लैटर निकला था जिसमें कहा गया था कि हिन्दुस्तान का डि-स्टेब्लाइजेशन किया जाना चाहिये। उसका खंडन आया है, लेकिन उसके बाद भी काफी अखबारों में चर्चा हुई है कि यह गलत है, यह सही है।

शायद हमारा देश इसका जवाब दे, लेकिन मैं समझता हूं कि वह ठीक ही है। बात तो साफ आ जाती है कि उनके मन में क्या है, वह इस मूवमेंट को क्या समझते हैं। जाहिर है कि बाहर के देश भी इस मामले में दखल दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या आपकी सरकार इतनी कमजोर है जो इसको रोक नहीं सकती ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : जब तक अमरीका के समर्थक यहां बैठे हैं,

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप रूस के समर्थक हो गए, इसलिए प्राबलम है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मेरा यह कहना है कि इस सरकार ने सिखों की डिमांडज को प्यार से बातचीत के जरिए तय करने की कोशिश की है, लेकिन अकाली···

श्री मनीराम बागड़ी : सिखों की बात मत करिए, अकालियों की बात करिए।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आपने पूरी बात सुनी नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं। अकाली तमाम सिखों को रिप्रजेन्ट नहीं करते हैं। जैसे मैंने आंकड़े दिए हैं कि पंजाब में 118 सीटों में से सिर्फ 37 उनके पास हैं और 13 पार्लियामेंट की सीटों में से सिर्फ एक है। वह पंजाबियों को रिप्रेजेन्ट नहीं करते हैं, बल्कि सिखों को भी नहीं करते हैं क्योंकि नामधारी सिख हैं, निरंकारी सिख हैं, कांगड़ी सिख हैं और हरिजन सिख हैं। शहरी सिख भी उनके साथ नहीं हैं। अगर इस बात में कोई गलती है तो मुझे बताया जाए। मैं अमृतसर से चुनकर आता हूं जो कि सिखों की मैजोरिटी सीट है। अगर अकाली सारे सिखों को रिप्रेजेन्ट करते हैं तो मैं कैसे चुनकर आया हूं ? वहां गोल्डन टैम्पल है जहां पर से सारी दुनिया में प्रचार करते हैं और पंजाब में प्रचार करते हैं। इसका मतलब साफ है कि सिख देशभक्त हैं, उनकी देशभक्ति में शक नहीं किया जा सकता है। देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना पूरा हिस्सा डाला था और देश की आजादी के बाद जब देश का निर्माण हुआ तो उसमें भी उनका पूरा हिस्सा रहा है।

मुझे चौधरी साहब माफ करें, उन्होंने उनकी देशभक्ति पर शक किया है।

श्री मनीराम बागड़ी : यह क्या कह रहे हैं आप ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में सिखों ने अंग्रेजों की मदद की वरना वह हिन्दुस्तान से चले जाते। मैं कह सकता हूं कि देश की आजादी में सिखों ने ज्यादा असर डाला है।

16.00 hrs.

भगतसिंह फांसी पर चढ़े, ऊधम सिंह फांसी पर चढ़े, करतार सिंह ने अपनी जान दी, देशभक्त गुरदीप सिंह बाबा जहाज पकड़ कर लाए थे देश

को आजाद कराने के लिए। इसलिए हम उनकी देशभक्ति पर शक नहीं कर सकते। मैं आपसे विनती करूंगा कि अकालियों के साथ हमारी लड़ाई है वे सिखों की मेजारिटी को रेप्रेजेन्ट नहीं करते हैं। हम उनको प्यार से समझायेंगे। अगर वह नहीं मानेंगे और दूसरा तरीका अपनायेंगे तो जो कानून है इस देश का उसके मुताबिक उसका भी इन्तजाम होगा।

श्री मनीराम बागड़ी : गलत बात थोड़ी सी मत कहिए, चौधरी साहब ने यह नहीं कहा···

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : चौधरी साहब कह दें · (व्यवधान)···आप वकील न बनें। चौधरी साहब खुद कह सकते हैं।···(व्यवधान)···

श्री चरण सिंह : 1857 की जो बात मैंने कही,···(व्यवधान)···उसके साथ मैंने यह भी कहा था कि 84 परसेंट वह इंडियन ही थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देकर देश को गुलाम बनाया था, जब तो सिख उस लड़ाई में शामिल भी नहीं थे 84 परसेंट वाली में।···(व्यवधान)···

श्री मनीराम बागड़ी : हिन्दुओं के अन्दर तफरका डालने की कोशिश भाटिया साहब न करें। हर हिन्दुस्तानी बहादुर है, कोई भी हिन्दुस्तानी कायर नहीं है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : चौधरी साहब ने अपनी बात कह दी है। आप को वकालत करने की जरूरत नहीं है। वह अपनी बात कह सकते हैं।

मैं अर्ज करूंगा कि पंजाब का जो मसला है वह गंभीर है। उसको हम सबको शांति के साथ हल करना है। जो प्राबलम मैंने आपके सामने रखी है वह यह है कि अकाली जो कि सारे सिखों को रेप्रेजेन्ट नहीं करते हैं, एक माइनारिटी को रेप्रेजेन्ट करते हैं वह ताकत हासिल करना चाहते हैं देश में, करें, जो देश का तरीका है, जो इंडिया का कांस्टीच्यूशन है उसके जरिए, वोटों के जरिए वह पावर में आयें, पहले भी तीन बार आए हैं, फिर भी आयें तो वह उसके लिए एक तरीका है, वोटों के जरिए वह आ जाते हैं तो ठीक है और अगर उसके जरिए न आकर तलवार की नोंक से ताकत हासिल करना चाहते हैं तो नहीं आने दिया जाएगा। मैं सदन में खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ऐसी बात किसी कीमत पर नहीं मानी जायगी। अगर उनकी कोई डिमांड बाकी रह गई है तो बातचीत के जरिए आयें, अपोजीशन वाले भी उसमें मदद करें, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन एक बात बिलकुल साफ है कि पंजाब सरकार हो या सेंटर की सरकार हो उनके एक्सटीमिस्ट्स के सामने और जिस ढंग से वह ताकत हासिल करना चाहते हैं उसके आगे हरगिज नहीं झुकेगी। यह इंदिरा गांधी की सरकार है, यह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगी। पंजाब का पूरा इन्तजाम किया जाएगा। उन लोगों से डील किया जाएगा। कानून किसी को नहीं बख्सेगा चाहे वह गोल्डन टेम्पल के अन्दर हो या बाहर हो। काफी आदमी पकड़ लिए हैं पंजाब सरकार ने और काफी आदमी और पकड़े जा रहे हैं उनकी इन्फार्मेशन के मुताबिक। मैं एक बात और कह दूं···(व्यवधान)··· मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं।

यह जो प्राबलम है यह मैंने आपके सामने रखी। सरकार ने पूरी कोशिश की है इस मामले से निपटने की और अगर किसी दूसरे तरीके, किसी दूसरे ढंग से अकाली यह चाहें कि इस मसले को हल करें तो इसकी कभी इजाजत नहीं दी जाएगी।

श्री मनीराम बागड़ी : एक बात पूछना चाहता हूं उनसे आपके माध्यम से कि होम मिनिस्टर का यह बयान है कि जो गुनहगार हैं वह गोल्डन टेम्पल में हैं और भिन्डर साहब जो आई०जी० हैं उनका बयान है कि वह वहां नहीं है, दोनों में कौन बात सही है?

सभापति महोदय : यह होम मिनिस्टर से पूछिएगा। इसका जवाब भाटिया साहब नहीं देंगे।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): Chairperson, I was listening with rapt attention to my immediate predecessor, the hon. Member of the ruling party, Mr. Bhatia. I am happy to note that he has made intensive research into the composition of the Akali Party and he has come to the conclusion that the Akali Party is of kulaks and zamindars. Actually it is a sad commentary on their Party because under their system zamindari still remains. Now he has also made ample utilisation of statistics and actually he has come to a grand conclusion that the aim of the Akalis is to capture power with open sword. It is a piece of news and for this grand discovery, I think, he should be awarded Bharat Ratna or something like that. But so far as common people like us are concerned, we have not seen anywhere that the Akalis are trying to capture power with their swords.

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : राज करेगा खालसा ।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : But the people who are saying this, Bindranwale and his followers, are the people who actively campaigned for you in 1980 elections. Against the people who are giving an open call to defy law and are indulging in violence, you are practically doing nothing to curb their activities Before you accuse the opposition, Mr. Bhatia, should not there be some self-introspection ? Tell me : is there any Government worth the name in Punjab ? (*Interruptions*) Is it not the responsibility of the Punjab Government to tackle violence and extremist activities ? (*Interruptions*) What is your Government doing ? It is your responsibility. We have never told you either in this Parliament or outside not to take action against the extremists and the people who are violating laws and indulging in violence. It was your incapacity and spinelessness that you did not dare to take any action. And the second thing because of which you could not take any action, is that there are some people in Delhi belonging to your party, who are restraining your hand and preventing you from doing it. Do you want to challenge it ? I want to quote from your people of Punjab Legislature Party. You know better than I do. He is Mr. Birdevinder Singh, Chief Whip of Congress (I) Legislature Party. This has appeared in '*The Tribune*', Chandigarh, of 5 June, 1983. Among other things he said :

> "Referring to the killings by the extremists and the failure of police to apprehend the culprits, he said the police were either demoralised or lacked a proper direction from the Government."

You accuse the opposition. You try to find a scapegoat. But this is your leader, Chief Whip of your Legislature Party in Punjab, who is openly saying and it is published in a newspaper that because of lack of direction from the Government, culprits cannot be apprehended. I think, you understand it.

PROF. K.K. TEWARY (Buxar) : I would like to know whether the veracity of this paper statement...(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : I am really sorry to see the pathetic result of Bangalore brain washing. This is the result of your Bangalore brain washing...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Mr. Chakraborty, you address the Chair.

PROF. K.K. TEWARY : With permission of the Chairman you can quote, not without that.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Now, I would ask Mr. Sethi, on the last occasion he declared in the Rajya Sabha that he would take stringent action against the culprits who might be hiding in the Gurudwaras. That was a bold declaration but why did he not do it, not implement it ? Who prevented him ? Did the Opposition prevent him or is it a fact that his own people prevent him or because of lack of courage, lack of direction or because of the fact that some of the extremists are your potential friends, you want to utilise them in the near future, power being the *summum bonum*, be-all-and-end-all of your thinking and activity ?

Prime Minister is supposed to be very very

responsible. After her tour she reaches our country and says that the Opposition Parties are responsible and they are exploiting the Punjab situation. How are the Opposition Parties exploiting ? Well, there is nothing wrong in democracy to try to gain power. You want to remain in power—we want to go to power by ballot. That is not your understanding of democracy as far as Indira Gandhi and other Congress leadears are concerned. But what is democracy ? Labour Party comes to power, Conservative Party comes to power. That is not your idea of democracy because you think that the Congress is born to rule and it will continue to rule. Surely we will put forward our points of view, will try to capture the minds of the people. It is a battle to capture the minds of the people and to get majority in the ballot. That is the democracy that I can understand. What is your version of democracy, please give it. The Prime Minister says that we are trying to exploit but the Opposition Parties met and wanted to cooperate with the Government to find a solution. And it was Mr. Bahuguna who said to the Akalis that 'if you do not condemn violence you count us out.' The Opposition Parties gave a call being responsible, because they have the unity and integrity of their country in their heart, that 'we are ready to cooperate with the Government and find a solution to the Punjab problem.' And the response from the Prime Minister and her party is that the Opposition Parties are out to create disruption. They are trying to make political capital out of it. Just now Mr. Bhatia boldly declared that since Indira Gandhi is in power, they will solve it. Well, we all know that you can solve it because you are in power. We are in opposition, we can suggest but we cannot do. But the problem is, Mr. Bhatia, your bold declaration is good but why can you not solve it ? It has been hanging fire for a pretty long period and why is it that you cannot solve it ? If you say that you can solve it, you are strong enough, then it means that since you are not solving it, you are not interested in solving it because by using the extremists you want to discredit the Akali leaders. Now, what is happening in Punjab ? Because of your procrastination, the whole movement is gradually taking communal turn. After 1947 there was no communal riot in Punjab.

All the religious communities, all the linguistic communities were living peacefully. Now we find that communal riots have taken place three time. I would like the Government to take note of it. There is a Hindu Suraksha Samiti, where Congress (I) people are members Can you tell me why in Haryana they have the Hindu Suraksha Samiti ? Are they afraid that people from Punjab are going to attack them. Giving a communal turn in this way is dangerous. Probably your calculation is that if there is a communal turn, the Hindus will come to you for security and they will support you.

AN HON. MEMBER : Jummu pattern.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Exactly what you did in Kashmir...(*Interruptions*) You will have a chance to speak when you can have your say. You utilised the Shia-Sunni differences in Kashmir ; you utilized the communal forces in Kashmir just to capture power. In Punjab also the Congress (I) people are leading other communal forces, like the Hindu Suraksha Samiti. There is a pattern, there is a method in their action. In Assam they did the same thing. They allowed the boys to do all these things. They exploited the whole situation ..(*Interruptions*) Yes, you did it, and not in a democratic way. There is a pattern in it. Your economic policy cannot give economic benefits to the people. That is why your policy, like the British, is to divide and rule.

Now I would ask a straight question. Is it not Shrimati Gandhi who in 1970 gave the award that Chandigarh should go to Punjab ? Is it not a fact that there was a time frame of five years within which it was to be implemented ? Instead of accusing Janata and other parties, why did they not implement it ? After all, it was their award. Why did they not implement it, at least during the emergency, when they were enjoying absolute powers, sending millions of people to jail ? They did not do it must for the sake of political expediency.

Now it is not the demand of the Akalis,

it is the demand of the whole people of Punjab that Chandigarh should be a part of Punjab and that a separate capital should be built for Haryana. You are committed to it ; the money for it will have to go from the Centre, according to the award of the Prime Minister. Since we from the opposition are asking for the implementation of this award, you are saying that we are exploiting the situation and making political capital out of it. What is this ? Whom are you trying to hoodwink ? Why are you creating a smoke-screen ? It is your award and it is your party which should implement it.

I have said on the floor of the House that we do not believe in communalism or in demarcation of areas on the basis of religion. That is a medieval idea. In Europe they fought for 100 years and then came to secularism. From bitter experience we have learnt that the basis of division of State cannot be religion but only language. I do not agree with Shri Charan Singh when he says that there should be one language for the unification of the country. Switzerland has four languages and yet it is a nation. The Soviet Union has many languages and yet it is a nation. Ours is a multilingual country.

So, I strongly urge that in Punjab the village should be regarded as a unit. Whether a village should go to Punjab or Haryana should be on the basis of language and nothing else. If for implementing this principle some villages from Punjab are to be given to Haryana, it should be done. Similarly, if some villages from Haryana should go to Punjab, it should be done. This is not a new principle. I suppose Shri Bhatia knows the resolution of the Congress before independence.

The Indian National Congress was committed to dividing the States on the basis of language. It is only after Independence that you deviated from this principle and when people started the movement, Andhra was created and later on the States Reorganisation Commission was constituted. Why should it not be implemented now ? Are the Akali wrong ? Are they frustrated politicians out to capture power when they want that you should implement your own award, when they demand that certain villages...

SHRI R.L. BHATIA : First they wanted Hindus' areas to be cut. (*Interruptions*). They deliberately cut Kangra because it is a Hindu majority area. Akalis wanted to have a Sikh majority area. It is part of Punjabi Suba. If you do not understand...(*Interruptions*). They want to cut an area where they have a majority.

(*Interruptions*)

SHRI CHITTA BASU : It is a question of language, Hindi or Punjabi.

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Madam, I would like to draw your attention to the fact as to how they are making the thing difficult.

You are now ready to refer everything to the Commission. Why can't you delink Chandigarh, to which you are committed, Mr. Bhatia ? You referred everything to the Commission. Why are you not delinking Chandigarh ? I ask : When did you start talking with the Akalis ? Akalis did not start agitation then. They wanted to talk. For one year they patiently waited. You only started talking when they had started their movement and when their 'Jail Bharo' movement was very successful. Then only you understood the reason and you started the talks. You referred to Sardar Swaran Singh. Well, Mr. Bhatia, you are a knowledgeable person. What was the suggestion of Sardar Swaran Singh ?

MR. CHAIRMAN : You address the Chair and talk.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Yes, yes, I am sorry. You are always there and I am addressing them.

So, Madam, I want to know what was the suggestion of Sardar Swaran Singh, and whether it is a fact or not that an agreement was reached between Sardar Swaran Singh and Akali leaders. And a statement was also drafted which was to be published, but subsequently the Government of India changed its mind and the statement that came out was not the statement which was

agreed upon. The Akalis agreed. In the tripartite talks most of the issues were almost settled and the differences were narrowed down. Ultimately you are not interested in solving the problem because of political reason, i.e., with the help of the exremists you want to crush the Akalis and to make the Punjab safe for Congress (I). Who is indulging in politics ? It is your party. You proclaimed that 'we are a secular party'. Is it true that you are a secular party. But what is your action ? I do not question. Yes, the Prime Minister is talking of secularism. But it appears to be disturbing that in Kerala you have joined with a communal force, in Tripura you joined the extremist force. Where is your secularism ? Where is your anti-casteism ? Your only aim is to remain in power and any action which helps you to remain in power is good for you. You have no standard ; you have only one standard to remain in power. That is why you keep the Punjab question burning. That is why is you don't take action against the extremists and that is why you are not really interested in solving the problem: Otherwise the problem would have been solved. So, I say that this is a problem which concerns all the political parties. I do not agree with Mr. Bhatia that it is their problem. It is nation's problem. Punjab is a border State and the Punjabis are valiant people. They made the supreme sacrifice during the freedom movement. I have told it here, I shall go on telling it that when I was in Andamans, I had seen the names of the Punjabi heroes who had made the supreme sacrifice for the freedom of our country.

I cannot believe that Punjabis are behind Khalistan. There is a minority and I am happy to note that at long last.

Rip Wan Winkle has woken up. You have said that foreign hands are there. We had been shouting here that foreign hands are there. They are trying to disrupt. Now I am happy that you have accepted it. It is good. Now take stern action against all these extremists. We have never said to be soft to the extremists. We have never said that do not take action against these people who are demanding Khalistan. Why are you not taking ? Now it is time for you to take it. I believe that reason will dawn and you will be taking the co-operation of the opposition parties. Talk with the Akalis. You have said....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Time is over.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Minister has sent a letter. Here is a copy of the letter published in the Tribune. Here it has been said we are ready to talk. But what is the solution ? You have said nothing about the solution. What is Congress (I) solution ? You condemn us and say the opposition parties are creating trouble. But you are the ruling party. What is opinion of your party ? What is the solution that you yourself advocate ? Please tell us, we want to know. Nothing concrete ; only referring it to Commission ! Only this thing ! Religious demands you have accepted. (*Interruptions*)

SHRI C.M. STEPHEN (Gulbarga) : That is the solution—reference to a Commission.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : That is a solution ! Very good.

SHRI R.L. BHATIA : If the parties do not agree, it has to be referred to the Tribunal.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : What you have said is full of sound and fury which signifies nothing. What is that ? They have put forward certain demands—concrete demands. You must have thought of certain concrete solution—your party's solution.

SHRI C.M. STEPHEN : What is your party's attitude to the demands which are listed here ? What is the attempt of your party ?

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : We have clearly said what is our party's stand. But will you kindly say what is the stand of your party ? Will you kindly say what is the stand of the Punjab Congress (I) ? Will you kindly say what is the stand

of Haryana Congress (I) ? You know what is happening in Punjab and Haryana. They are fighting. Have you a all India party, all India opinion ? You do not have.

SHRI R.L. BHATIA : Supposing a solution is found out, can you take the responsibility that they will agree to it ? They will still go back.

SHRI C.M. STEPHEN : Because you have come up with your own consensus, we are asking you to send your own people to Haryana and Panjab. (*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : I would ask you one question. When elections were held in Assam, did you act an agreement of all the political parties ? We agreed. But BJP and Janata did not. You go ahead. You are the ruling party. Now I would say please give up your policy of drift and procrastination. Please negotiate. Make up your mind. Stop accusing the opposition parties. You think you are preparing yourself for the coming elections. Forget for the time being the elections. Think about the country and try to arrive at a settlement. Think about the interest of the country. Try to arrive at settlement on just and democratic demands of Panjabis.

This is a border state. We are to stop the poisonous propaganda that is going on. Let us unitedly work to save our country from disintegration against the foreign forces which try to disrupt our unity. Let us work together. But before that you will have to give up your procrastination, drift and accusing the opposition parties. You must realise your weakness, your fault and then and then solution can be found.

SHRI CHIRANJI LAL SHARMA (Karnal) : Madam Chairman, I have been listening with rapt attention to the most eloquent but apparently powerful speeches of some of the hon. Members from the Opposition. One thing that puzzles my brain and baffles my understanding is as to why this is termed as "Punjab issue", while the neighbouring States are directly involved. The real problem is being ignored. Why do we not call it 'Punjab-Haryana-Rajasthan issue' ? Probably, hon. Members from the Opposition have not thoroughly studied the problem.

The trouble started, Madam-Chairman, after the 18th February, 1982, when after the agreement that was arrived at between the three Chief Ministers on the 31st December, 1981 regarding the Ravi-Beas water dispute, Madam Indira Gandhi went to village Kapuri in Patiala district, to perform the inaugural ceremony of the SYL canal. It was from that day onwards that the trouble started. The Akalis started with five demands. The number went up to 45 and now they come down to 12. I am saying this on the basis of a letter which has been addressed to the Members of Parliament by Sant Longowal. This letter brings down the number of demands to 12.

I would not be wasting the time of the House by dilating upon all those demands. I will be touching only two of them with which Haryana is directly concerned. Madam Chairman, I will first touch this Chandigarh problem before I come to water dispute. Haryana was a part and parcel of Punjab before partition and even after the partition of the country in 1947.

I was a Member of the Punjab Assembly those days. I know the treatment that was meted out to Haryana by the then Punjab and the Punjabi people. Our rights were being ruthlessly trampled under their iron feet. So tremendous was the onslaught, so terrific was the blow and so bloody was their machine of coercion, that Haryana was practically shaken under their heels. Haryanavis were obliged to raise a hue and cry saying that they could not tolerate it. With the result that one Committee, known as the Sriram Sharma Committee was formed. This Committee had been formed because the budget that was passed for the Haryana region used to be consumed and used to be spent in the Punjab region. We rose in protest agaist it. After the recommendations of the Sriram Committee, there was a demand for Punjabi Suba. But before the demand came, two committees known as the Hindi Regional committee comprising the present Haryana area and the Himachal which was part of Punjab, and the Punjabi Regional committee had been formed. Very soon, there was a demand for the Punjabi Suba, not by Haryanavis, not by the Himachal people,

but by Akalis. Well, their dreams could materialise. Luckily for Haryana, Punjabi Suba was formed. Haryana did not lose anything. Punjab lost and lost materially. Haryana gained and gained solidly and Himachal was all gold. In this connection, Madam Chairman, I deem it necessary to point out because their one of the demands is that Punjabi should be the second language of the adjoining States of Punjab, namely, Rajasthan and Haryana. This Gurumukhi and Punjabi used to be taught all over the erstwhile state of Punjab, of which Haryana and Himachal were part and parcel.

Haryana came into being on the 1st of November, 1966. What was our position that day ? What is our position today ? During the span of 16 to 17 years, our State of Haryana has made tremendous progress in every walk of life, whether it is industry, whether it is agriculture, whether it is technology, whether it is roads, whether it is transport, whether it is electricity, whether it is education and so on, because we heaved a sigh of relief. But the progress of Haryana shows how we were made to suffer immeasurably so long as it was a part of Punjab.

After Haryana came into being, at that time, the Shah Commission was there because of the linguistic division of States. What was the recommendation of the Shah Commission ? Without going into details, I would refer to para 135, sub-clause (3). I quote :

> "That District Hissar, Mohindergarh, Gurgaon, Rohtak and Karnal, and Tehsils Narwana and Jind (District Sangrur) and Tehsil Kharar (including Chandigarh Capital Project), Naraingarh, Ambala and Jagadhri will form the Hindi-speaking State."

My hon. friend, Mr. Charan Singh, for whom I have great respect, was laying stress on the report and the recommendations of the Shah Commission. We also stick to that, that the report of the Shah Commission is implemented. But what happened subsequently ? There was a hue and cry amongst the Akalis, the then Akali leaders, and Sardar Fateh Singh gave a threat to immolate himself if Chandigarh was not given to Punjab. The result was that due to these pressure tactics, Madam Prime Minister decided to modify the award given by the Shah Commission. What was the modification ? It was that Chandigarh, minus seven villages and railway station of Chandigarh will go to Punjab and 114 villages and Fazilka will go to Haryana. This award was given by Madam Prime Minister or, say by the Government of India or it may be said like this that the Shah Commission's report was modified to that extent. Now, we stick to that.

My learned friends from the Opposition have been supporting the case of Punjab saying that Chandigarh should go to Punjab. Let Chandigarh go to Punjab. But may I have the temerity, through you Madam, to ask my hon. friends as to why they are not uttering a word about the transfer of Abohar and Fazilka which was also a part and parcel of the award ? Nobody is speaking about it. This is something which certainly pinches us. I do not know why this change in the stand of the Opposition. Just about a couple of months back Punjab was discussed, not once, but twice in the House.

There was a meeting of the Opposition parties in Vijayawada. The leader of the Lok Dal, Shri Charan Singh, refused to attend the meeting saying that it was a meeting of the regional parties and that he would not attend it. Surprisingly enough, for reasons not known to us, better known to him, he decided to attend the opposition conclave in Delhi. We have no explanation for that. I do not know as to why he decided to do so. Was it under threat of letters addressed to him by the Akalis ? He is a bold man.

SHRI CHARAN SINGH : Pressure of my friends of the other parties. That is all.

SHRI CHIRANJI LAL SHARMA : Mr. Charan Singh has been good enough to tell the House that it was a pressure of friends. It was a pressure from the parties which he had the opportunity of testing during the period when he was guiding the destiny of the country, as the Prime Minister, the parties that refused to repose confidence in him ;

and the parties that betrayed him, while he was being inducted as Prime Minister of the country and now again he feels that if they join hands and heads together, they can again come to power. I can say with a sense of confidence and responsibility that this dream of the Opposition will never be allowed to materialise.

Now about Chandigarh. As was rightly pointed out by Mr. R.L. Bhatia, the Akalis were in power for sometime in 1967. Then again Akalis were in power from 1977-79, for a period of about 33 months. There was Akali Government in Punjab. There was Janata Government in the Centre and Shri Surjit Singh Barnala was the representative of the Akalis in the Central Government. Again, may I ask my Hon. friends as to whether they ever care to ask the Akalis as to why they kept mum during the span of 33 months when they held power, when they were at the helm of affairs and why they did not raised hue and cry ? Silence amounts to acquiescence. What does it lead to ? This leads to the irrebuttable conclusion that it is nothing but a struggle for power. If Sardar Darbara Singh is replaced by Shri Badal and if an Akali replaces him, the whole problem will be solved. Otherwise, what was implicit has become explicit by this action of the entire Opposition who support the Akalis. They kept mum so far.

Then again what is the role of the Opposition ? What did the Opposition do just a couple of months earlier ? The Opposition was of the considered opinion that the integration of the country should be there. That was the primary thing. Does this action of the Akalis, who have tried to take the law in their hands, who created terror and who are creating disturbance in the calm sea of the nation, show that they believe in integration of the country ? Then let me refer to the BJP in particular in this connection.

एक सुरतिया में दो सुरतियां ।

What does BJP say in Haryana ? Refer to the statement of Shri Mangal Singh completely contradicting the stand that has been taken by BJP leadership. In this connection...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कांग्रेस वालों को अच्छा नहीं लगता है यह !

श्री चिरंजी लाल शर्मा : वह अच्छा लगता है या बुरा, मैं इस सिलसिले में चूंकि माननीय वाजपेयी जी ने बीच में टोक दिया इसलिए एक शेर अकबर इलाहाबादी का कह दूं :

मेरा तरीके मज़हब क्या पूछती हो मुन्नी,
शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी ।

Both the Akalis and the BJP had formed the Government together. I do not use unparliamentary language. Let me not be misunderstood. But I do not find a better word. They are the chips of the same bloc and that is why the BJP is now taking the stand that Chandigarh should be given to Punjab. I have very high regard for Shri Vajpayee and all his friends. Why do they take this stand ?

In all fairness, they should say that if Chandigarh be given to Punjab, Abohar and Fazilka should go to Haryana. We have no objection to it. We say that this transfer of Chandigarh to Punjab and Abohar and Fazilka to Haryana should be done simultaneously, on the same table, at the same time and with the same stroke of pen.

About water dispute, I have to say a few words about Ravi and Beas water. The river Beas rises in the Pir Punjab range near Rohtang Pass in the upper Himalayas and falls in the south-westerly direction in Himachal Pradesh till it emerges in the plains near village Talwara in Hoshiarpur district of Punjab.

River Ravi rises in Bara-Banghal area in Chamba district of Himachal Pradesh and drains the southern slopes of the Dauladhar range. After crossing the Shivaliks, it enters the Punjab plains at Madhopur.

Now I would refer to the letter addressed to the MPs by Sant Longowal. He says :

> "Application of internationally and even nationally recognised riparian principle for the distribution of Punjab river waters."

They have completely forgotten, or perhaps do not know, that the riparian rule of water applies from country to country and not from State to State or from district to district or from tehsil to tehsil. Simply because, after coming from Chamba and other places these rivers, pass through the plains of Punjab, Haryana should be deprived of the right of water of these rivers—this is what they say. If Haryana also starts applying such principles and says that they will not allow people from Punjab to pass over their roads, would that be all right ? Is it at all a reasoning ? But this is the argument that is being advanced.

In this connection, I would be referring to the recommendations of four or five Committees. I am in possession of all documents. The Food Committee recommended during February 1966 that 4.56 million acre feet of water be allocated for the areas now forming the State of Haryana. Number two, the Fact Finding Committee, in April 1970, recommended that 3.78 MAF should be allocated to Haryana ; the case then remained under correspondence between the Government of India and the States of Punjab and Haryana ; no decision was arrived at. Number three, the Planning Commission Note of March 1973 ; in this Note an allocation of 3.74 MAF, on the basis of availability of surface and ground waters, was suggested for Haryana. Number four, the Chairman, Central Water Commission, reported in 1974....

श्री राम विलास पासवान : यह सबको मालूम है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : सबको मालूम होता तो यह बहस नहीं करते।

I happen to be an advocate by profession. Either convince us or be open to conviction. A lawyer tries to convince the court by cogent and reasonable arguments and rulings and this august House is the highest court in the country.

In this Report the Chairman, Central Water Commission, recommended sharing of the water on fifty-fifty basis. Lastly, the Award given in 1976 by the Prime Minister shows that 3.5 MAF water was given to Haryana.

In this connection it will not be out of place if I make a mention of the population and the area, cultivable as well as otherwise of the five States. The census figures of 1981 are : Punjab 1,66,69,755 ; Haryana 1,28,50,902, that is, 56 per cent and 44 per cent.

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : हमारे माननीय सदस्य रूलिंग पार्टी के हैं, अपनी तरफ से हम एक आफर करते हैं, सारा पानी जितना अपना चाहे लें और उनको दे, शांति करवा दें और सुलह करवा दें।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : बहुगुणा जी ने कहा है कि फैसला करा दो। तो हम ने कितनी दफा फैसले के लिए इनवाइट किया है।

The Cabinet Sub-committee showed grace and magnanimity by going to Chandigarh twice, i.e. on 11.1.83 and 18.1.83. Then we are addressing letters time and again. The Home Minister has been asking them rather requesting them again and again.

लेकिन उनके नखरे जिहाज में चलते हैं। बहुगुणा जी हम से कहते हैं, लेकिन वह खुद तशरीफ ले गए थे, संतजी से उन्होंने मुलाकात की है। उनका जो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया हम उस का स्वागत करते हैं। जो गलत बात थी उन लोगों की वह उन्होंने कही। तो जहां तक हमारा सवाल है फैसला कराने का, हम हर वक्त तैयार हैं।

We are inviting them with open arms to come and discuss.

श्री राम विलास पासवान : चिरंजी लाल जी, जब दोनों कोर्ट में चले गए थे देवी लाल जी और प्रकाश सिंह बादल जी पानी के मसले को लेकर तो आपकी सरकार आई, उसने फिर विदड्रा क्यों करवा लिया दरबारा सिंह और भजन लाल से ? फैसला होने देते।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : चूंकि पासवान जी ने

एक सवाल किया है इसलिए मैं उसका जवाब देवीलाल जी के एक डी०ओ० से देता हूं :

सभापति महोदय : आप टाइम का भी ख्याल रखें ।

SHRI CHIRANJI LAL SHARMA : This is a very important subject. This is D.O. No. 18/16/78 PW-2 dated 18th April 1978. This was written when Mr. Devilal was Chief Minister in Haryana and Mr. Badal was guiding the destiny of Punjab as head of the Akali Govt.

श्री राम विलास पासवान : वह क्या पढ़ते हैं ? कोर्ट से मामला क्यों उठवा लिया यह क्यों नहीं बताते ?

श्री चिरंजी लाल शर्मा : बतला रहे हैं। सुनिए तो ।

You kindly listen.

"My dear Badal,

You would kindly recall our numerous discussions regarding the start of work of Sutlej-Yamuna Link Canal in the Punjab territory. Before the start of the Budget session of the Vidhan Sabha on 28th February it was agreed that you will perform the opening ceremony of the canal at a function to be arranged by you. I was expected to preside over this function. On the basis of this assurance I had made a statement in the Vidhan Sabha to this effect. As the start of the work has already been considerably delayed, I shall be grateful if you would kindly fix an early date for the function and communicate the same to me along with the time and venue. If you would like me to make any arrangements, I shall be glad to assist."

This letter bears testimony to the fact that when Mr. Devilal was the Janata Chief Minister of Haryana and Mr. Badal was the Akali Chief Minister, a decision to start digging of the canal had been taken by them. And now the hands of the clock cannot be put back and the decision cannot be reversed. With your permission, Madam, I place this *letter on the Table of the House.

I again just draw the attention of my hon friend to a letter dated...

MR. CHAIRMAN : You have already taken 25 minutes. Please conclude now.

SHRI CHIRANJI LAL SHARMA : 5 minutes more Madam. This is a very important subject.

This letter is from the Commissioner and Secretary to the Government of Haryana regarding the money that has been advanced saying that land has been acquired. Haryana has advanced Rs. 20.5 crores towards the construction of this canal on 10.11.76—Rs. 1 crore, on 30.3.79—Rs. 1 crore, on 11/12th January 1982—Rs. 2 crores, on 25th February 1982—Rs. 4 crores, on 20th August 1982—Rs. 7.5 crores, on 18th October 1982—Rs. 5 crores. The total amount that has been advanced in favour of Punjab for the construction of the SYL canal comes to Rs. 20.5 crores.

I am also laying the copies of these letters on the table of the House. (*Interruptions*) After spending Rs. 20/1-2 crores, not an inch of land digging has been done in spite of the categorical assurance given by Punjab. I do not know what the Punjab Government had been doing ? The Punjab Government is not doing the digging operations due to the threat of the Akalis. Can the Government run like this ? This is something, Madam, which cannot be tolerated.

Shri Charan Singh had put a very pertinent question. If the Akalis failed to turn up for discussion, why did not the Government give the unilateral decision ? Madam,

* The Speaker not having subsequently ascended the necessary permission the paper was not treated as laid on the Table.

hon. Members of the Opposition are fully aware of this fact that the decision was given in 1970 regarding territorial matters that Chandigarh would go to Punjab and Abohar and Fasilka to Haryana. The decision regarding River Beas Water was given in 1976. Has this been implemented ? The last agreement was signed on 31st December, 1981 by Sardar Darbara Singh as Chief Minister of Punjab, by Mr. Bhajan Lal, as Chief Minister of Haryana and by Shri Mathur, C.M. Rajasthan. This was further attested by the then Irrigation Minister. This was further confirmed in the presence of our Prime Minister. Now by their own conduct they are estopped under Sec. 115 of the Evidence Act, from taking the plea that this should be reopened.

Where is the guarantee that after another decision is taken, the Akalis will be ready and willing to abide by it and that they would implement that decision ? Where is the guarantee that they would honour this decision if it is taken unilaterally ? Does it not show the magnanimity, the broadmindness and largeheartedness of the Government of India and, particularly, of the Prime Minister and the Home Minister that in spite of the rigid stand taken by the Akalis, they are requesting them time and again to come for a discussion ? All this has been an exercise in futility. Is the Government to blame for it ? Is the Congress Party to blame ? No !

Madam, you must have also read in the papers that on the 17th of last month, there was a *rail rokho* agitation in Punjab. The Government of India took a wise decision not to run the trains because the Akalis wanted to create mischief. This decision of the Government of India was adversely commented upon by certain leaders. It was said that this decision of the Government not to run the trains showed its weakness. The decision taken by the Government not to run the trains that day was a very important decision. This also showed that Government was open to conviction. Government is ready and is willing to talk. But, because of the support given by Shri Vajpayee Ji, because of the support given by the Janata Party and other Opposition leaders, the Akalis have been inspired to take this rigid stand not to have talks with the Government. This is a political exploitation of the situation. Regarding the conduct and the attitude of the Opposition Parties, I would say, Madam, that so long as Smt. Indira Gandhi is there to guide the destiny of this nation as the head of its Government, not an inch of land from India will be allowed to get away. This is the secessionist approach of the Akalis hached by Opposition Parties which is encouraging them to believe in this sort of separation. This is nothing but a hue and cry for Khalistan in miniature. All Akalis are not extremists. There are 12 M.Ps. belonging to the Congress Party. May I ask a question as to why these Congress M.Ps. are not taken into confidence by them ? Don't they represent India ? Why the Sikh Congress men and why the Hindus from Punjab are not being taken into confidence in the matter of discussion regarding the Ravi-Beas and Chandigarh issues ?

17.00 hrs.

Why Akalis alone ? Why this undue importance is being given to Akalis ? I would say that these dreams of the Opposition will not materialise even if heavens fall.

अपोजीशन तो दूर, ज़मीन की ताकत तो क्या समुद्र के तूफान और आसमान को बिजलियां भी इंदिरा जी के रास्ते में हायल नहीं हो सकती। देश के टुकड़े-टुकड़े नहीं होने दिए जायेंगे।

इन्हीं चन्द अल्फाज के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

17.01 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

···(व्यवधान)···

श्री जॉर्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस पर चाहे जो भी फैसला हो, मगर एक बात बहुत ही साफ हो चुकी है, दो सदस्यों के भाषणों को सुनने के बाद और इस

सदन के बाहर इस सदन के ही एक सदस्य ने, जो अन्य सदस्यों से कुछ विशेष जानकारी रखते हैं। उनके अपने बाहर के बयान से कि पंजाब की समस्या का हल इस सरकार से होना नहीं है। सरकार का जो मानस है, यहां पर दो माननीय सदस्यों के जरिए व्यक्त हुआ है, उससे पहले ही हमें अन्देशा मिल चुका था। 16 जुलाई के ट्रिब्यून में यह रोहतक की खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :

> "Mr. Rajiv Gandhi, one of the AICC General Secretaries today came down heavily on the Akali Dal, the National Conference and other Opposition parties. He said the Akalis had been caught in thier own game and the time was not far when their own men would beat them. Speaking at the fourth NSUI training camp here Mr. Gandhi said the Akali demands could not be accepted. Their demands would never end and they would keep on raising new ones for their political survival."

एक और खबर हिन्दुस्तान टाइम्स में पी०टी० आई० की खबर है, इसी भाषण के तीन रोज पहले 13 जुलाई को अमृतसर में यही महानुभाव कहते हैं :

> "Mr. Gandhi said the Akali agitation had been launched with a view to 'grabbing political power' and not for fulfilment of 'certain demands'.

सरकार की जो भावना है, वह इस बारे में बहुत ही साफ और स्पष्ट है। इस बात से परेशान होने की स्थिति कम से कम मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हम इस बात को पहले ही जानते थे कि कम से कम अगले चुनाव समाप्त होने तक इस मसले का फैसला इस सरकार से अपेक्षा करने की बात गलत है। क्योंकि सरकार को यह मसला जिन्दा रखना है।

इसका कारण बहुत ही साफ है। एक तो यह सत्र शुरू होने वाला था, उसके एक दिन पहले प्रधान मंत्री का जो भाषण हुआ और जिसमें उन्होंने कहा—विरोधी कैसे देश को विघटित करने के काम में लगे है, विरोधियों को मारना है। इनके पास और कोई चीज बची नहीं है, सरकार चला नहीं पा रहे हैं, समस्याओं का हल नहीं कर पा रहे हैं, काम करने वाली सरकार क्या काम कर रही है—यह सब दुनिया को दिखाई दे रहा है। अब एक ही चीज़ बच गई है—हम तो निकम्मे हैं, लेकिन ये लोग जो देश को विघटित करने का काम कर रहे हैं, इनके साथ हमारा निकम्मापन ठीक चलेगा। अब यह तर्क आगे के साल-डेढ़ साल तक चलेगा। क्यों चलेगा—इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं—एक तो जैसा मैंने कहा—कोई भी आर्थिक, कोई भी राजनीतिक, कोई भी सामाजिक समस्या को हल करने का काम आपके हाथ से अब होना नहीं है। दूसरा कारण—पिछले साल के मई महीने की 15 तारीख से हिन्दुस्तान के दस राज्यों में चुनाव हुए—जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल के इलाके, पूर्वांचल के इलाके, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उसके बाद दक्षिण में केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक—इस तरह से 10 राज्यों में इनका सफाया हो गया। इन लोगों का जो मज़बूत गढ़ माना जाता था—कर्णाटक और आंध्र—इनके हाथों से निकल गए, इनकी नेता का अपना क्षेत्र भी नहीं बचा···

···(व्यवधान)···

कुछ सुन लीजिए और अपने नेता को जाकर बतलाइये। सिर्फ ताली बजायेंगे तो फिर कल यहां आने का मौका नहीं मिलेगा। अपने नेता को समझा दीजिए। अच्छे नेताओं का काम होता है दूसरों की बात सुनना और अपने नेता को समझाना।

इसलिए जब 10 राज्यों में सफाया हो गया और वहां से भी सफाया हो गया जहां से ये बहुत उम्मीद रखते थे, तो अब बचा क्या—सिर्फ हिन्दी इलाके···

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आप ने अपने लिए कौन सी जगह इस बार तय की है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप तो यूथ कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं।

ऐसी स्थिति में इन्होंने तय किया कि उत्तर हिन्दुस्तान में ऐसी स्थिति का निर्माण करो जिसमें सिखों को बदनाम किया जाय। इन्होंने कहना शुरू कर दिया—कि इन लोगों के जरिये देश में तबाह होने की स्थिति निर्माण हो रही है। असम में भी यही प्रयास किया गया था, लेकिन वहां का प्रयास फंस गया। वहां इन्होंने प्रयास किया कि असम के विद्यार्थियों का जो संगठन था उसको तोड़ो और अल्पसंख्यक मुसलमानों के भरोसे चुनाव लड़ो, वहां पर सरकार बनाने का काम करो। नतीजा क्या हुआ हजारों लोगों की हत्यायें हुयीं, हजारों लोग मारे गये, मामला और ज्यादा बिगड़ गया, क्योंकि जो मारे गए, उन्होंने कहा—हमें बली का बकरा बनाकर तुम ने गद्दी पाली, लेकिन हम तो मारे गए। जब बात वहां फंस गई तो यहां इस चीज़ को जिन्दा रखकर खड़े हैं। बात बिलकुल सीधी है, हम लोगों की बनाई हुई नहीं है, आपके सामने है। इसको राजनीतिक बनाये बगैर अब इन लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा है और इसके लिए इन्होंने झूठ को चलाया है। कितना झूठ चलाया है—बोलते है कि सिखों की तरफ से यह बात आ रही है कि वे अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं—खालिस्तान। हम यह नाम इन लोगों के प्रचार माध्यमों से सुन-सुन कर हैरान हो गये हैं। खालिस्तान की चर्चा करने वाले लोग हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नहीं हैं, हिन्दुस्तान के भीतर भी हैं और हिन्दुस्तान के बाहर भी हैं, लेकिन वे अकाली नहीं हैं। शिरोमणी अकाली दल नहीं है जो खालिस्तान की चर्चा करता है।

खालिस्तान की चर्चा श्री भिंडरावाला जरूर करते हैं। गृह मंत्री जी उनको अच्छे ढंग से पहचानते हैं और अगर न पहचानते हों, तो कम से कम आपसे पहले जो गृह मंत्री यहां आ कर बैठ गए, उनसे जानकारी हासिल कीजिए कि वे उनको कितने अच्छे ढंग से जानते हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि श्री भिंडरावाला ने जब दल खालसा बनाया, तो उसका पहला पत्रकार परिषद आपके दल के चंडीगढ़ कार्यालय में हुआ था। यह सीधा सा सवाल है और इसका सीधा सा जवाब दीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो भूतपूर्व गृह मंत्री जी से पूछकर जवाब दीजिए और 1980 के बारे में तो भाटिया साहब ने कबूल ही किया है और इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कबूल किया है कि जब मैं अकालियों के खिलाफ लड़ा, तो हम लोगों को उनसे मदद मिली।···(**व्यवधान**)···

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उन्होंने यह नहीं कहा था।···(**व्यवधान**)···

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप रिकार्ड उठाकर कल देख लीजिए। वे यह बोले हैं। वे बोले तो हैं लेकिन जो उन्होंने बोला वह बहुत कम बोला।

SHRI GIRDHARI LAL VYAS : He is making a wrong interpretation.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can speak when you get your chance.

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उपाध्यक्ष जी, असल में जो गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनाव हुए थे, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि उनमें इन्होंने भिंडरावाला जी की मदद ली थी और क्या उनकी मदद से वहां पर इन्होंने अकालियों को हराने की कोशिश नहीं की। मैं यह कहना चाहता हूं कि खालिस्तान की मांग उनकी तरफ से होगी लेकिन अकालियों की यह मांग नहीं है। अगर कोई शब्द लोंगोवाल कह जाएं और 'कौम' शब्द का इस्तेमाल वे कर जाएं, तो इसका मतलब नेशन से ले लिया जाये, यह मैं समझता हूं ठीक नहीं है। पिछले सत्र के आखिरी दिन जब इस विषय पर चर्चा हुई थी, तो उस समय मैं मौजूद नहीं था लेकिन जो चर्चा हुई थी, उसको मैं देख रहा था और मंत्री जी ने क्या कहा, उसको भी मैंने

देखा है। उस चर्चा में श्रीमती गुरबिन्दरकौर ब्रार ने जो भाषण दिया, उसको मैंने पढ़ा है। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं भी सिख कौम के लिए उतनी ही प्राउड हूं। जितनी कुर्बानियां सिख कौम ने दी हैं, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं दी हैं और आगे भी वे देती रहेगी। उन्होंने जो उस वक्त बोला था, वह ठीक बोला था और मैं उसकी तारीफ करता हूं लेकिन अगर कोई उसके लिए यह कहे कि श्रीमती गुरविन्दर कौर ने अलग राष्ट्र की चर्चा इस सदन में की है, तो कितना जुल्म उन पर होगा। 'कौम' शब्द का इस्तेमाल राष्ट्र के लिए नहीं किया गया।

MR. DEPUTY-SPEAKER : She is going to be the next speaker.

SHRI GEORGE FERNANDES : Please don't disturb me.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am not disturbing.

श्री जार्ज फर्नान्डीस : 'कौम' शब्द का इस्तेमाल अनेक जगहों पर इस देश में लोग हमेशा किया करते हैं। इसका इस्तेमाल वे राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि जाति, बिरादरी आदि के लिए वे करते हैं। अब अकालियों को मारना है और क्योंकि देश के लोगों को गुमराह करना है, तो इसको एक प्रचार का माध्यम आपने बना लिया है और आप के हाथ में रेडियो, टेलीविजन और अखबार हैं। जैसा चाहा और जिस ढंग से चाहा, आप उनको अपनी बात कहने के लिए और बोलने के लिए मजबूर करते हैं ताकि देश में अकालियों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ एक माहौल इस तरह का पैदा हो। तो एक यह झूठ है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : झूठ शब्द कहना अनपार्लियामेंटरी है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह आप क्या कह रहे हैं। दूसरा झूठ सिखों की राष्ट्रीयता के बारे में हैं···(**व्यवधान**)···यूथ कांग्रेस के होते हुए आप यह सब क्यों कहते हैं। आप तो इसके बारे में जानते हो।

अभी चौधरी चरण सिंह यहां पर भाषण दे रहे थे और उन्होंने जब यह कहा···

श्री अजीत सिंह दाभी (कैरा) : लोंगोवाल साहब जब पाकिस्तान में जाते हैं तो उनसे यह कहा जाता है।···(**व्यवधान**)···

SHRI GEORGE FERNANDES : I am not yielding.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is not yielding. Only when he yields you can say something.

(*Interruptions*)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह तुम्हारा सबजेक्ट नहीं है।

SHRI AJITSINGH DABHI : What he has been saying is incorrect.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is not yielding, Mr. Dabhi and whatever you ask he will not reply. You can ask your other speakers to reply to that.

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जब चौधरी चरण सिंह साहब बोल रहे थे, तो हमारे कुछ मित्र उनके किसी वाकये को लेकर एतराज करने लगे और बाद में मेरे बहुत लायक दोस्त जब भाटिया साहब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सिखों के पेटरियोटिज्म के बारे में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।

और वे शब्द इस्तेमाल करते हुए उन्होंने चौधरी साहब के किन्हीं वाक्यों पर आक्षेप करने का प्रयत्न किया। अब चौधरी साहब परेशान हो गये। हमने उनसे कहा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। उस पर हल्ला भी हुआ।

भाटिया साहब ने चौधरी साहब का जिक्र किया है। उनकी अपनी ही एक बात थी जो कि उन्होंने इसी सदन में जब पंजाब के मसले पर आखिरी बार बहस 9 मई, 1983 को हुई थी उस समय कही थी। मैं भाटिया साहब के दो-तीन वाक्य पढ़कर सुनाता हूं—

"हकीकत यह है कि 1980 में चुनाव हुए, उनमें 13 एम०पीज० जो जीत कर आए उनमें 12 कांग्रेस आई के थे और केवल एक अकाली दल का था।"

फिर उन्होंने इस बात को यहां पर दोहराया। "जो 12 कांग्रेस आई के जीत कर आए थे उनमें 10 सिख भाई थे जो कि देश भक्त थे, जिनको···"

आप इस बात को सुनिए, यह बहुत गंभीर मामला है। चूंकि सिखों की देशभक्ति पर बहस की जा रही है इसलिए भाटिया साहब की बात को सुन लीजिए। भाटिया साहब कहते हैं—

"12 कांग्रेस आई के जीत कर आये, उनमें 10 सिख भाई थे, जो देशभक्त थे।" उनको उन्होंने देश-भक्त माना—"जिनको देशभक्त लोगों ने चुनकर भेजा।" दूसरी तरफ असेम्बली में 117 सीटों में से अकालियों को सिर्फ 37 सीटें मिलीं, मैजोरिटी कांग्रेस आई को मिली। मेजोरिटी में हमारे देशभक्त जीत कर आये।" पंजाब में इस पर हल्ला हो रहा है। कांग्रेसी देशभक्त, कांग्रेस को वोट देने वाले देशभक्त, कांग्रेस के नाम पर जीत कर आने वाले देशभक्त। कांग्रेस के विरोध में वोट देने वाले, कांग्रेस के विरोध में जीत कर आने वाले लोगों की देशभक्ति पर आक्षेप किया जा रहा है। आज इस सदन में इसका खुलासा होना चाहिए। चौधरी साहब जब बात कर रहे थे और उस वक्त इस झूठ को चलाने की बात की जा रही थी।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Fernandes...

SHRI GEORGE FERNANDES : I have just started, Sir. I am speaking in this House after six months.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Why can't you listen to me ? There are many speakers. Please listen to me, Mr. George. (*Interruptions*) Your Party has been allotted certain time. There are many more speakers from different parties. Your Party has been allotted 14 minutes ; you have already taken 18 minutes. You must decide yourself. How much time do you require now ?

SHRI GEORGE FERNANDES : I won't take all the time. Don't interrupt me. The other speaker spoke for half an hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You started at 5 p.m. It is now 5.20. Now be brief and conclude. Every other leader must speak.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : He will take 15 more minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You sit down. He is the Member concerned. I have got so many leaders to cell. They cannot wait for a long time. We have fixed the time. You cannot take all the time of the House. Therefore, be brief and conclude.

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अब तीसरा झूठ है जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि स्टीफन साहब बोलने वाले हैं। वे शायद बाद में बोलेंगे। अभी वे कुछ दिखा रहे थे और दिखाते हुए मदारी के खेल की तरह बार-बार कह रहे थे कि "इसको देखो, इसको देखो !

अब मेरे पास प्रकाश सिंह बादल, जिनका नाम अनेक बार यहां लिया गया है, उनका जवाब है। यह पत्र उन्होंने तमाम संसद सदस्यों को भेजा था। 3 अगस्त 1982 का पत्र है जिसको अब एक साल होने जा रहा है। पता नहीं कितने लोगों ने उनके पत्र को पढ़ा है।

Leader of the Opposition of the Punjab. This letter is dated 3rd August, 1982. It says as follows :

"I feel that the time has come when the position and demands of the Akali Dal should be clarified once again. It is unfortunate that despite the fact that the Shiromani Akali Dal has been explicit and clear about these demands yet there has been confusion created by interested quarters that Akali Dal demands are communal in content and will disturb the communal harmony of State, strengthen the hands of extremists and encourage separatist tendencies. It is in this context that I feel it necessary to write to you in the midst of Akali Dal's struggle for the attainment of its objectives.

Salient and more important demands of the Akali Dal are as under :—

Political demands

1. To restore Punjabi speaking areas, including Chandigarh to Punjab.

2. To get due share of the river waters on the principle of law, equity and justice.

3. More autonomy and powers for the States throughout the country in accordance with the real Federal set-up.

4. Introducing Punjabi as a second language in Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Ganga Nagar area in Rajasthan, etc. in view of large Punjabi speaking population of these areas.

5. Stoppage of ejectment of Punjabi settlers in Terai area of U.P. and from Haryana.

6. Release of innocent persons arrested so far and stoppage of police repression in Punjab.

Religious demands

1. Enactment of All India Gurdwaras Act.

2. Setting up of Broadcasting facilities for Gurbani Kirtan from Golden Temple.

3. Grant of holy city status to the city of Amritsar and banning the sale of liquor, tobacco and meat within the walled city of Amritsar.

4. Non-interference in the religious affairs of the Sikhs by the Govt. and its henchmen.

"The above demands no where spell out any communalism or parochialism. These demands are for the general interest of the Punjabis as such and are in the national interest for the welfare of the entire country.

The religious demands are such that relate to the Sikhs only and in on way encroach on the rights of others or hurt their feelings."

मैंने उनको जवाब दिया। वे जेल में बंद थे। उन्होंने जेल से अपने हाथ से चिट्ठी लिखकर भेजी। 18 अगस्त की चिट्ठी है जिसका एक वाक्य मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

This letter is dated 18th August, 1982. It reads as follows :

"I may add that the Press is not giving true picture about the demands of Akali Dal. I assure you once again that none of our demands is against any religion or against our beloved country, for which we are always ready to make any sacrifice."

23 अगस्त को सन्त लोंगोवाल ने मुझे पत्र लिखा है। जो पत्र मैंने श्री बादल को लिखा था वह उन्होंने लोंगोवाल को भेजा। उनका जवाब पढ़ूंगा—

"I would like to emphasise that the Akali agitation is in no manner connected with extremism or any separatism. We stand for the unity and integration of the country. Our tradition and record has always been to give lead for patriotic sentiments. Our faith in democracy is deeprooted.

"Our demands are divided into four parts : (A) Religious (B) Territorial (C) Political and (D) Economic. Part A is connected with Sikh people only where we seek religious freedom and non-interference by the Government in religious affairs of the Sikhs. The second demand is connected with the Punjab as a whole. On the economic sides our major issue apart from other things is to provide justice on the distribution of river waters to the State of Punjab. We want this to be referred to the Supreme Court for final decision."

This is for your information, Mr. Stephen, because you talked about it just now. Then it reads further as follows :

(D) Finally we want a real federal system of Constitution with more autonomy to the States.

इन लोगों को ऐसा बदनाम किया है। "चेंज देयर पोजीशन" कौन पोजीशन चेंज करता है। पोजीशन आप चेंज करते हैं, आपकी पार्टी और आपकी सरकार चेंज करती है। 14 जुलाई का गृह मंत्री जी का भाषण है—

Then there is another letter from the Press Information Bureau, Government of India, dated 14th July, 1983. It reads as follows :

"The Union Home Minister, Shri P.C. Sethi has reiterated that the Government has been keeping the doors open for negotiations with the Akalis regarding their demands."

It further reads as follows :

"The Government are making earnest efforts to amicably settle the remaining two demands regarding the sharing of Ravi-Beas waters and territorial disputes."

आपके महामंत्री, जिनके बगैर आपका दल चल नहीं पाता, जिनको बनाने के लिए आप सब लोग क्या-क्या कर रहे हैं। भोपाल से, रोहतक से खबरें आती हैं। वे क्या कहते हैं—

UNI adds—dated 13th July—Mr. Gandhi said, "Akali agitation had been launched with a view to grabbing political power and not for fulfilment of certain demands."

"...Akali demands could not be accepted."

Who is changing the position ? Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee or your Party and your Government ? Are you speaking with one voice ? Have you ever been able to speak with one voice ?

शर्मा जी बोल रहे थे। तब दोस्तों ने उनसे सवाल पूछा था कि आप क्यों पंजाब में एक जबान बोलते हैं और हरियाणा में दूसरी। उनको आप छोड़ें। यहां इस सदन में आपका जो हाइएस्ट लवेल और पौलिटिकल आथोरिटी है और पार्टी आटोरिटी है वह दो जबान बोल रहे हैं और बदनाम कर रही है अकालियों को। कुछ तो सीमा होनी चाहिये। यह बताया जा रहा है कि सी० आई० ए० का हाथ है। यह शुरू हो गया है कब ?

At the highest level of your political authority and your Party, you changed.

कांग्रेस पार्टी के महामंत्री रूस में थे। लौट आते हैं। अमरीका से शुरू हो जाता है कि विदेशी हाथ है। भोपाल पहुंच जाते हैं और कहते हैं सी० आई० ए० का हाथ है।

एक और आपके महामंत्री हैं। वह कहते हैं :

On the 3rd of July, Mr. Home Minister, on the 3rd of July, Mr. Deputy-Speaker, *Pravada* the official journal of the Soviet Union or whatever it is called, came out with the story that the C.I.A. is interfering along with Pakistan in the internal affairs of India in Punjab. There was a headline, "U.S. charged with de-stabilising India".

एक अखबार है नैशनल हैराल्ड जहां लोगों को तनख्वाह नहीं दी जाती है। उसको मैं पढ़ता नहीं हूं। लेकिन उसकी कल एक सिलपिंग मैंने उठा ली।

"The AICC (I) General Secretary, Mr. Chandulal Chandrakar"—Do I see him

around ?—"today charged the United States with destabilising India by creating trouble in India. He said, the reason for creating trouble in Punjab was"—This is the most original reason you have discovered, Mr. Chandrakar ; I thought it should go as a humour column of some journal. "He said, the reason for creating trouble in Punjab was that the green revolution had come in the State." You need some grey matter ; not green matter. And, I quote him :

> "The United States is at a loss to understand where it should sell its surplus wheat which it has been selling to India."

यह बयान इनका है। यह पुराने उस्ताद हैं, इसलिए अपने को बचा कर कहते हैं। लेकिन जिन को ये चढ़ाना चाहते हैं वह बेचारे नए लड़के हैं। उनको कुछ जमता नहीं है। वह जाते हैं रोहतक और क्या कहते हैं ?

> "In his 45-minute speech he expressed satisfaction over the peace in Haryana and appealed to the people to remain vigilant. He said the super powers were bent upon weakening the country and asked the students to fight the challenge."

वहां पर पढ़ा देते हैं लेकिन अमृतसर पहुंचते पहुंचते भूल गए। क्या करेंगे ? उन्होंने तो पहले कहा है कि मैंने इतिहास पढ़ा नहीं है,..... पढ़ना है। लेकिन उनको तो इतिहास करना है और कर रहे हैं बेचारे।

"Super Powers !". There are only two super powers. Mr. Deputy-Speaker, I am sure you are aware of this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : If you are aware of it, I am also aware of it. Please conclude now. Half-an-hour is over. Some more speakers are also there.

SHRI GEORGE FERNANDES : I will not take more than ten minutes. Do not worry.

SHRI K.P. UNNIKRISHNAN : He is not referring to ADMK and DMK.

SHRI GEORGE FERNANDES : There are only two super powers. One is called the United States of America and the other is called the Union of Soviet Socialist Republics. And now we are told by the son of the Prime Minister, the General Secretary of AICC (I), the senior pal of all of you, that the two super powers are interested in destabilising the country.

This is not a laughing matter.

Mr. George Shultz was here in this country, the Foreign Secretary of the United States.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Was this matter taken up with him ?

SHRI GEORGE FERNANDES : Was this matter taken up with him ? He was here on the 30th of June. The Prime Minister had sixty minutes, alone with him, in the first instance, and thirty minutes along with the aides. Then, in an unprecedented gesture, according to the national Press, the Prime Minister invited him to a Private Tea next day where her son also was present. And, Mr. George Shultz and his wife and the Prime Minister and her son had a private tete-a-tete with them.

What happened during those second 60 minutes, first 60 minutes and 30 minutes apart from the meeting of the India-United States Joint Commission, which was presided over by the co-Chairmen, Mr. P.V. Narasimha Rao and Mr. George Shultz, Secretary of the United States of America ?

क्या यह सवाल छेड़ा गया, उनसे पूछा गया, क्या उनको बताया गया कि हम लोगों को यह खबर मिली है रूस से या कहीं और से, या आई० बी० से या गृह मंत्रालय से कि आप लोगों का हाथ है पंजाब के मामले में ? नहीं। उनकी इतनी तारीफ होती है अखबारों में कि वह कहने लगते हैं कि हमारा तो यहां आना अपेक्षा से ज्यादा कामयाब हो गया। और अपने जाइन्ट स्टेटमेंट में कहा :

> "Both the Minister of External Affairs of India, Shri P.V. Narasimha Rao and the Secretary of State of

the United States of America, Mr. George Shultz expressed their satisfaction with the mutual benefits accruing from the expansion and strengthening of contacts between the United States of America and India and the contributions such contacts make to Indo-US relations."

This is of 30th June. Here is your record. And then you speak with another mouth, Mr. Chandrakar and that non-history reading and only history making Joint Secretary of yours gets into a hysteria. He goes round the country and says CIA and Pakistan...(*Interruptions*)

SHRI C.M. STEPHEN : Why are you angry about CIA ? (*Interruptions*)

SHRI GEORGE FERNANDES : Mr. Stephen, we know your capacity. The point is that if your Government and that is the Government of India believes that the visit of Mr. George Shultz was the most nicest thing that had happened... (*Interruptions*) I am not yielding. If Mr. George Shultz's visit was the most nicest thing and you say it under your joint signatures, then after 7 days you go on telling the world that CIA is having roots in this country. I would like to know : is the Government of India... (*Interruptions*)

SHRI C.M. STEPHEN : When he has drawn my attention and mentioned my name I have the right to reply. (*Interruptions*) He has to yield because he has mentioned my name. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will allow you to clarify the position after he finishes his speech, because your name has been mentioned here.

श्री जार्ज फर्नान्डीस: यह जो सी०आई०ए० का मामला हुआ, इसके पहले इन लोगों ने लीबिया पर आरोप लगाया था, लन्दन से खबरें भेजी थीं कि लीबिया इसमें इनवाल्वड है। बाद में गदाफी ने एक दम दिया कि हमारा नाम लिया तो खबरदार, तो डरके मारे फिर उनका नाम नहीं लिया। बदनाम करेंगे अकालियों को, सिखों को, आन्दोलन को और विरोधियों को, सी०आई०ए० पाकिस्तान, लीबिया को। पता नहीं अब और किसका नाम खोज रहे हैं।

इसलिए मुझे इस सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है, न थी, और न आज है। लेकिन जो सवाल है पंजाब का इसका हल होना जरूरी है, और जो 3 मुद्दे हैं अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून के बारे में जो 7 गुरुद्वारों की तरफ से आपको प्रस्ताव आया है उसको कीजिए, देर न कीजिए। कानून के मामले में जो विरोधियों ने 16 दलों की मीटिंग बना दी उसको स्वीकार कीजिए, जमीन के मामले में, जो भी सिद्धांत को बनाकर उस मसले को हल करना है उसको कीजिए। विलेज, कंटिगुइटी, या भाषा का आधार हो उसको स्वीकार कर लीजिए और इन तीनों समस्याओं को हल करते हुए हरियाणा की जो समस्या है पानी की, जमीन की और राजधानी की···

हरियाणा के मामले को भी हल करने का काम आपको करना होगा।

(व्यवधान)

मेरा आपके और आपकी सरकार के ऊपर रत्ती भर विश्वास न होते हुए भी, मैं इसलिए अपेक्षा करता हूं कि आप कुछ अक्ल दिखाकर कुछ राष्ट्रीयता दिखाकर, कुछ देश के हित को दिखाकर मसले को हल करोगे।

कुछ इतिहास बहुत पुराना नहीं, नजदीक का इतिहास मुझे याद आ रहा है। मैं चाहूंगा कि एक किताब आप पढ़ें गृह-मंत्री जी। किताब का नाम है, "लिबरेशन वार", इसके लेखक हैं सरकारी अफसर श्री के० सुब्रह्मण्यम, जो आपकी इंस्टीट्यूट आफ डिफेंस स्टडीज के डायरेक्टर हैं। बंगला देश के आजाद होने के बाद लिखी हुई यह किताब है, लम्बी किताब है और इसके को-आथर हैं मोहम्मद अयूब, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, स्कालर हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप

इसको पढ़िये। यह दूर का इतिहास नहीं है, आजादी के समय का इतिहास नहीं है कि क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और कहां-कहां ? क्या हुआ था लीग और कांग्रेस के रिश्ते में और क्या वायदे हुए थे ? क्या लखनऊ पैक्ट हुआ था क्या तोड़ा गया था, वह इसमें नहीं है, बल्कि ताजा इतिहास है क्योंकि वह इतिहास बंगला देश का है।

आज देश के सामने जो खतरा है, उसमें ये परेशानियां मुझे नजर आ रही हैं। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, संभव भी नहीं है, मगर मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ें। मैं सिर्फ दो वाक्य इसमें से पढ़कर अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

यह जो एक्सट्रीमिस्ट और माडरेट की वहम आप चला रहे हैं, मैं शेख मुजीबुर्रहमान को बरसों से जानता था।

Shri Mujib-ur-Rehman was a moderate, he was not an extremist. Prof. Ranga you would be knowing it.

मुजीबुर्रहमान की मांग बंगला देश बनने के पहले बंटवारे की नहीं थी, आजाद देश की नहीं थी। मुजीबुर्रहमान ने मांग की थी आर्थिक, भाषा, की, मामूली मांग विकेन्द्रीकरण की, देश के विघटन की नहीं। उनका मैनिफैस्टो, उनके सिक्स-प्वाइन्ट प्रोग्राम, उनका पूरा इतिहास पाकिस्तान की राष्ट्रीयता का था।

इसमें लिखा है कि जब भुट्टो बम्बई कालेज में पढ़ता था, याहिया खां एक मामूली कर्नल था हिन्दुस्तान की सेना में, तब शेख मुजीबुर्रहमान मुस्लिम लीग का एक महान नेता, बहुत बड़ा नहीं तो साधारण नेता, के रूप में ऊपर आ चुका था।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Don't forget to read those those two sentences...

(*Interruptions*)

I have only reminded him to read the two sentences. He took the book but he did not read.

SHRI GEORGE FERNANDES : Sir, your are a man with no memory at all.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Thank you. you opened the book and said you will read two sentences but you are going abroad. Therefore, I have reminded you...(*Interruptions*)

SHRI GEORGE FERNANDES : Sir, whatever may be our other views ; we respect you...(*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : You read those sentences, that is what I am saying. There are so many other speakers also. You have already taken 40 minutes.

SHRI GEORGE FERNANDES : I will read those. This book is written by Mr. Subramaniam, a man who advises your Government on defence matters, a man who advises your Government on subcontinental matters. He says :

> "If the army and the People's Party leader Zulfikar Ali Bhutto had permitted the political developments to take their normal course, Sheikh Mujib-ur-Rehman would have saved the unity of Pakistan."

मगर उससे ज्यादा खतरनाक जुमला जो उन्होंने लिखा है, वह सुनिये—

I quote Mr. Subramaniam, an Adviser to this Government on defence and external matters :

> "Various minorities in Asian countries who feel aggrieved that their cultural identities are not being adequately safeguarded and that they are not being offered adequate opportunities for participation in the decision-making at the national level and who are victims of economic injustice and feel that they are discriminated against, are all likely to derive inspiration from the emergence of Bangladesh and the Indian political model."

तो बात तो साफ है, इसको समझ लीजिए। यह मत बोलिए कि बहुत फर्क है।

यह मत बोलिए कि पूर्व पाकिस्तान जो था और पंजाब का जो मसला है दोनों में बहुत फर्क है। इतिहास और क्रांति विचार को चौखट में बिठाकर नहीं होती है, भावनाओं से जो बातें उमड़ आती हैं उससे उनका निर्माण होता है। इसलिए समय अभी भी है, गृह मंत्री जी, हालांकि मैं चाहता हूं कि आप की सरकार आज ही चली जाए। लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत लोग इस्तीफा नहीं देंगे, शायद आंध्र के लोग दें, लेकिन बहुत लोग नहीं देंगे इसलिए आपकी सरकार रहेगी··· (**व्यवधान**)···आचार्य जी, आप भी रहेंगे; जब तक वह बोलेगी, आप लोग रहेंगे, लेकिन जब तक समय है तब तक इस मसले को हल कीजिए।

एक बात और कहकर मैं समाप्त करता हूं William Penn, a very distinguished citizen of the world,

उन्होंने लिखा था :

> "Democracy dies in the hearts of the democrats before it dies at the hands of the dictator."

...(**व्यवधान**)...

कहीं आने वाली हम लोगों की पीढ़ी ऐसी बात न कहे कि हिन्दुस्तान में इस देश की एकात्मता पर जिन लोगों को विश्वास था उन लोगों के ही दिल में इस देश की एकात्मता पहले खत्म हो गई और उसके बाद उसको खत्म करने में वह लोग आ गए जिनको कि एकात्मता पर कभी भी विश्वास नहीं था।

इन शब्दों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि इन तीनों मसलों पर गृह मंत्री जी फैसला करने में अब विलम्ब नहीं करेंगे। गुरुद्वारों में कौन बैठा है, वहां आग किस ने लगायी ये सब बातें गौण हैं इस बहस के लिए। पहले समस्याओं को हल करना बहुत जरूरी है। समस्या को हल करिए। हम लोगों का सहयोग है आपके बावजूद, आपकी प्रधान मंत्री के बावजूद हम लोगों का सहयोग रहेगा इस मसले को हल करने में।

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर (दुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने मेरे सम्बन्ध में दो-तीन बातें बहुत स्पष्ट कही हैं इसलिए मुझे खुशी है कि मुझे कुछ कहने का मौका मिला। इसमें तो कोई शक नहीं है, वैसे संसद की कार्यवाही को गैलरी से 1947 से मैं देखता रहा हूं और सभी काफी दिनों से यहां से देख रहा हूं। इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं···(**व्यवधान**)···

1967 से तो बहुत अच्छी तरह से देखा है और इसमें तो कोई शक नहीं, यह मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं कि जार्ज फर्नान्डीस बहुत अच्छे नाटककार हैं। अपने नाटक को पेश करने में बहुत माहिर हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। एक अच्छे वक्ता हैं। अच्छे वक्ता होकर के लोगों को गुमराह भी करते हैं। अच्छे वक्ता होना एक बात है, गुमराह होना और गुमराह करना और बात है। अच्छे वक्ता होने के साथ साथ दूरदर्शिता भी होना···(**व्यवधान**)··· उन्होंने मेरा नाम लिया है, आप याद रखिए··· (**व्यवधान**)···

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please listen to him. Why can't you listen to him ? When he has listened to you, why can't you listen to him ? I have given him an opportunity to reply. This is only a discussion. Why are you worried ? If there is anything unparliamentary, we will remove it. He is replying to the points raised. You cannot object to it. I have given him an opportunity, because his name has been mentioned.

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : आप को संसदीय प्रणाली पर विश्वास है तो आपको मालूम होना चाहिए, जब वह बोल रहे थे तो मैंने हस्तक्षेप नहीं

किया और उसके बाद मैंने उत्तर देना उचित समझा।···(**व्यवधान**)···

मैं यह कह रहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि वह अच्छे नाटककार हैं और कितने किस्म के नाटक उन्होंने किए हैं यह सबको मालूम है। कितनी दफा पार्टी बदली यह सभी जानते हैं। उन्होंने साथ-साथ यह भी कहा हमारे उपाध्यक्ष महोदय के लिए कि उनकी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है। उनकी स्मरण शक्ति जितनी तेज है यह वह देखें। उन्होंने कहा कि यहां ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, ग्रीन रेवोल्यूशन की उन्होंने चर्चा की··· (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हमने नहीं कहा, इस पत्र में छपा है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : पत्र में छपा है उस का उल्लेख आपने किया या नहीं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : नेशनल हैरेल्ड में छपा है।

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : नेशनल हैरल्ड पत्र नहीं है आपकी दृष्टि में ? आप बता दें आप पत्र किसको कहते हैं ? आपने नेशनल हैरल्ड से उद्धृत किया, जो भी कहिए, जिस भी भाषा में कहिए, नेशनल हैरल्ड में छपा है यह कहा।

आपने कहा कि उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कही गई है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आपने कही है या नहीं ? (**व्यवधान**)

SHRI GEORGE FERNANDES : I have only quoted.

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : ये कह दें कि ग्रीन रेवोल्यूशन की चर्चा नहीं की है तो मैं बैठ जाता हूं। एक संसदसदस्य के लिए मैं यह तो नहीं कह सकता कि आप झूठ बोलते हैं लेकिन सत्य से परे है। (**व्यवधान**) ग्रीन रेवोल्यूशन की बात जो कही है···(**व्यवधान**)

SHRI GEORGE FERNANDES : It is said that the reason for creating troubles in Punjab over the Green Revolution...

(*Interruptions*).

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि देश ने तरक्की की है जिससे ये घबरा गए हैं।···(**व्यवधान**)···

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is all right, Mr. Chandrarkar. Please complete it. There will be no end. Please clarify your position. That is all. Don't make a speech. There are other people to speak.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is all right. George will manage. Why do you worry ?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Sir, I am on a point of order. You have allowed the hon. Member to speak because...

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, I have not. Mr. Fernandes mentioned his name. So he wanted to give some clarification and I had allowed him. That is all right. Now, Mrs. Gurbinder Kaur Brar may speak.

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Sir, you have not settled the thing. Once the hon. Member is denying the statement...

(*Interruptions*).

श्रीमती गुरबिंदर कौर ब्रार (फरीदकोट) : डिप्टी स्पीकर साहब, आज हम फिर पंजाब के ऊपर बहस कर रहे हैं। पहले भी कई दफा इसके बारे में चर्चा पार्लियामेंट में हुई है लेकिन उस वक्त से आज तक कई चेंजेज हो चुकी हैं।

एक बात तो मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि अप्रैल, 1978 में अमृतसर में अकालियों

(अकाली भी वे जो पुरानी सोच में थे) और निरंकारियों के दरम्यान झगड़ा हुआ। यह 1978 की बात है जबकि अकाली रेजीम पंजाब में था। उसमें 13 सिख मरे थे। तो एक्सट्रिमिज्म की बुनियाद उस वक्त रखी गई जिसको अब आप देख रहे हैं। उसके बाद पंजाब और हरियाणा में पानी का झगड़ा, टेरिटोरियल एरियाज का झगड़ा और बाकी चीजों के झगड़े हुए। प्राइम मिनिस्टर साहिबा कपूरी में गईं और एस० वी० एल०, जिसका जिक्र श्री चिरंजीलाल जी कर रहे थे, उसको खोदने का काम शुरू किया गया। तो उस वक्त जो हमारे अकाली भाई थे जिन्होंने 1977 से 1980 तक कोई बात नहीं करी थी, उन्होंने कहा कि हम कपूरी में मोर्चा शुरू करेंगे। आपको याद होगा उससे पहले श्री जगदेव सिंह तलवंडी ने आनन्दपुर रोजोल्यूशन के बारे में यहां दिल्ली में अपना मोर्चा शुरू किया हुआ था। तो यह जो कपूरी में मोर्चा चला यह कामयाब नहीं हुआ। कुछ लोग कैद हुए लेकिन लोगों से ज्यादा वहां पर पुलिस थी। यह कपूरी का मोर्चा एक किस्म से फेल हो गया।

इधर तलबन्डी रोज सैशन चला रहे थे और अकाली भाई अरैस्ट हो रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निरंकारियों और अकालियों के दरम्यान जो झगड़ा हुआ था, उसमे 13 सिख मारे गए। उसके बाद आपको याद होगा, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, उन्होंने जनरलिस्ट लाला जगतनारायण को मारा और निरंकारियों के गुरु बाबा गुरबचन सिंह को मारा और अभी चौधरी जी कोई मेहता की बात कर रहे थे। इस बात पर भिण्डरावाला के चार आदमियों को अरैस्ट कर लिया गया। जब अरैस्ट किया गया तो भिंडरावाला ने यह नारा लगाया कि मैं अमृतसर से मोर्चा लगाऊंगा। इस मौके का फायदा उठाकर जब अकाली दल ने देखा कि मोर्चा लग रहा है, तो वह भी अमृतसर में आकर ज्वाइन कर गए और जगदेवसिंह तलवन्डी, जो राज्य सभा के मैम्बर भी हैं, उन्होंने भी अपना मोर्चा अमृतसर मे जाकर इकट्ठा कर दिया। ये तीन मोर्चे एक मोर्चे में आ गए। यह है बुनियाद, जो इन्होंने इस किस्म का मोर्चा शुरू किया। एक लाख 50 हजार आदमी अरैस्ट भी कराए। पहले इनको जेलों में रखा और फिर इनको रिलीज किया। इन लोगों ने इकट्ठे होकर 46 डिमांड्स रखी हैं। जैसाकि भाटिया जी ने बताया कि इसमें कुछ रिलीजियस डिमांड्स भी हैं, जोकि प्रधान मंत्री ने स्वीकार कर ली हैं। इसके बाद लोंगोवाल ने एक चिट्ठी सभी संसद सदस्यों को भेजी है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, पढ़ना नहीं चाहती हूं, क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने उसको पढ़ लिया होगा। अब उनकी 12 डिमांड्स रह जाती हैं। जो पहली डिमांड उन्होंने रखी है, वह यह है कि :—

Autonomous status for the State.

Restoration of Chandigarh and the left out Punjabi speaking areas to Punjab.

जैसा कि चिरंजी लाल जी ने भी कहा है :

Application of internationally and even nationally recognised riparian principle for the distribution of Punjab.

इन सब बातों से आप वाकिफ हैं। सेठी साहब ने भी एक पत्र जारी किया वाटर के सिलसिले में। वे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। यह मसला भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी : आप इसके बारे में क्या कहती हैं ?

श्रीमती गुरबिंदर कौर ब्रार : जस्टिस होना चाहिए। न उधर के लोग सफर करें और न हम लोग सफ़र करें। हमने भी पानी लेकर खेती करनी है। अनाज पैदा करके सारे मुल्क को देना है। हरियाणा और पंजाब को 50 प्रतिशत अनाज पैदा करके दे रहा है। मैं यह नहीं कहती कि आप सारा पानी उनका लेकर हमें दे दो। इकानोमिकली सफर करता है पंजाब। यह सारे पंजाब की डिमांड

है। मैं एक बार फिर कहूंगी कि यह अकेले अकालियों की डिमांड नहीं है। हम लोग जो सारे पंजाब में रहने वाले हैं, हिन्दू और सिख, यह उन सबकी डिमांड है।

उन्होंने एक और बात लिखी है, जो मेरे समझ में नहीं आई है :

Granting second language status to Punjabi in the adjoining States of Punjab as provided in the Nehru formula.

आपको क्या तकलीफ है, यदि राजस्थान और हरियाणा में लोग पंजाबी पढ़ने लगें। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।

End to the forcible eviction of Sikh peasants from the States of U.P., Haryana and Rajasthan as is being done in utter disregard of Article 19 of the Constitution of India.

ऐसी कोई बात नहीं हुई ?

किसी को एवैक्यूएट नहीं किया गया—न यू० पी० से किया है और न किसी और जगह से किया है। यह उनकी अपने मन की शंका है, पता नहीं क्यों उन्होंने इसको इन मांगों में रख दिया है।

जहां तक रिक्रूटमेंट का सवाल है—1974 में बाबू जगजीवन राम ने इसको शुरू किया था। उन्होंने कहा कि मार्शल रेस कुछ नहीं है, इसको पापुलेशन बेस पर करो, सब आदमी इसमें आ सकते हैं। इस बात की चर्चा संत लोंगोवाल ने की है और मैं चाहती हूं कि आप इस पर गौर करें।

जहां तक —

Enactment of All India Gurudwara Act on the lines of Sikh Gurudwara Act, 1925—की बात है—इसमें गृह मंत्री जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है। दूसरे मंदिरों और मस्जिदों के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं है तो फिर गुरुद्वारों के लिए ऐसा एक्ट क्यों लगाया हुआ है। इसे आपको देखना है, क्यों किसी की रिलीजस बातों में इन्टरफीअर करते हैं।

जहां तक अमृतसर के होली-सिटी स्टेट्स का सवाल है—इसको तो हम सभी मानते हैं। दुर्गयाना मन्दिर के चारों तरफ, हरमन्दिर साहब के दो सौ मीटर में अगर ये चीजें न लायें तो इससे कौन सा फर्क पड़ जाएगा। हरिद्वार में भी ऐसा नहीं होता है।

जहां तक गोल्डन टैम्पल से ब्राडकास्ट का सवाल है—इन्दिरा जी ने इसको मान लिया था, लेकिन सवाल टाइम का पैदा हो गया। वह कहते हैं कि ज्यादा टाइम दो। मेरे ख्याल में अगर इस तरह से एक-एक को टाइम देने लगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनकी बात हमने पहले ही मानी हुई है।

किरपाण की बात का जहां तक ताल्लुक है—जैसा भाटिया जी ने कहा—6 इंच की किरपाण की बात तो मानी हुई है, लेकिन अब वह कहते हैं कि जिस किस्म की और जिस मर्जी साइज की इजाजत होनी चाहिए। इस डिमाण्ड के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि मुल्क की इन्टीग्रिटी और यूनिटी का ख्याल रखते हुए अगर इसका कोई साल्यूशन हो जाय तो यह समस्या हल हो सकती है और मेरे ख्याल में वह मुल्क के लिए और पंजाब के लिए सबसे बढ़िया बात होगी। बातचीत से मामले को सुलझाने में कुछ देना भी पड़ता है। अगर हम देना न चाहें और लेते चले जांय तो इससे बात नहीं बनेगी। अपोजीशन के भाई भी अगर इस काम के लिए तैयार हैं तो वे भी हमारी मदद करें···

श्री जार्ज फर्नान्डीस : गाली देने के बाद बात कैसे होगी ?

श्रीमती गुरविंदर कौर ब्रार : हम गाली नहीं दे सकते हैं।

जहां तक सेन्टर-स्टेट रिलेशन की बात है, सरकारिया कमीशन बना दिया गया है। हमारे गृह मंत्री जी ने अकालियों को नेगोसियेशन टेबिल पर आने के लिए कहा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब वे इसको क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं।

एक बात मैं आपको और बतलाना चाहती हूं—अमृतसर में, दरबार साहिब में जब से अटवाल साहब का मर्डर हुआ है, देखने में यह आया है कि सुबह और शाम जितने लोग वहां जाया करते थे, अब उनकी तादाद में कमी आई है, वहां पर जो चढ़ावा चढ़ता था उसमें भी कमी हुई है। हमारे यहां जो सिख कौम लफ्ज का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब कम्यूनिटी से है, नेशन से नहीं है।

It does not mean that it is a nation.

एक छोटी सी बात और बतलाती हूं—गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज ने कुछ खत लिखे थे—मुगल बादशाह औरंगजेब को। जब गुरु गोविन्द सिंह जी दक्कन गये तो वहां पर बरार उनके साथ थे। ज़फरनामे में इस बात का जिक्र है—बरार कौम बहादुर है, मेरे पीछे है, इसलिए मैं कैसे हारूंगा। इसका मतलब यह नहीं था कि वह कोई अलग नेशन बनाना चाहते थे।

18.00 hrs.

I quote :

> "Mr. Ganga Singh Dhillon from the USA visited Pakistan in 1978 and was received by President Zia. He was again in Pakistan in April, 1980 and March, 1981 (soon after he had propounded his "Sikhs are a nation" theory at a Sikh Educational Conference in Chandigarh) in November, 1981 and May, 1982."

यह इसमें लिखा हुआ है। मैं जार्ज फर्नान्डीस साहब को एक बात कहना चाहती हूं :

It is not Mr. Bhindranwala who said that they want Khalistan. It was Mr. Ganga Singh Dhillon who said :

यह एक नेशन है और इसका खालिस्तान बनना चाहिए। नेशन की थ्यौरी उसने इन्ट्रोड्युस की है। इस तरह की बात जगजीत सिंह चौहान कहते हैं। अब इसमें आगे यह लिखा हुआ है। यह मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूं :

> "Giani Bakhshish Singh, a former postal employee in Britain advocated unity of action between protagonists of Khalistan and Naxalites and also unity among various Sikh groups following different political ideologies for the limited purpose of achieving a "Sikh homeland."
>
> Some supporters of Giani Bakhshish Singh in Britain said in 1974 that Bangladesh had been formed with India's help and that there was no reason why "Khalistan" should not be formed with Pakistan's help."

इसमें ये दोनों चीजें दी हुई हैं।

जब आपने देखा होगा कि टाइम्स आफ इन्डिया में चार सीरीज निकली हैं और श्री जे० डी० सिंह उनको लिखने वाले हैं। उन्होंने संत लोंगोवाल का इन्टरव्यू लिया है। मैं इसमें से कोट कर रही हूं :

> "Sant Longowal affirms that the Akali demand for autonomy is no different from that made by the C.P.M. Government in West Bengal. Defence, External Affairs, Currency and Communications (Railways and Posts and Telegraphs) should remain with the Centre and other matters should be under the jurisdiction of the State Governments."
>
> About the controversy whether the Sikhs are a separate nation, he says, he has been wrongly reported. He used the word "quom" which had been used in official records since pre-partition days. "Quom" does not mean a nation-State but a community. India has several "quoms."

यह जे०डी सिंह के आर्टीकिल में है। कहने का मतलब यह है कि जो अकाली हैं वे यह नहीं कहते कि खालिस्ता बनना चाहिए लेकिन वे इस चीज को तो कन्डम कर सकते हैं और उनको स्ट्रोंग अल्फाज में इसको कन्डम करना चाहिए ताकि यह जो बीज है, यह बिल्कुल खत्म हो जाए और मुल्क की यूनीटी और इन्टेगरिटीक ायम रहे।

एक दो बातें मैं और कहना चाहती हूं। अमृतसर में जो बिजनैसमैन हैं वे इस चीज़ से परेशान हैं। अमृतसर से व्होलसेल में चीजें बाहर जाती हैं और बाहर से ऐसे ही उनके पास पैसा आता है। अब जब बाहर इस तरह का प्रोपेगेन्डा लोग सुनते हैं, तो उनको घबड़ाहट होती है। इस तरह से अमृतसर में वहां की बिजनैस कम्युनिटी को काफी नुकसान पहुंचता है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में ऐसे बहुत से शरारती लोग हैं, जो हिन्दुओं और सिखों मे तफ़रका डालना चाहते है और इस तफरके का रिजल्ट यह हुआ है कि जालन्धर में, अमृतसर में मलरकोटला में और पटियाला में थोड़े झगड़े हुए और वहां पर कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहती हूं कि पंजाब के जो लोग हैं इन्होंने बहुत ही सेंसीबिल तरीके से अपना काम किया है और इतने प्रोवोकेशन के बाद भी वहां अमनचैन और शांति है। मैं यह नहीं कहती कि वहां कुछ हुआ ही नहीं। वहां पर कुछ केस होते हैं, बम गिराए जाते हैं और कुछ लोगों को घरों से, दुकानों से बाहर लाकर मारा जाता है।

और पुलिस में इतनी डिमारेलाइजेशन है कि सेक्रेटेरियेट में निरकारी को शूट करके वे आराम से पांच सौ कदम गए। उनके पीछे कोई नहीं भागा। आजकल वे आसानी से भागकर जा सकते हैं। पहले तो यह जमाना था कि ऐसी हालत में सारे के सारे आदमी उसके पीछे भाग लेते थे जिससे आदमी कुछ नहीं कर पाता था। इसलिए बात यह है कि गवर्नमेंट और पुलिस को स्ट्रोंग हेण्ड्स के साथ इन एक्स्ट्रीमिस्ट्स लोगों के साथ डील करना चाहिए जिससे कि पंजाब के लोगों को विश्वास पैदा हो जाए कि सरकार हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ बचाएगी। इसके बाद वहां काम नहीं चलने वाला है। ऐसा वहां सारे लोग सोचते हैं।

हमारे पंजाब में एक तरफ पाकिस्तान का इन्टरनेशनल बार्डर है। पाकिस्तान के साथ दूसरी तरफ अफगानिस्तान का बार्डर लगता है। इसलिए वहां पूरी स्टेब्लिटी होनी चाहिए। पंजाबी औरत और मर्द बहुत बहादुर कौम है। जब पाकिस्तान के साथ हमारी 1965 में और 1971 में वार हुई थी तो हमारे यहां से थोड़ी दूर पर टेंक वगैरह: थे। वहां पर बम्बार्डमेंट होता रहता था। लेकिन पंजाब की औरतें इतनी बहादुर हैं कि जैसे ही बम्बार्डमेंट खत्म होता, वे उस इलाके में अमेरिकन कपास चुनने के लिए चली जातीं। इतनी हौसले वाली वे औरतें हैं। ऐसे ही वहां के आदमी हैं। लेकिन उनको सारे मुल्क की हमदर्दी और सपोर्ट चाहिए। हिन्दु हो, मुसलमान हो, सिख हो सबकी मदद पंजाब को चाहिए ताकि पंजाब के लोगों के होसले बने रहें।

यह जो पंजाब का सूबा है और हरियाणा का सूबा है, ये दोनों एक ही हैं। मैं तो दोनों को बराबर मानती हूं। पहले तो पंजाब पेशावर तक था, अब छोटा-सा रह गया है। लेकिन हम सब लोगों की कल्चर तो एक ही है। हम सबकी कल्चरल हेरीटेज एक ही है। इसलिए वहां के लिए जितनी मदद हो सके वह मदद वहां दी जानी चाहिए। मैं यहां सभी भाइयों से कहना चाहती हूं कि अगर किसी हिस्से में कोई चीज हो जाती है तो उससे दूसरे हिस्से भी परेशान होते हैं।

They want to solve this problem with earnest desire.

इसलिए हर प्रोब्लम को साल्व किया जाना चाहिए। अगर किसी भी हिस्से में कोई नुक्स हो तो वह बाकी के हिस्से को भी नुकसान पहुंचाता है।

मैं पूरे इत्मीनान के साथ कहती हूं कि हमारी जो सेन्टर की सरकार है वह पूरे तरीके से इस मसले को देख रही है और आपको पता भी होगा कि कुछ एक्स्ट्रीमिस्ट्स पकड़े भी गए हैं। पंजाब में पीस कमेटियाँ बनाई गई हैं। वहां पर सब जगह के लोग पदयात्राएं कर रहे हैं। फिर भी बीच में कुछ सरटेन चीजें आ जाती हैं, सरटेन लोग आ जाते हैं जिनसे कुछ रुकावट आती है।

चौधरी चरण सिंह जी यहां पर नहीं हैं। मैं चाहती थी कि वे यहां पर होते। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण लोग और खत्री लोग जाटों को पसन्द नहीं करते थे इसलिए बहुत सारे जाट मुसलमान हो गए। मैं बताना चाहती हूं कि यह बात नहीं थी। जिस वक्त वहां पर उन पर जुल्म हो रहे थे तो उस वक्त गुरु गोविन्द सिंह जिनका नाम गोविन्द राय था ने एक ऐसी कौम पैदा की जिसका चेहरा किसी से छिप नहीं सके। उस वक्त लोग जंगलों में रहते थे और हौसले के साथ रहते थे। उनको देखते ही यह पता लग जाता था कि यह सिख है। उन लोगों को यह पता ही नहीं था राज्य क्या होता है, आराम क्या होता है। वे बड़े हिम्मत वाले लोग थे।

दूसरी बात चौधरी चरण सिंह ने सरदार बूटा सिंह के बारे में कही। वे तो सिख हैं। उनके मुँह पर दाढ़ी है, उनके सिर पर पगड़ी है। यह तो साफ नजर आ रहा है कि वे सिख हैं।

यह बात मेरी समझ में नहीं आई। पता नहीं उनके दिमाग में क्या था। वे क्या चाहते थे। अब हैं नहीं वरना मैं उनसे पूछती कि वे आखिर चाहते क्या थे। सच्ची बात तो यह है कि मुझे इस बात का दुख हुआ कि बातों को तोड़-मरोड़कर रखना अच्छी बात नहीं होती। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पूछा और 1857 के गदर की याद करने लगे। चन्द लोगों ने किया होगा। मैं यह नहीं कहती कि मैं सबकी जिम्मेदारी लेती हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारे ही ऐसे हैं। (**व्यवधान**)

हम प्राउड फील करते हैं।

We feel proud. We are Indians and we will remain as Indians and we will defend India.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Before I call upon Mr. Vajpayee, I would say that there are about 15 hon. Members to speak. Now the time is 6.10 p.m I would, therefore, appeal to the hon. Members to be as brief as possible so that I can accommodate all the Members wanting to speak and the Minister also can reply. The House also must be full. Therefore, I leave it to you...

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpur) : When the question as to how many hours are to be allotted for this debate was taken up this morning, there was no time limit fixed. So, the Members will speak as long as they want.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think, you were not in the House...

SHRI GEORGE FERNANDES : You were not here. I was very much here.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Speaker had announced that the Motion would be put to vote at 8 O'Clock. It is there on record.

Now, Mr. Vajpayee. I would appeal to the hon. Members to be as brief as possible. There are 15 Members to speak. I must do justice to all. Nobody should be left out.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस काम रोको प्रस्ताव का उद्देश्य पंजाब की गंभीर समस्या को हल करने में सरकार की विफलता के लिए उसकी निन्दा करना है। प्रस्ताव का उद्देश्य पंजाब में कानून और व्यवस्था की निरंतर बिगड़ती हुई स्थिति के लिए राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लेना है। आखिर समस्या को हल करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है ?

प्रतिपक्ष ने समस्या के समाधान में सहयोग दिया है। क्या गृह मंत्री महोदय इस बात से इन्कार कर सकते हैं ? कुछ दिनों से प्रधानमंत्री के भाषण

इस ढंग के हो रहे हैं जिनसे लगता है जैसे सारी स्थिति के बिगाड़ के लिए प्रतिपक्ष दोषी है। मुझे याद है कि 4 मार्च को गृह मंत्री महोदय ने इसी सदन में कहा था, मैं उद्धृत करना चाहता हूं--

> "I must express my thanks to the leaders of the Opposition in Parliament for their participation and their valuable contribution to the tripartite talks. We will continue to seek solution in that spirit and we will continue to solicit the help and support of the opposition leaders and parties to find out an amicable solution."

लेकिन इन दिनों प्रतिपक्ष के खिलाफ बाकायदा एक अभियान चालू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कहती हैं कि प्रतिपक्ष के नेता जब उनसे मिलते हैं तो कुछ कहते हैं और जब अकालियों से मिलते हैं तो कुछ और कहते हैं। क्या मतलब है इस आरोप का? वे किसी नेता का नाम लेकर बताएं। किस तरह उस नेता ने दोहरी बात कही है, यह स्पष्ट करें। अगर प्रतिपक्ष की ईमानदारी पर शक है तो फिर सहयोग नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने किस तरह के उत्तर दिए हैं? मैं समाचार पत्र से उद्धृत कर रहा हूं :

"Lucknow, 18th May

> To the suggestion of the Janwadi Party leader Chandrajit Yadav that the Akali Dal demands which have not so far been accepted by the Government soould be referred to a Supreme Court Judge, Mrs. Gandhi retorted : how would it look if the entire government was handed over to the court ?"

अभी कांग्रेस के सदस्य कह रहे थे कि वे अदालत के फैसले से बंधने के लिए तैयार हैं।

SHRI BUTA SINGH : Political problems will have to be solved by political parties.

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh) : Now the Punjab Governor also says that it should go to the Supreme Court —both the water and territorial issues.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आरोप लगाया जा रहा है--विरोधी दलों पर कि वे अलग अलग भाषाओं में बोल रहे हैं। गृह मंत्री विरोधी दलों को धन्यवाद देते हैं सहयोग के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री विरोधी दलों की निन्दा कर रही हैं। असहयोग के लिए जब अकाली दल और कांग्रेस सरकार की वार्ता विफल हो गई तो प्रतिपक्ष को उसमें शामिल करने के लिए बुलाया गया। लेकिन जब कांग्रेस सरकार और अकाली दल के बीच पहले वार्ता आरम्भ हुई तो उस वार्ता में प्रतिपक्ष को शामिल नहीं किया गया तो हमारे कांग्रेस के मित्र समझते थे कि यह उनका और अकाली दल का घरेलू मामला है, हम इसको निपटा लेंगे, पंजाब की और पार्टियों को विश्वास में लेने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर बात करने की आवश्यकता नहीं है, मामला हल हो जाएगा। लेकिन जब मामला हल नहीं हुआ तब प्रतिपक्ष के नेताओं को बुलाया गया। मेरे मित्र इंद्रजीत गुप्त जी यहां बैठे हुए हैं और वह यह जानते हैं कि जब यह तय हुआ कि त्रिपक्षीय वार्ता हो तो मैं तैयार नहीं था, मेरे मन में रिजर्वेशन था, मैं असम के अनुभव से सीखा हुआ था। जब बातचीत विफल होने लगती है या जब सरकार अपना मन बना लेती है कि समझौता नहीं करना है तो विरोधी दलों पर दोषारोपण किया जाता है।

क्या यह सच नहीं है कि त्रिपक्षीय वार्ता के परिणामस्वरूप मतभेद कम हुए थे, अकालियों ने यह मान लिया था कि केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों पर विचार करने के लिए जो कमीशन बनेगा उसके निर्माण में आनन्दपुर साहिब के प्रस्ताव का हवाला देने की जरूरत नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि अकालियों ने यह मान लिया था कि हिमाचल पर, हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से पर, राजस्थान के गंगानगर पर वे अपना दावा छोड़ते हैं? क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने मान लिया था कि जहां तक जल के बंटवारे का सवाल

है राजस्थान के साथ जो समझौता हुआ था उसको हाथ न लगाया जाए ? क्या यह प्रगति नहीं है ? सेठी साहब ने स्वयं अपने स्टेटमेंट में कहा था कि कुछ मामलों में प्रगति हुई है और आगे मामलों पर बातचीत करेंगे ।

> "As you know, the Government has been having a series of discussions on the demands of the Shiromani Akali Dal in which some progress has already been made, but some need to be discussed further."

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आज वे कायम हैं इस बात पर ? अकाली कायम है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यही सवाल मैं सेठी साहब से कर रहा हूं ।

सेठी साहब ने अकालियों को वार्ता के लिए पुनः निमंत्रण दिया तो विरोधी दलों को क्यों छोड़ा गया ? आपने संत लोंगोवाल को यह लिखा—मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

> "It would be appropriate to resume the talks directly. I, therefore, invite you to meet me in Delhi."

उस समय विरोधी दलों को विश्वास में लेने की जरूरत क्यों नहीं रही ? अगर आप सीधे बातचीत के जरिये मामला हल कर लें तो हमें बड़ी खुशी होगी । लेकिन अगर आप मामला हल नहीं कर पाते तो अपनी विफलता का दोष हमारे मत्थे क्यों मढ़ रहे हैं ?

आज पंजाब में हालत क्या है ? क्या पंजाब में कोई हकूमत है ? क्या पंजाब में जान और माल की हिफाजत है ? आए दिन लोग मारे जा रहे हैं । हिन्दू—सिख संघर्ष का दुर्भाग्यपूर्ण, भयावह खतरा पैदा हो गया है । पटियाला की चिंगारी किसने लगाई ? हिन्दू सुरक्षा समिति की ओर से पंजाब बन्द का आह्वान करने वाले कौन थे ? हरियाणा में हिन्दू रक्षा समिति क्यों बनाई गई है ? अगर हरियाणा और पंजाब में विवाद हो और हरियाणा की रक्षा के लिए, हरियाणा की बात कहने के लिए कोई समिति बने तो मैं इस बात को समझ सकता हूं । लेकिन हरियाणा के हिन्दू को क्या खतरा है ?

एक माननीय सदस्य : बी० जे० पी० का ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गलत बात है, झूठी बात है । यह खिलवाड़ न करो देश की तकदीर के साथ । एकता, अखंडता कौन नहीं चाहता है ? क्या अकाली दल ने अपने को खालिस्तान की मांग से अलग नहीं किया है ? मुट्ठी भर सिखों को छोड़ कर कोई खालिस्तान नहीं चाहता । सिख देशभक्त हैं । मैंने इंग्लैंड में बातचीत की, यूरोप के कई देशों में, अमरीका में बातचीत की । जो खालिस्तान के समर्थक हैं वह न्यूयार्क में गुरुद्वारे में नहीं जा सकते हैं । लन्दन में गुरुद्वारे में नहीं जा सकते । हर जगह मेरी सभाओं में बड़ी संख्या में सिख आए । मैंने कहा खालिस्तान नहीं बनेगा । उन्होंने कहा कौन मांग रहा है ? हम खालिस्तान नहीं मांग रहे हैं । मगर आज हम हर सिख को शक की नजर से देख रहे हैं । क्या यह उन्हें चुभता नहीं है ? विदेशों में मुझ से सिखों ने कहा हम भारत से प्यार करते हैं, लेकिन जब हम भारत जाते हैं, तो हवाई अड्डे पर हमें शक की नजर से देखा जाता है । पुलिस और कस्टम्स वाले हमें अलग खड़ा कर देते हैं, हमें रोक कर रखा जाता है, हमारे पासपोर्ट की अतिरिक्त जांच होती है । अगर किसी सिख ने कनेडियन पासपोर्ट ले लिया तो क्या हुआ ? पासपोर्ट के रंग से खून का और दिल का रंग नहीं बदल सकता । आज हम क्या कर रहे हैं ? हम जबरदस्ती खालिस्तान की बात कर रहे हैं । मैं दोहराना चाहता हूं खालिस्तान के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा, देश को दुबारा बंटने नहीं दिया जाएगा । मगर कौन बंटवारा मांग रहा है ? हमने एक हौवा खड़ा कर दिया है, और उसका लाभ उठाने की कोशिश की जाएगी अगले चुनाव में । यह देश हित का तकाजा नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं पंजाब में आप स्थिति सामान्य क्यों नहीं कर सकते हैं ? यह ठीक है कि

अकालियों को हिंसा की, हत्या की, आतंकवाद की और कड़ी निन्दा करनी चाहिये। वह निन्दा कर रहे हैं। यह भी ठीक है कि गुरुद्वारों में अपराधियों को शरण नहीं मिलनी चाहिए। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब की पुलिस और वहां का प्रशासन क्या कर रहा है? लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। अटवाल को किसने मारा। उसकी सी० बी० आई० जांच कर रही है। उसका परिणाम क्या है? वह ब्रिगेडियर कौन था? वह आई० पी० एस० अफसर कौन था? जब पंजाब में समझौता होने लगता है तब कोई न कोई ऐसी हत्या कर दी जाती है। कौन है इसके पीछे? पटियाना में जो कुछ हुआ वह जालंधर में दोहराया गया। सोडल मन्दिर पुराना विवाद का स्थान है। मामला अदालत में है। अदालत ने अपने फैसले को रोक दिया है कि वहां कोई नया निर्माण नहीं होगा। वहां 24 घंटे पुलिस का पहरा है। फिर 23 जून की रात में निर्माण कैसे हो गया? बड़ा भारी चबूतरा बन गया, 125 फुट ऊंचा निशान साहब लग गया। पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस पंजाब सरकार के काबू में है? क्या पंजाब का प्रशासन मुख्य मंत्री के काबू में है? सरदार दरबारा सिंह राष्ट्रवादी सिख हैं, मगर प्रशासक नहीं हैं। पंजाब की सरकार जानमाल की रक्षा के प्राथमिक कर्त्तव्य में विफल रही है। "प्रताप" के दफ्तर में बम से भरा पार्सल भेज दिया गया। किसी भी डाकखाने में जांच क्यों नहीं हुई पार्सल की?

'प्रताप' के दफ्तर को पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं। वह पार्सल कर्मचारियों के हाथ में सीधा चला गया। पार्लियामेंट हाउस में मेटिल डिटेक्टर लग रहे हैं। पंजाब में प्रबन्ध नही है। कर्मचारियों ने पार्सल खोल लिया। दो लोग मर गए, जिससे तनाव बढ़ गया। पंजाब की पुलिस ने शोक करने वालों पर गोली चलायी। निहंगों को खुली छूट दे दी। पंजाब में सरकार बदलिए। पंजाब के प्रशासन की सफाई करने की जरूरत है। सरकार के फैसले अपराधियों को पहले पता लग जाते हैं। ऐसे लोग पंजाब के प्रशासन में घुसे हुए हैं जो देश के प्रति वफादार नहीं हैं। उनकी छानबीन कीजिए। पंजाब में कानून और व्यवस्था का जहां तक सवाल है, वह कायम कीजिए, इसमें विरोधी दल क्या करेंगे?

SHRI C.M. STEPHEN : Infiltrators from where ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Mr. Stephen, you did not follow me as to what I had said.

SHRI C.M. STEPHEN : I have perfectly followed.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Not from Bangladesh.

SHRI C.M. STEPHEN : From inside, I know.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं मांग करता हूं कि अगर आवश्यक हो तो पंजाब में राष्ट्रपति राज्य लागू कर दिया जाये। खालिस्तान अमेरिका में नहीं है, अगर खालिस्तान की थोड़ी बहुत भावना है तो आपकी विफलता के कारण पंजाब में है। कड़ाई से निबटिये, फिर जो राजनीतिक सवाल हैं, उनको हल करने के लिए बातचीत जारी रखिए। मगर बातचीत जारी रखने का यह तरीका नहीं है जो प्रधान मंत्री अपना रही हैं।

प्रधान मंत्री कहती हैं कि मैं कौन हूं जो हरियाणा की जमीन दे दूं? वे पूछती हैं कि क्या यह मेरी जमीन है? जब चंडीगढ़ पंजाब को दिया था तो किसका था? जब अवार्ड दिया तो क्यों दिया? यह क्यों नहीं कहा कि अदालत फैसला करेगी। बेरूबारी दिया, तीस बीघा दिया तब वह जमीन किसकी थी?

कौन कहता है कि हरियाणा की जमीन पंजाब को दे दो? मैं समझता था कि सारी जमीन हिन्दुस्तान की है। मैंने पंजाब में भी कहा, हरियाणा में भी कहा कि जब तक चंडीगढ़ हिन्दुस्तान में है, मुझे कोई चिन्ता नहीं है। क्या

कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता कि जो थोड़े-बहुत मतभेद अभी बचे हैं, उन्हें हल कर लिया जाए ? मगर अब सरकार अगर त्रिपक्षीय वार्ता बुलाएगी तो उसमें शामिल होने के पहले मुझे 2 बार सोचना पड़ेगा। हम गालियां खाने के लिए नहीं हैं, हमने ईमानदारी से बातचीत सफल बनाने की कोशिश की है। आज हमारी इन्टैग्रिटी पर आरोप किए जा रहे हैं। मुझे भी संदेह है कि सरकार पंजाब की समस्या को अगले चुनाव तक हल नहीं करना चाहती। सरकार सहयोग नहीं चाहती, संघर्ष चाहती है, सद्भाव नहीं चाहती, तनाव चाहती है। सरकार की नजर राष्ट्रीय एकता पर नहीं है, आने वाले चुनाव पर है। यह सत्ता का खेल कब तक चलेगा ?

मैं अकाली दल से भी एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने 15 अगस्त तक अपनी कार्यवाही करने का फैसला किया है। मैं उसका स्वागत करता हूं, मगर मैं एक कदम आगे जाना चाहता हूं। पंजाब में जो परिस्थिति पैदा हो गई है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने आंदोलन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना चाहिए। हिन्दू और सिखों की लड़ाई इस देश के जीवन में बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी।

कब पंजाब में आग लग जायेगी, कोई नहीं कह सकता। यह तो पंजाब के लोग देशभक्त हैं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता संयम से काम ले रहे हैं, लेकिन बात बिगड़ सकती है। 3 जगह दंगे हो चुके हैं। अकाली दल से मैं अपील करना चाहता हूं, सरकार तो नहीं सुनेगी, इन्हें तो कुर्सी चाहिए, आंदोलन स्थगित करने के बाद हिन्दू और सिख एकता के लिए पंजाब में अभियान शुरू किया जाये।

मैं अकाली दल से कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री से कुछ मत मांगो, जो कुछ मांगना है हरियाणा से मांगो। देश से मांगो। हरियाणा में सद्भाव पैदा करो। प्रधान मंत्री कहती हैं कि 1977 में अकाली क्यों चुप थे ? केवल इसलिए चुप नहीं थे कि उन्हें गद्दी में हिस्सा मिल गया था, गद्दी में हिस्सा तो आप भी देने के लिए तैयार हैं। आप तो स० प्रकाश सिंह बादल को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं।

(व्यवधान)

लेकिन अकाली दल ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। अकाली दल ने कहा कि कोई भी सरकार का परिवर्तन होगा तो उससे पहले 6 महीने के लिए असेम्बली को सस्पेंड करना जरूरी है। आप उसके लिए तैयार नहीं हुए।

आप कहते हैं कि आप गठ-बन्धन नहीं चाहते, आप सरकार में हिस्सा नहीं देना चाहते, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं मगर हमारा कहना है कि हमारे लिए पंजाब का सवाल केवल सत्ता में बंटवारे का सवाल नहीं है।

1977 में अकाली संतुष्ट थे, आज उनमें विश्वास का संकट पैदा हो गया है। यह विश्वास का संकट पैदा हुआ था 1980 के बाद। केन्द्र जिस तरह से चला है, केन्द्र का गृह-मंत्रालय जिस तरह से चलाया गया है, गुरुद्वारों के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का दखल हुआ, और दिल्ली के गुरुद्वारों के चुनाव में जिस तरह से अकालियों की काट करने के लिए भिंडरावाले को बढ़ावा दिया गया उससे अकालियों के मन में एक सन्देह पैदा हो गया है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : आपके राज में गुरुद्वारों के चुनाव हुए थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारे राज में हुए थे तब गड़बड़ नहीं हुई थी।

श्री बूटा सिंह : वाजपेयी जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरी पंजाब सरकार ने आकर

चुनाव अभियान किया था। मुख्य मंत्री आए थे और उनके सभी मंत्री आए थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दिल्ली के ले० गवर्नर ने कालेजों के प्रिंसिपलों को बुला बुलाकर कहा था कि किन उम्मीदवारों के लिए वोट देना। जब मैंने यह आरोप पार्लियामेंट में लगाया था तो ज्ञानी जी ने कहा कि ले० गवर्नर भी एक सिख हैं, भले ही मोना सिख होंगे। (**व्यवधान**)

प्रधान मंत्री ने स्वयं उत्तर दे दिया कि केन्द्र हमारे पास था तो समस्यायें नहीं थीं। अगर केन्द्र में आज समस्यायें हैं तो यह आपकी विफलता है। उस समय गैर जनता सरकारें थीं, कहीं टकराव नहीं था और आज प्रधान मंत्री कहती हैं कि गैर कांग्रेसी सरकारें, गैर कांग्रेसी राज्य केन्द्र से टकराव करने पर तुले हुए हैं। (**व्यवधान**)

क्या राज्यों के लिए अधिक अधिकार मांगना केन्द्र से टकराव करना है? हम भी चाहते हैं राज्यों को आर्थिक मामलों में अधिक अधिकार दिए जायें। अगर यह देश टूटेगा तो क्षेत्रीय दलों के उभार के कारण नहीं टूटेगा, देश अगर टूटेगा तो केन्द्र में जो जरूरत से ज्यादा सत्ता इकट्ठी हो गई है उसके कारण देश की एकता कमजोर होगी।

मैं अकाली दल से एक बात कहने वाला था कि वे सिखों के लिए अलग कौम शब्द का प्रयोग करते हैं। कौम शब्द के प्रयोग पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कौम का अर्थ है कम्युनिटि, उसका अर्थ है जाति। लेकिन वे अंग्रेजी में नेशन लिखते हैं। इससे भ्रम पैदा होता है। आज भी संत लोंगोवाल की जो किताब मुझे मिली है उसमें नेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। हमने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को नहीं माना है, हम बहुराष्ट्र के सिद्धांत को नहीं मानेंगे। मजहब के आधार पर राष्ट्रीयता नहीं चल सकती। मजहब के आधार पर जो पाकिस्तान बना था वह बंट गया, बंगला देश अलग हो गया। ईरान ईराक आपस में लड़ रहे हैं। एक राष्ट्र में अनेक मजहब मानने वाले लोग रह सकते हैं और एक मजहब मानने वाले अनेक राष्ट्र हो सकते हैं। अतः सिख नेशन मानने की बात पैदा नहीं होती है। लेकिन अब अकाली दल ने एक नया ट्विस्ट दिया है, एक नया मोड़ दिया है, उन्होंने कहा है :

> "The repeated affirmations currently being made by the Sikhs that 'They are a Nation' must be seen in this context".

संदर्भ क्या है?

उन्होंने नेहरूजी को कोट किया है। फिर आर्टिकल (25) की बात कही है। कहा है कि सिखों को हिन्दू कहा जाता है, उसके ऊपर हिन्दू पर्सनल लॉ लागू है। अब अकाली दल कह रहा है कि आर्टिकल (25) में संशोधन कर दो और सिखों को हिन्दुओं की परिभाषा में से निकाल दो और सिखों के लिए अलग पर्सनल लॉ बना दो। मैं नहीं जानता सिखों का कोई पर्सनल ला अलग है या नहीं? अभी तक तो नहीं है। अब शायद वे नया पर्सनल लॉ बनाना चाहते हैं। संविधान के डायोक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है कि सारे देश के लिए एक पर्सनल ला होगा, अभी तक वह लागू नहीं हुआ है क्योंकि हम किसी पर जबर्दस्ती पर्सनल ला थोपना नहीं चाहते। लेकिन सिखों के मामले में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सारे समाज का ढांचा और कानून की सारी व्यवस्था इस ढंग से बनाई गई है कि सिख हमारे अभिन्न अंग हैं। अगर आज कोई हरिजन सिख पंथ को कबूल करले तो वह उन सुविधाओं से वंचित नहीं हो जाता जो सुविधाएं हरिजन होने के नाते उसको मिलती रहती हैं। अगर वह इस्लाम को कबूल कर ले या ईसाइयत को कबूल करले या बौद्ध बन जाए तो उन सुविधाओं से वंचित हो जाता है। सिख होने पर वह वंचित नहीं होता क्योंकि हम समझते हैं कि वे हमारे अपने ही हैं, हिन्दू परिवार के अंग हैं। क्या अकाली इस चीज को खत्म करना चाहते हैं?

दूसरा सवाल मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि

एक ही परिवार में एक लड़का हिन्दू है और एक लड़का सिख है।

लड़की सिख परिवार से आई है, लड़का सिख परिवार में ब्याहा है। अगर परसनल ला अलग हो गया, तो क्या परिवार के अलग-अलग व्यक्तियों पर अलग-अलग लॉ लागू होंगे। क्या परिवार टूटेंगे नहीं ? अभी तो उन्हें डर है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि लोग सिख रहना छोड़ दें। फिर कहीं दूसरा डर पैदा न हो जाए कि लोगों को जबरदस्ती सिख रहना पड़े। मेरा निवेदन है कि इसका निर्णय व्यक्ति पर छोड़ देना चाहिए, वह किस मत को मानता है और किस पन्थ को मानता है, यह उसका अपना मामला है। अलग पर्सनल लॉ की बात मुझे थोड़ा सा खटकती है। सिख एक पन्थ है, मैं, उसके सामने माथा झुकाता हूं। उसमें बलिदान की परम्परा लगी हुई है। दुनिया के इतिहास में ऐसे बलिदानों की परम्परा दिखाई नहीं देती। मगर गुरु गोविन्द सिंह जी ने कभी भी अलग होने की बात नहीं की थी। पहले सिख नानक पन्थी कहे जाते थे। गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज ने कहा था—

अखिल विश्व में खालसा पन्थ गाजे।
जगे धर्म हिन्दू सकल भण्ड भाजे॥

आज आइडेंटिटी की तलाश में अकाली कहते हैं कि वे हिन्दू नहीं है। मैं मान लूंगा, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि आप भारतीय तो हैं। इतना ही काफी है। अभी भी पंजाब की स्थिति को सुधारा जा सकता है, बशर्ते कांग्रेस चुनाव पर से अपनी नजर हटाकर समस्या को हल करने पर ध्यान लगाए। मगर मुझे इसकी आशा नहीं है, इसीलिए हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। धन्यवाद। (इति)

SHRI C.M. STEPHEN (Gulbarga) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, at this late hour of the day, I can promise I will be very very short.

We had earlier two occasions when we discussed the Punjab situation. At that time the entire House—the Opposition and the Government—focussed on the question of the Punjab developments. The discussion was not allowed to take diversionary lines at that time. This time the discussion has a different shape. The difference is that there are accusations and counter-accusations as between the Government and the Opposition and as between different elements in the Opposition with the result that the concentration on the Punjab situation has gone to the background.

The questions involved in the Punjab issues have been placed before you by different Members who spoke—both from Haryana and the Punjab. All the points of view—historical and others—are before us. I don't want to traverse the entire ground again.

Mr. Vajpayee pointed out that the Home Minister conceded at a stage that the Opposition was cooperating ; and that now the Prime Minister and the ruling Party are taking a view that the Opposition's conduct and stand are not helpful to the solution of the Punjab issue. He says there is a contradiction between the two. I would only say that both the positions are correct. When the Home Minister said that at the Tripartite Conference cooperation was forthcoming, he was stating a fact. Cooperation at that stage was forthcoming. But subsequently, a new attitude has been adopted by the Opposition and a new position has been taken. Now, therefore, we have come to a stage in which we are constrained to say that the attitude of the Opposition is not only not helpful, but it is creating hindrances for the solution of the problem.

What exactly is their attitude, is the question.

AN HON. MEMBER : Explain how.

SHRI C.M. STEPHEN : Mr. Vajpayee said : if only the ruling party takes its mind away from the forthcoming elections, everything will be all right. The difficulty with the Opposition is that they have only this obsession, i.e. as to how to face the elections. They being subject to that obsession, they think that everybody is labouring under

that sort of an obsession. They do not find the difference between their functioning, and how the Congress, the ruling party, is functioning. They have got their own problems, i.e. as to how to come together, how to create an alternative, how to iron out their differences, how to find a common issue on which they could hang together. So, they look at it that way. They are approaching every issue only in this manner. If only they can forget for a time that Government's approach to this matter and other matters is in terms of elections, they will be able to see the question in a proper perspective.

What exactly is the Government doing ? The first question is whether Government has been active in handling this question in a responsible manner. I have only to refer them to the resolution they passed in the Opposition conclave in Delhi. The resolution elaborately listed the steps that were taken, and the solutions that were ironed out. The resolution stated that as a result of negotiations and all that, this demand was conceded, this was settled, that demand was settled etc. ; and they came to the conclusion that the only two questions which remained were the questions about water and territorial dispute. This shows one fact, viz. that about 34 or 40 demands were put up, and then they were reduced to a smaller number. According to the Opposition conclave in which the Akali party people were present, they came to the conclusion that having settled all demands except these two—this means that they found not a Government which was not working, but a Government which was working—there was a Government which was bringing about a settlement on different issues. So, the Government was a Government which was handling these questions. Religious demands were settled—I am only quoting what they said. I am not making my statement, I am only quoting. (*Interruptions*)

SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR (Trivandrum) *rose.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Are you yielding, Mr. Stephen ?

SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR : The Opposition parties' meeting had put forward some concrete proposals. Why did Government not take action on them ?

SHRI C.M. STEPHEN : I am only handling one particular aspect of it. They should give the devil its due. That is my appeal to them. You can see how the matter was handled. The Home Minister went to Chandigarh, so also the Cabinet Committee to meet the Akali leaders, and finally our request to the Opposition parties was to come and cooperate with us in this matter.

We never stood on prestige. A tripartite conference was held. Certain grounds were covered, no doubt. But what did we came to, at the end of it ? After we found that there was a consensus on certain matters, it was felt that a settlement would not be possible, except in consultation with the Haryana Government, and the Opposition in Haryana. On that note, this tripartite conference adjourned, to call in the Haryana people—the Haryana Chief Minister and the Haryana Opposition.

They were called in ; and a second tripartite conference was held where the Government, the national Opposition and the Haryana political parties and Government were called in. A second tripartite conference was held. I recall this to emphasize the position that at the tripartite conference, the consensus was that with respect to the remaining issues, a settlement will not be possible except after consultation with the parties which was Haryana. Then it came to the question of water. We came to the conclusion that Rajasthan had also to come in. Rajasthan was also called in. Not only the Government of Rajasthan but the opposition parties also came in. Again a tripartite conference, national opposition and the Government of Rajasthan—these were the stages which we passed through. What I am saying is that upto a particular moment, government endeavoured its best to find a solution. Here is with me Mr. Longowal's statement which was distributed among the MPs. The former statements of Congress, Pandit Nehru and Mahatma Gandhi—it has been asserted again and again that those statements of policies were spelt out by the Congress from 1934 onwards. These policies have not been de-

faulted at all. The attitude to the Sikhs remain the same ; the attitude to the minorities remained the same. If the attitude to the minorities and the weaker-sections did not remain the same, the unity of the country could not have been accomplished ; the unity of the country can be had only if you give a sense of security to every segment of the population of this country, big or small. When the sense of security is gone, the unity of the country will be in danger. The sense of security was given with respect to other sections including the North-Eastern belt and, therefore, to a large extent, the unity was there. But the Sikhs' problem was a different problem. Against a historical perspective, you can see that from the days of the Guru downwards ; their perspective is slightly different. Therefore, it has to be handled in a different manner and it was handled in a different manner.

When Shri Charan Singh says, why don't you enforce law and order, why do you allow the criminals in Gurudwaras, why do you not get them out when you are in power, you must understand that this is not the way in which any emotionally explosive issue can be handled ; it has got to be handled keeping in view every perspective and what the consequences are going to be. When a mother handles the conduct of a child, it will be different from the manner in which a stranger handles the conduct of a child. A government has to handle a situation like a mother ; whether it is Shri Morarji or Shri Charan Singh or Shrimati Indira Gandhi, whoever that might be ; the government has got to handle it with a motherly attitude ; it is a difficult handling that is taking place.

We have come to the stage in which the remaining issues cannot be settled bilaterally. Government is not a party to that ; government is only a mediator ; government is only an agency to mediate and implement what can be brought about, what can be ironed out through negotiations ; the government is not interested in Chandigarh being there or here. But there are parties which are interested.

My friends, Shri Bhatia and Shri Chiranji Lal Sharma gave details of the verdict of the Shah Commission. When the Commission's verdict came, we faced another situation. Sant Fateh Singh declares that he will commit immolation. A new situation arises. We could not blind our eyes to the situation. Therefore, that was amended and a new settlement arrived at. The terms of the settlement were that Chandigarh will be for Punjab and Abohar and Fazilka will be for Haryana. Territorial and water disputes will be settled through a commission.

The question is whether the terms were accepted or not. Sant Fateh Singh on the basis of the settlement broke his fast and the whole thing was terminated. Akali Dal was in Government at that time. Akali Dal celebrated the settlement with illumination in whole of Amritsar and the whole of Punjab. So there are two parties to the question. They have got the right. It is not only Punjab but Haryana also has got the rights. We tried to settle it. It was not possible. The opposition friends tried, they failed. We tried, we failed. Tripartite tried but tripartite failed. Mr. Vajpayee says one thing here but his unit in Haryana cannot accept it. Chaudhari Charan Singh says something here but his unit in Haryana cannot accept it.

18.51 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

Janata says something here but their unit in Haryana cannot accept it. They will not accept it. There is a situation in which the national opposition may come together and take a position which they will not be able to sell to their units in Haryana and Punjab because they have got the regional aspirations.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : What about your party ? (*Interruptions*).

SHRI C.M. STEPHEN : My party at the national level is not interested whether Chandigarh must go there or Chandigarh must remain here.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : But you want us to do that ?

SHRI C.M. STEPHEN : We want to settle it. Therefore, we have come to a conclusion that as a united settlement is not possible, the matter will have to be referred to a third commission to give a verdict as to what it should be. When the two parties cannot agree together, a reference to a third party for arbitration is the principle that we have learnt at the feet of Mahatma Gandhi. This is what we said. Then they say : You do one thing ; hand over Chandigarh and the rest of it you refer to that. This is the question that is now before us. Again about water dispute, are they very clear that they will not seek to reopen the settlement with Rajasthan ?

AN HON. MEMBER : No.

SHRI C.M. STEPHEN : No, they have not agreed to it. I may tell you that they will not make a commitment at the moment. They say that they are leaving it open. That is why they say riparian law which means that the entire question beginning from Rajasthan they are seeking to reopen. What is the attitude of the opposition with respect to that ? Settlement is possible only with the concurrence of the interested parties. What is the position of the opposition with respect to that ? These are the questions now before us. When we come to that stage, then we say that we have come to the end of the tunnel. It is clear that a bilateral negotiation is not possible Let us refer the water dispute to a tribunal constituted according to the Act and the other matter to the Commission. Let us refer both of them to find a solution. What is the attitude of the opposition to this proposition ? Would they support it or not ? Would they say : Give Chandigarh to Punjab and with the rest, you do as you choose ? Is it the position that you take ? When you take up that position, then the charge is made that the position you are taking is creating hinderance. It is not helping to solve the problem. It is nothing more than that. We have conceded that you were helpful. I reiterate that you were helpful at the time of tripartite conference. After having done that, you failed, we failed and both of us failed in this particular matter. Therefore, what can be done out of that ? A reference to the commssion is the only way. When it comes to that, you take a negative attitude nnd you go about saying so many things. What are the things that are being said here ? Shri Charan Singh asks us : Why do you not take the hardest line ; why did you create Punjabi Suba ; why did you revive the Shah Commission ; why did you give another verdict ; why did you not use the force ; why did you not force those fellows out of the Golden Temple ? This is fanning one sort of bitterness. Another is, my hon. friend, Mr. George Fernandes, lost his balance when he heard about CIA. I had my doubts as to whether CIA is really operating here. I was not prepared to concede that way. But when I saw Mr. George Fernandes warning himself and started defending CIA, then I saw that there was something in it and it was absolutely clear to me. He goes off from the subject of Punjab. He goes to CIA, KGB and US. That is the objection he is having. My friend Mr. Vajpayee took the position that the two-nation theory or three-nation theory is not acceptable. I must certainly thank him for having taken that open strong position. He has also taken certain other positions. But the question is : if that is so, why is it that they are opposing like that ? Whom are we dealing with ? We are not dealing with one individual or one party but different elements are there.

I do agree that Khalistan is something we need not bother about. But the fact is somebody is going about as Khalistan, that is number one. Number two, there is Bhindranwala. Maybe we brought him, maybe you brought him, whoever might have brought him, he is there. He remains there like a Frankenstein. With arms and all that, that man is remaining there, and he says : I do not say yes, nor do I say no to Khalistan. Bhindranwala, with all the powers that he wields, he does not say no to Khalistan and he says : I do not say yes also to Khalistan. And then there is Longowal saying : yes, we are a separate nation. We want autonomous State everywhere, no quasi-autonomous, no semi-autonomous. Then there are the extremists on whom nobody has control at all Akali Dal says we condemn their activities. The very moment they say so, people are shot down. Either they have no control on these terro-

rist's who are shooting down people or when they say that they do not agree with terrorism they cannot be taken at the face value. If they have no control, then the question is, there is the Khalistan fellow going round, there is the Bhindranwala fellow going round and there is the terrorist fellow shooting about, there is the Longowal statement coming across, there is the Talwandi statement coming across and protesting that he will go ahead, and the Akali Dal resolution asking for an autonomous State and one nation and multi-nation theory. It is this multi-entity that we have to handle there. The question is when you say the *samasya*, the Punjabi *samasya*, the Punjabi question, I am again putting the question, what is the Punjabi question ? Most of the Punjabi question has been solved. The only question that remains is a question in which two or three States are involved. Would you say disregarding the position that the Haryana Government and the Haryana political parties are taking, that we must come across and put the steam-roller across and give the whole thing ? Would any Government do that ? Would any responsible Opposition advise the Government to do that ? That is the question. When that comes, when the Akali Dal takes up that position, are we not to sit up to think as to why it is so ? We have been trying the Government, not only the Government, the national mainstream, I do not say the Congress only, the national mainstream has been trying to handle the emotions, the resistance, the aspirations, the yearning for preserving the identity of the Sikhs in a very sympathetic manner. I do not say the Congress, but the national mainstream has been handling them in that manner and to the farthest extent possible.

19.00 hrs.

It has come to a stage in which it appears either you concede a separate nation proposition, amend the Constitution, split and separate it from the Hindu culture, whatever it might be, with a separate civil law or you say 'thus far and no further'. When it becomes clear that all these contentions about the water, the territory, the kirtan, all these are put up to cover something which is behind, when it comes to that, do we not owe it to the nation to address the question direct and to try to tell them the nation is united on this, thus far and no further ?

Shri George Fernandes took up Shri Rajiv Gandhi's statement and radiculed it. Shri Rajiv Gandhi said that these demands cannot be conceded. All the earlier demands were conceded. What is the present demand ? The present demand is, by-passing the Haryana Government and opposition, by-passing everything, you do this or I kill you. When such a demand comes, we have to say 'No'. That is why Shri Rajiv Gandhi said that these demands cannot be conceded. The demands can be conceded only by mutual consent, by mutual discussion, by mutual consensus, the alternative being an award by a commission. This is what he has stated.

I am repeating the poser to the opposition : do you or do you not agree, as stated in the opposition conclave resolution, that most of these demands were conceded ? That is what you have stated, which means that the kirtan was agreed to ; it means one and a half hours in the morning and half an hour in the evening of kirtanbroadcasting was agreed to ; it means re-opening of the water dispute, not involving Rajasthan but only involving Haryana and Punjab was agreed to ; it means that the framing of Gurudwara Act with consent of congregation in the historic Gurudwara sahebs Act was agreed to. These were the things that were offered. If you accept these are settled, then would the Akali people who participated in the conclave say : we agreed to all these. Or, would you say, along with that, that the Rajasthan dispute must be re-opened, by-passing Haryana we must do this ? Would you say that the Akali Dal has got the jurisdiction to speak for the Sikhs everywhere, it means the Sikhs everywhere, I would like to know. Because, Akali is one thing, Sikhs are different ; the Sikhs are larger than the Akalis. The Akali Dal covers interests which are larger than the Sikhs also. That is the real thing which we have to understand. Punjab does not mean only the Akali Dal ; Sikh does not mean only the Akali Dal ; these interests are entirely different. The Sikhs who are in the different States throughout the country, in the respective States they and the

pride of the people of those States. They are honoured and respected and they are contributing to the welfare of the States to which they are going. They are mingling with the people of those States. They are proud of the past of the Sikh people.

When you say Sikh means a separate nation, then I would like to join issue with Shri Vajpayee and say : thus far and no further, because the time has come when we have got to say that. I would appeal to Shri Vajpayee ; I would appeal to the Akalis that they must completely suspend the stir and then proceed to discussion. The fact remains that the killings are taking place because of the cover given by the *morcha* that is going on.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Not because of that, but because of your incompetence.

SHRI C.M. STEPHEN : May be incompetence, according to you. The police cannot and should not enter the Golden Temple. We would, for the time being, prefer Shri Bindranwale remaining in house arrest there rather than breaking into the temple.

It is the public opinion which has to be created. Would you join with us in creating that public opinion ? Would you join with us in making the demand that criminals must not have a sanctuary in the different temples ? These are the matters on which we have to join hands and create an opinion in this country rather than bother with that thinking that we are obsessed with the elections that are coming. We know perfectly well... (*Interruptions*). Sir, in one minute I am concluding. Mr. George Fernandes said that we are afraid of the elections, our ground is slipping. Well, Sir, we are a political party. I do not want to put up bold claims and all that. Let the things come along. We know what is happening, we are not remaining blind, we know the political pulse of our people and we are very happy that the pulse is perfectly in our favour.

I do not want to enter into any controversy. But I would only say that we are watching the movement, we are feeling the pulse of the people and we find that we are absolutely safely placed and for the Congress the method of boiling up with this Sikh question is absolutely unnecessary, and that crude method I would leave to you. This is all I would say.

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul) : Mr. Speaker, Sir, I am very much thankful to you for coming and presiding over this House at this time.

Sir, while the Punjab problem is burning in the west of the country, the Assam problem is burning in the east of the country, and they 'have contemplated to dismiss the Pondicherry Government'.

Sir, this House has become tired and disgusted with the repeated discussion of the same problem. This is, I think, for the third or the fourth time that we are discussing this problem.

Sir, in 1931 before he was executed, Bhagat Singh, the greatest warrior of this country who fought for the freedom and died for the freedom of our country, threw a bomb in the Central Assembly. He was taken to gallows and at that time, even when he was about to go to the gallows, he told the nation that 'I threw the bomb in the Central Assembly not with the object of killing the Britishers. I threw the bomb to make the deaf people of India to hear and fight for the freedom, to make the blind people of India to open their eyes and fight for the freedom and to make the dumb people of India to open their mouths and raise their voice to fight for the freedom.' In the same manner, these Opposition parties have brought this problem many times repeatedly before this House to make the deaf Government hear about the burning problem of this country and solve the problem, to make the blind Government open its eyes to solve the problem, to make the dumb Government to open its mouth and deliver the goods in the interests of the unity of the country.

Sir, this is the fourth time that we are dealing with this problem here. When I went to the lobby, I found so many people laughed at the Members saying : 'What,

Sir, you are going on discussing about it but no solution is found by the Government'.

There are three States ruled by the Congress (I), namely, Punjab, Haryana and Rajasthan. Of course, excepting in a few States you are in power in all the States, but your Government is unable to face the challenge of the Khalistan. I want to know whether Khalistan is in power or this Government is in power. Are they not ashamed to hear the challenge of the Khalistan leaders who appealed to the military—because many Sikh people are in the army—to revolt against the Central Government in support of their demand, as if we are against the unity of India and as if we are against the welfare of the country ?

We are for unity in diversity. We are for non-violence and not for violence. We are for peaceful settlement. We are not for fighting and eating the flesh and bones of our own brothers. We do not want bloodshed. We do not want shooting. We do not want to kill our own brothers. One Sikh gentleman has killed D.I.G. He was also his own brother. A family man has in other words killed another family man, his own man.

A journalist has said that Shri Rajiv Gandhi has pointed out that U.S.A. Government is interfering in this matter. I want to ask the Government of India and the Home Minister whether you have registered a strong protest if there is interference. This has been pointed out by very senior leader of the House and the country that there is outside interference. Why do you not hear all this ? You are just shifting the blame on the opposition. I want to know are you in power or are we in power ? Who is in power, please tell me ? On what moral or legal aspect or grounds are you shifting the entire burden on the opposition parties ? We are not Prime Minister, Home Ministers, Chief Ministers. We are only opposition parties, voicing the people's mind here, just representing that with brain and tongue. Government is having more power—police power. Why do you not solve the problem ? You have been having this problem from 1969. The statesman always thinks of next generation. The real statesman interested in the welfare of the country and future generation will plan for future generation. Petty politicians think of the next general election or by-election. You are concerned with the next general election. You always think whom you can purchase, with which party to have alliance, how much we can pay, how much conflict we afford to commit so that we may remain in power. We should be in power is all that you are always thinking. You are always applying your mind in this regard. I am not blaming any particular individual. I am making a charge against the entire Government collectively. You have failed in your duty by not solving the problem of Punjab. You have not solved Assam and Punjab problem. You have not touched farmers problem, Government employees problem, working class problem. You have touched nothing except your pocket. That is what I can say. Women's problem is there. Dowry problem is there. How many suicides are being committed. How many brides are being burnt by their husbands. You have not brought any comprehensive legislation. You are always thinking of the next general election. That is very bad. Election is not so important.

We are against multi-nationals. We are not for separation or division of the country. We are a nation. There should not be any further division of the country. We are brothers and sisters. There should not be any division. There are no two opinions on this matter. Is it not your duty to put your head and lay your hands to solve the problem ? Have you applied your mind to solve the problem ?

Sir, we have got great respect for the temples and gods. We accept gods and religions. What for we are having gods, temples and religions ? They are all for the welfare of human beings and for the welfare of men and women. Therefore, when a temple is against the interests of the country when a temple is against the security of the country and when the Golden Temple or any temple for which we are having great respect is giving protection to all the criminals, murderers, robbers, anti-social and anti-national elements,

is it not your police duty and military duty to raid and arrest all those fellows ? Did you do it ? You have not done it because you are afraid of the next elections ; you are afraid of losing their votes. You have not cared for the unity of the country. That is my charge.

Sir, all the Opposition Parties are cooperating. Can you cite even a single instance of non-cooperation of the Opposition Parties in this matter ? Can you say any statement which is repugnant to the solution to this Punjab problem ? No. Everybody is cooperating. Everybody is ready to cooperate. But you are not willing to cooperate with the Opposition Parties. You are not willing to solve the problem. Therefore, this is too late for the Government to bring a solution to this problem.

Sir, I recommend to the Government that the reasonable religious demands may be accepted ; reasonable, social and communal demands may be acceded to by the Government. But the political demands against the interest of the country should not be accepted. When there is a fight between Khalistan and India, the interests of India should be protected and not the Khalistan's interest. Therefore, whatever may be the result, you must lay your hands and apply your judicious mind or non-judicious mind or whatever mind in the matter to solve this problem. Sir, my respected friend, Mr. Stephen was very strong—he is always very strong—in his speech without any substance. He was the Telephone Minister. Unfortunately, telephone is now partly working. At the time when he was the Minister, no telephone throughout the country was working. For instance, my own telephone at Madras was always getting wrong numbers. He was confessing before this hon. House that the problem can neither be solved unilaterally or bilaterally. Then, what kind of "laterally", he can solve this problem ? I do not know how he will solve this "laterally" or "literally". It is better to refer the demands of the concerned parties to the Supreme Court. Don't you have faith in the Supreme Court and the High Courts ? If you have confidence in the judiciary, you can refer it to the court for a just, reasonable, moral, legal and Constitutional solution.

श्री जी० एस० निहाल सिंह वाला (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय, जब से पंजाब में अकालियों की मांगों का मसला चला है, तब से कई बार इस हाउस में उस पर बहस हो चुकी है। वक्तन-पे-वक्तन यह सवाल यहां पर उठता रहता है। लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक इसका कोई हल नहीं निकला और हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि हमारे पंजाब की बदकिस्मती है। पंजाब एक जरई पैदावार में हिन्दुस्तान का सबसे बढ़िया सूबा है, जिसके पास सिर्फ एक कसर 54 फीसदी भूमि का हिस्सा है। उसमें से तकरीबन 69 फीसदी गन्दुम और 50 से ज्यादा चावल देता है। इन सब चीजों के बावजूद भी पंजाब ने एक रिकार्ड रखा है और 91 लाख टन गेहूं पैदा किया है। उस सूबे में इतनी गलत शक्ल अखितयार कर जाए और उसका हल न निकले, मैं तो समझता हूं कि यह मुलक के लिए भी बदकिस्मती है।

एजीटेशन शुरू करने के बाद अकालियों ने एक-एक कर मांगें बढ़ाई हैं। मैं पहले हिन्दुस्तानी और बाद में सिख होते हुए तीन मांगों का हकदार हूं। ये मांगें कुछ हैं, तो पूरी होनी चाहिए। मांगें भी मुनासिब ताकि हिन्दुस्तान के बाकी लोग हम से नफरत न करें। जहां तक धार्मिक मांगों का ताल्लुक है, उनको देखना चाहिए। कुछ मांगें अकालियों ने वैसे ही रखी हुई थी, ताकि एक बड़ी लिस्ट बन जाए – गुरुद्वारे से कीर्तन करना दो घंटे, कृपाण छः इंच से नौ इंच हो जाए या अमृतसर से जो गाड़ी जाती है, उस का नाम गोल्डन टैम्पल नाम कर दिया जाए। ये सारी बेकार की बातें हैं। लेकिन वे एक बात चाहते थे और कहते हैं कि सरकार को कोई हक नहीं है वह किसी धर्म में दखल दे और दूसरी तरफ सरकार को मजबूर करते हैं कि तुम अपनी सारी ताकत से हमें काबिज कर दो सारे हिन्दुस्तान के सिखों पर। चाहे वे कहीं के रहने वाले हों और वे पसंद करें या न करे। नागेड का सिख नहीं चाहता अमृतसर के सिख को ताकत देना। अगर पटना साहब का सिख नहीं चाहता तो सरकार को क्या हक है कि वहां के

सिखों को मजबूर करे। मैं समझता हूं कि सरकार को वन्स फॉर ऑल फैसला कर देना चाहिए कि हम किसी धर्म में किसी किस्म का कभी दखल नहीं देंगे। वे अपना इलैक्शन करायें। टोहरा साहब को सारे हिन्दुस्तान का प्रैसीडेंट बना दें, सरदार प्रकाश सिंह बादल को सारे हिन्दुस्तान का जनरल सैक्रेटरी बना दें और चाहे सारे हिन्दुस्तान के गुरुद्वारों का रुपया घर को ले जाए, हम बिल्कुल ऐतराज नहीं करते हैं। यह उनका मामला है। अगर हम चाहेंगे और हमें लालच आएगा तो हम उनमें शामिल हो जायेंगे और अगर नहीं शामिल होना चाहते हैं, तो नहीं होंगे। मगर सरकार क्यों उसमें मजबूर करे।

बाकी मांगें, चाहे आप उनको पोलिटिकल कह लें या ज़रूरत समझते हैं कि हमारा यह हक बनता है। स्पीकर साहब आप भी वहां के रहने वाले हैं और पंजाब एसेम्बली में हम लोग इकट्ठे भी रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब कौन-सा दूर हो गए हैं। अब भी इकट्ठे हैं।

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला : मैं तो सिर्फ याद करा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब भी पार्लियामेंट में हम इकट्ठे हैं।

...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप सब की कृपा है।

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला : स्पीकर साहब, एक नक्शा सामने आना चाहिए। गिला नहीं करना चाहिए कि इस तरफ से क्या बोले। जो उनका जी चाहा, बोले। मसला सिर्फ पंजाब का है।

यह मसला हल होना चाहिए। ये लोग उस को अपने ढंग से पेश करते हैं और हम अपने ढंग से पेश करते हैं। सवाल यह है कि कब तक यह इस तरह से चलता रहेगा।

यह झगड़ा कब से चला? यह उस वक्त से चला जब हरियाणा वालों ने कहा कि हम कपूरी गांव से नहर खोदेंगे। वहां पर एक फंक्शन रखा गया। अकाली दल वाले ऐसे मौके की इन्तजार में थे ताकि उनको मोर्चा लगाने का मौका मिले। लिहाजा उन्होंने ऐलान कर दिया कि कपूरी गांव में मोर्चा लगायेंगे, नहर नहीं खोदने देंगे। उस मौके पर अगर वह यह कह देते कि नहर खोदने दो, पानी के बारे में बैठकर फैसला कर लेंगे कि कितना तुम्हारा हक बनता है और कितना हमारा हक बनता है, अपोजीशन के लीडर्स को बैठा लो, हमारे लीडर्स को बैठा लो और बैठकर फैसला कर लो। लेकिन उनका यह कहना कि हम नहर नहीं खोदने देंगे—यह नामुनासिब बात है। अगर इस तरह से सोचा जाय तो ये भी कह सकते हैं कि रेल हमारे इलाके से गुजर कर पंजाब में जाती है हम रेल को नहीं जाने देंगे। इसलिए इस तरह की बातें नामुनासिब बातें हैं।

हमारी एक बदकिस्मती यह है कि अकाली मोर्चा पोलिटीकल कभी नहीं होता है, धार्मिक होता है। अगर यह पोलिटिकल मोर्चा होता, तो वे इसको चण्डीगढ़ से चलाते, वहां के सैक्रेटेरियट से चलाते, इसके लिए गुरुद्वारे में जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन इन्होंने गुरुद्वारे में मोर्चे को शुरू किया ताकि वहां पर कोई नाजायज कत्ल करके चला जाय या कोई वारदात करके चला जाय तो पुलिस अन्दर न जा सके। यह कहा जाता है कि वहां की गवर्नमेंट क्या करती है। कोई भी गवर्नमेंट हो—कोई भी नहीं चाहेगा कि पहले ही दिन खून से हाथ रंग ले। चाहे जनता पार्टी की सरकार हो या कोई दूसरी सरकार हो, सबकी यही कोशिश होगी कि कोई तसल्लीबख्श फैसला हो जाय, ऐसी बात न की जाय जिससे मासेज में नफरत बढ़े। लेकिन उन्होंने इसका नाजायज फायदा उठाया।

हमारे कुछ दोस्त कुछ ऐसी बातें कहते हैं—जिन को सुनकर मुझे एक मिसाल याद आ रही है—आम का अचार खायेंगे लेकिन तेल से परहेज करेंगे। जब आम का अचार खाना है तो तेल से कैसे परहेज हो सकेगा ? ये लोग भिंडरानवाले की शिकायत करते हैं, वह ऐसा है, वैसा है, लेकिन लोंगोवाल की तारीफ करते हैं, बादल साहब की तारीफ करते हैं। तोहरा साहब के खिलाफ बोलते हैं। उनका यह लहजा बड़ी देर से चला आ रहा है। जब संत फतह सिंह थे तो जनसंघ के साथ उनकी लड़ाई थी। वे लोग कहा करते थे—धोती-टोपी जमना पार, या शायद इसी तरह की कुछ बात कहा करते थे, जब कि संत फतह सिंह कभी कह दिया करते थे—हिन्दू सिख भाई-भाई। जो उनकी मर्जी होती थी करते थे और जो चाहते थे संत से कहला देते थे। उसी तरह से आज इस संत को बैठा रखा है, जो शो-व्वाय की तरह से है और जो मर्जी आती है करते है। आप देखिए—मैं अमृतसर गुरुद्वारे में नहीं जा सकता, क्योंकि डर लगता है, कत्ल कर देंगे। अटवाल साहब, डी. आई. जी का मामला साफ हो गया और कोई गिरफ्तार नहीं हुआ···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई ?

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला : अभी बतलाता हूं। इसलिए कि सरकार जब कुछ करती है तो आप जुडीशियल इन्क्वायरी मांगते हैं। जब सरकार सख्ती करती है जो आप जुडीशियल इन्क्वायरी की मांग करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब नहीं मांगेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : अब खुली छुट्टी है, करो।

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला : वह तो करना ही पड़ेगा और जरूर करेंगे। लेकिन सरकार का फर्ज है कि लोगों को मौका दिया जाय। आज मैं गुरुद्वारे के किसी कमरे में नहीं जा सकता, सिख होते हुए भी नहीं जा सकता, इसकी क्या वजह है ? भिण्डरानवाला अपनी मर्जी से वहां रहता है, क्या शिरोमणी अकाली दल के प्रधान गुरुचरण सिंह तोहरा उनको निकाल नहीं सकते। उनके आदमी कुछ भी कर आते हैं, अपने साथ असलाह रखते हैं, उनको क्यों नहीं निकालते, बल्कि उनको प्रोटेक्शन देते हैं। आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, गवर्नमेंट को तो पता होना चाहिए, बागड़ी जी, आपको भी पता होगा, बादल साहब जो एक माडरेट अकाली हैं उसने असलाह देकर अपने आदमियों को उनके पीछे छोड़ा। आजकल बादल साहब की क्या मजाल है, कभी अमरीका चले जाते है कभी रशिया चले जाते हैं, वह इस झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका पत्ता वहां से कट चुका है।

श्री मनीराम बागड़ी : यह सही है।

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला : मानते हो तो फिर उनकी वकालत क्यों करते हो। बागड़ी जी बहुत सच्चे आदमी हैं। वे कहते हैं कि मेरे करीब बैठनेवाले दो जबानें रखते हैं। आपके लिए उन्होंने यह कहा था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने क्या कहा, वह आपने नहीं सुना। मैंने कहा था कि कांग्रेस के दो जबानें हैं, जोकि दिखाई नहीं देती हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : वह भी है लेकिन इस मामले में मैं इनके साथ हूं।

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला : स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब का मसला हल हो सकता है अगर अपोजीशन के मेरे दोस्त इसको **कैस इन** न करना चाहें। जिसकी गलती हो, उसको गलत कहें। जब तक ये इस बात को नहीं मानेंगे कि भिंडरावाला अकाली पार्टी का पार्ट एण्ड पार्शल है और उसका डोमीनेशन अकाली पार्टी पर है, तब तक ये इसको नहीं

समझ पाएंगे। बादल ग्रुप अलग है और मेरे दोस्त भाटिया साहब इसको तफसील से नहीं समझा सके कि भिंडरावाला का गुरुद्वारा इलेक्शन्स में क्या रौल था। वे जीवन सिंह उमरनांगल के खिलाफ थे और जो स्टूडेंट्स का लीडर था और नक्सेलाइट था, उसको लड़ाना चाहते थे लेकिन उमरानांगल को यह नहीं मालूम था और उसने अपना आदमी उसके खिलाफ लडा दिया। इसलिए वहीं तक उनकी लड़ाई महदूद है और जिस दिन भिंडरा-वाला के खिलाफ मैं यहां पर बोला, तो मैं यकीन दिलाता हूं इस हाउस को कि उमरानांगल ने, जो चंडीगढ़ के सेक्रेटेरियेट में मुझसे मिला था, यह कहा कि वाह, क्या बात आपने कही और अकाली पार्टी का होते हुए भी उसने मुझे कांग्रेचूलेट किया जबकि मैंने भिंडरावाला को एब्यूज किया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो दोनों अलग अलग हुए।

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला : बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप क्यों उनकी वकालत करते हो।... **(व्यवधान)**.. वे सब एक हैं लेकिन अलह्दा-अलह्दा उनको काम सौंपा हुआ है।

एक माननीय सदस्य : अभी तो आप कह रहे थे कि वे अलग-अलग हैं।

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला : मैं तो यह कहना चाहता हूं कि वे सब एक हैं लेकिन अलग-अलग काम सौंपे हुए हैं। उनका प्रोग्राम एक है और वे खालिस्तान के हक में हैं लेकिन हिन्दू-सिख भाई-भाई के नारे लगाते हैं। जब रेल पर जाते हैं तो कत्ल करते हैं और बैंकों में डकैती डालते हैं और उनको लूटते हैं, तब जब वे नानक निवास में जाकर रहते हैं, तो उनको बाहर क्यों नहीं निकालते और उनको पुलिस को हैंड ओवर क्यों नहीं कर देते। मान लिया कि सरकार कम-जोर है।

श्री मनीराम बागड़ी : सरकार तो कमजोर है ही।

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला : मैं इसको मान लेता हूं कि सरकार वहां पर कमजोर है लेकिन आप ऐसा काम करने वालों की तारीफ क्यों करते हो और उनकी मदद क्यों करते हो।

श्री मनीराम बागड़ी : हम कभी उनकी तारीफ नहीं करते हैं। इसमें हम आपके साथ हैं।

श्री जी०एस० निहालसिंहवाला : तो मैं यह कहता हूं कि यह एक छोटा-सा मसला है। इसमें किसी की वकालत करने की बजाए, असली बात को आपको देखना चाहिए।

मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अबहोर और फाजिल्का के बारे में कहना चाहता हूं कि यह मसला क्या है और यह चण्डीगढ़ के साथ कब लिंक हुआ। मैं इसको ईमानदाराना तौर पर बताता हूं कि यह कैसे हुआ। उस वक्त भी मैं यहां पार्लिया-मेंट में मेम्बर था। सन्त फतेह सिंह ने मरण-व्रत रख लिया और यह कहा कि फलां तारीख तक चण्डीगढ़ हमको दे दीजिए, नहीं तो मैं जल मरूंगा और क्या ड्रामा उन्होंने रचा कि जो अकाल तख्त साहब है, जो हिस्टोरीकल प्लेस है बिल्कुल उसके ऊपर वाली छत पर दरबार साहब के सामने वे चले गए। बागड़ी जी भी वहां जाया करते थे और ये उनके शिष्य थे। वहां पर उन्होंने बड़े-बड़े कुण्ड बनवाए और उनमें मिट्टी का तेल डाला और फिर सांकल से अपने को बंधवा दिया और ऐसा इसलिए उन्होंने यह कहकर किया कि मैं जलकर मरना चाहता हूं और मैं डरकर छलांग न लगा जाऊं, इसलिए मुझे सांकलों से बांध दिया जाए। आखिर वह दिन आ गया और वे इन्तजार करते रहे कि सरदार हुकुम सिंह सैंट्रल गवर्नमेंट से कुछ आदेश लेकर आ रहे हैं लेकिन वे नहीं पहुंचे। इस पर एक डेपुटेशन ढिल्लों साहब से, जोकि स्पीकर थे, मिला और उनसे कहा कि सन्त की जान खतरे

में है। उन्होंने कहा कि मैं इसको कैसे बचा सकता हूं, आप गवर्नमेंट से कहें। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर के यहां डैपूटेशन पहुंचा। वे प्रधान मंत्री के सामने ढोंग रचा करते थे और जब उन्होंने यह देखा कि हर चीज के लिए ये एजीटेशन करते हैं तो उन्होंने गुस्से में यह कह दिया कि चण्डीगढ़ लेना है तो ले लो, मैं कब मना करती हूं। इसके बदले अबहोर और फाजिल्का दे दो। उन्होंने यह सोचा कि चलो जान बची और लाखों पाए। वे यह कहकर अबहोर और फाजिल्क दे देंगे वहां से आ गए लेकिन जब वे पंजाब पहुंचे, तो वहां पर उनको लोगों की तरफ से बड़ी जूतियां पड़ीं और सिखों और पंजाबियों ने यह शोर मचाया कि हमको बेच कर ये आ गए है और चण्डीगढ़ के लिए इन्होंने इतना अच्छा और बढ़िया इलाका दे दिया। इसके बाद वे इससे बैक-आऊट हो गए। तो वे उससे भाग खड़े हुए। चण्डीगढ़, फाजिल्का और अबोहर का मसला एक नहीं है। चण्डीगढ़ क्या है, क्या नहीं, लेकिन मुझको इतना पता है कि एक सच्चर फारमूला हुआ था। सच्चर फारमूले के आधार पर कमेटियां बनी थीं। एक कमेटी हिन्दी रीजन के लिए बनी थी और दूसरी कमेटी पंजाबी रीजन के लिए बनी थी। हिन्दी बोलने वाले इलाके हिन्दी रीजन में शामिल हुए थे और पंजाबी बोलने वाले इलाके पंजाबी में शामिल हुए थे। उस वक्त किसीने यह बात नहीं उठाई कि चण्डीगढ़ पंजाबी रीजन में है या हिन्दी रीजन में है। उस वक्त किसीने यह नहीं कहा कि अबोहर हिन्दी रीजन में है। उस वक्त सब सन्तुष्ट हो गए थे। पंजाबी वाले भी और हिन्दी वाले भी। मगर अफसोस यह होता है कि कभी कभी कमीशन वाले भी नाइंसाफी कर बैठते हैं। सच्चर फारमूले के आधार पर जो पंजाबी रीजन और हिन्दी रीजन बने थे उनका सत्यानाश हो गया। अब खरड़ और शकरगढ़ तहसीलों के बारे में कहा जाता है। मैं कहता हूं कि खरड़ को चण्डीगढ़ से अलग नहीं किया जा सकता। मैं कहना चाहता हूं कि आप रिकार्ड उठा कर देख लीजिए। रिकार्ड के मुताबिक चण्डीगढ़ पंजाब का है, अबोहर और फाजिल्का भी पंजाब का है। मैं आप लोगों से यहां दरख्वास्त करूंगा कि कुछ लोग जो इस तरह की बातें करते हैं आप उनमें न आयें। इससे सारा पंजाब बर्बाद हो रहा है, सारा मुल्क इससे बर्बाद हो रहा है।

हमारे चौधरी साहब एक बुजुर्ग आदमी हैं। पता नहीं चौधरी साहब गुस्से में यह बात कह गए या जल्दी में यह बात कह गए कि 1857 में क्या हुआ। मैं यह मानता हूं कि हर फिरके में और हर कम्युनिटी में अच्छे भी लोग हो सकते है, बुरे भी हो सकते हैं। मगर सिखों ने हिन्दुस्तान की बहू-बेटियां मुसलमान बादशाहों के यहां नहीं भेजी थीं, हमारे में से कुछ सिख चले गये थे तो इससे क्या हो गया। जितना बड़ा रोल हिन्दुस्तान के बहादुर हिन्दुओं का है उससे हमारा बहुत छोटा रोल है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि अपोजीशन को और हमारी पार्टी को भी कि गलत लोगों को गलत कहो, सही लोगों को सही कहो। अपोजीशन के लोग जिस तरह की तकरीरें यहां करते हैं अगर इस तरह की तकरीरें जालन्धर, अमृतसर, पटियाला में करें तो उन्हें कोई रिस्पांस न मिले।

एक माननीय सदस्य : आपको मिलेगा।

श्री जी० एस० निहालसिंहवाला : मैं तो करके आया हूं। आखिर में मैं इतना ही कहता हूं कि हम सबको मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए।

SHRI INDRAJIT GUPTA : (Basirhat) : The House is debating this Punjab issue now for well over five hours and apart from certain charges and counter charges, of course, which we have been hearing, we just now heard a conclusion, rather a depressing conclusion, if I may say so, made here by Mr. Stephen who is, of course, an important leader of the ruling Party, in which he said at the end that we have now reached the stage where it is not possible to advance further. Before he spoke, we have all been anxiously listening to hear whether any responsible Member of the ruling Party is willing to spell out, in spite of all the diffi-

culties that are there, what concretely they are thinking or whether we are now to subscribe to Mr Stephen's conclusion that we have reached a stage where no further advance is possible.

I do not know what the Home Minister is going to say. Of course, we have the benefit of reading in the Press of what he has said in the other House, rather the statement he made in the other House where he seems to-day he may say something different—to have just offered two alternative packages and said, 'Take it or leave it', either abide by the Prime Minister's award without explaining why the Prime Minister's award has not been implemented to this day by the Government itself, or, if you do not like that award, then, refer all these disputes, particularly, the water dispute and the territorial dispute, to a tribunal. That is all he had to offer, according to what I read in the Press.

Now, Sir, enough has been said to create a gloom, I should say, over the situation as it has come to develop now. The people are expecting, I suppose, that the Parliament of this country will be able to indicate, through discussion and debate, some way out of this impasse. Why the entire Sikh community to whom enough tributes have been paid by everybody in this House— I need not add my voice to this—has come under the cloud of suspicion ? Everybody says that the akalis do not represent the entire Sikh community. Is it because of the doings of the Akalis that the entire Sikh community is under some sort of cloud of suspicion ?

I want to point this out here that there was a time, a few months ago, when the Chief Minister of Haryana who belongs to the Ruling Party, took it upon himself to see that any car or transport passing through his State, if it contained any Sikh passenger, must be asked to get down and he must be investigated. Who gave this right to him ? The eminent people like Gen. Harbaksh Singh and Gen. Arora who, in spite of their protestations about their identities, were humiliated and were asked to get down from their cars. Was it just because they were wearing turbans and were having beards ? Who gave this right to the Chief Minister of the Congress Party ?

SHRI C.M. STEPHEN : Why do you stare at our Home Minister ?

SHRI INDRAJIT GUPTA : You must know how the situation has developed. You should have admonished Shri Bhajan Lal for doing all this I can say one more thing. There was a stage when there was such a pressure of public opinion, I do not know if our friends believe in it or not, when it was possible to confront the Akali leadership with this question that it was their responsibility of seeing that absconders or the people who have got charges against them and who are criminals and who have committed offences should not be permitted a shelter inside the Gurudwara or temple. It is their responsibility also to see that they are turned out because, if they have remained there and if they harbour them in that place of worship, then, that place of worship ceases to be sacrosanct. If such types of people are given shelter in that place, it is their responsibility to see that they do not allow such types of people to defile the place of worship. It is their responsibility to turn them out. A situation like that had come out. If there was a proposal like that, the country would welcoming it. Suddenly, from Delhi, an ultimatum was delivered during the budget session and that ultimatum was that within seven days if they do not turn these people out, we shall take all steps necessary to go into the Gurudwara. I think that ultimatum had the result of uniting the Sikh community together again. There was a threat certainly. Fortunately or unfortunately, you cannot stop that because of the conditions in our country. Because of social and religious conditions in our country, you cannot say 'yes, we shall send the police or the security forces into the gurudwara.' But, Sir, the responsibility could have been foisted on to the Akali leadership that it was their responsibility to turn out these people. But, that opportunity, was also lost by the language of that ultimatum. (*Interruptions*). Anyway, Sir, I do not know if the C.I.A. is involved in it or not.

SHRI C.M. STEPHEN : You will please go through the record.

SHRI INDRAJIT GUPTA : I think

the CIA would not be the CIA if they missed an opportunity like this. Bat there is no proof and, as such, I do not agree with Mr. Fernandes. Of course, we do not know what transpired in talks between Mrs. Gandhi and the External Affairs Minister and Mr. Shultz but I am sure even if they had confronted Mr. Shultz as to whether CIA is interfering here, Mr. Shultz is not a simpleton as to admit that such a thing is happening. But I would like to know what is the government's reaction to the statement which was made a little earlier by the American Ambassador here in Delhi, Mr. Harry Barnes, who said publicly that if some people can come to India--meaning the delegates to the non-aligned conference—and plead the case of Puerto Rico's independence or defend the rights of Puerto Ricons then why are they so touchy when somebody in America defends the right of Khalistan. Has there been any reaction from our Government ? We have not found anything. We do not know if they raised this matter at all with anybody on the American side. Certain there was no public reaction. I am glad to say that some people in the ruling party and some organisations which are controlled by the ruling party did react to it and did protest publicly and held demonstration outside the American embassy but as far as you are concerned—Mr. Sethi—and the Prime Minister there has been no reaction whatsoever.

19.47 hrs.

[DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI *in the Chair*]

What I want to say is that it is only a settlement of this issue—difficult no doubt—which can really isolate the extremists. I do not subscribe and none of us subscribe to this view which is sometimes being insinuated here that everybody in the Akali camp is an extremist. You want to tar everybody with the same brush whereas we do not. If you want to isolate the extremists the only way is through an early settlement of this question and as somebody said here everytime the possibility of settlement appears on the horizon immediately there is a spurt in these extremists' activities because they get desperate then.

SHRI C.M. STEPHEN : What is your suggestion ?

SHRI INDRAJIT GUPTA : Before I come to any suggestion I would like to touch certain things which have not been mentioned at all.

So much has been said about water dispute. We all agree that 1955 agreement about water cannot be re-opened and a clear position was taken in our meeting with the Akalis in the tripartite meeting also. That is our stand even now. 1955 agreement cannot be re-opened. It is not only a question of Rajasthan. It also involves the whole question of Indo-Pakistan agreement. But you do not say a single word about the non-construction of Thien dam. What happened to the Thien dam which is an integral part of this whole water issae ? Why Central Government is dragging its feet and does not see to it that construction of the Thien dam takes place ? Twenty-five years have lapsed. The officers are sitting there. You are responsible for that. Why is Thien dam not being constructed and along with that the link canal can be made to function and the remaining water disputes can be referred to the tribunal. They have agreed to it. What I am saying is that the amount of consensus which was arrived at at the tripartite meeting—Mr. Stephen has himself elaborated that certain broad lines of consensus were agreed upon—why don't you catch hold of that and take some initiative to further concretise the discussion instead of saying you cannot go further. Of course, legitimate rights of Haryana have to be protected. There is no doubt about it. No doubt about it. But it will never be done unless all these things are taken up together.

SHRI C.M. STEPHEN : Then they shifted the stand and wanted the Rajasthan issue also to come in and therefore Rajasthan people were brought in for tripartite conference.

AN HON'BLE MEMBER : No, no.

SHRI C.M. STEPHEN : Let them openly say it.

SHRI INDRAJIT GUPTA : In spite of

everything that is being said against us, against the Opposition parties, we maintain that we have made, may be humble efforts,, but we have made earnest efforts, sincere efforts, to bring the Akalis to some sort of consensus and the differences have been narrowed down. If the Akali leadership tries to resile now from any of those agreed points of the consensus, well, certainly we will not support them. And now I should say that Mr. Longowal's appeal to the Members of Parliament contains many points which, I suppose, have been made again under some sort of extremists pressure and they cannot be supported. But, here, I would like to say that there is some confusion. I do not know whether it is deliberately created or whether it is due to some sort of ignorance and what about this Article 25 of the Constitution which he has demanded should be amended so as to declare India a multi-national country in which different nationalities could live without losing their identity ? People who know more Urdu than I know—I know a little bit of Urdu and I studied it once—will tell me the meaning for the word 'Quam' and if you translate it into English, it can mean a 'nation' also, it can mean religious community, it can mean a caste, even a caste is referred to a 'Quam,' religious community is referred to a 'Quam'. So, will you please tell me the Urdu word for the word 'nation' ? Please translate the word 'nation' into Urdu. There is no other word except 'Quam'. So, this is the trouble. This word 'Quam' can mean any of these three things.

Now, Mr. Longowal says that like 'Jains' and 'Buddhists' the Sikhs want their separate entity to be maintained with separate laws to uphold their social, religious and other rights. Their demands for being treated as a separate nation, should be viewed in that context. He is mixing up two things, that is, 'nation' with the 'religious community'.

Now, in this Article 25, it is clearly stated that reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly.

Now, they have asked for a separate Personal Law. I do not know what its implications are. Somebody should tell us. I invite the Akali leaders. Anybody on that side can explain to us. Sardar Buta Singh can explain what the implications for demanding Personal Law for Sikhs are. From some enquiries I made, it seems to me that the main thing which is troubling them in the Hindu Personal Law is the question of inheritance of property, because the most valuable property in the Punjab is land, particularly agricultural land and some people do not want that by the Hindu Inheritance Law this land should pass on to the daughter, to the women and then pass on to the son-in-law and ultimately go out of the family. Is that the reason, why they want the separate Personal Law. They should state it publicly. But anyway this matter can be followed up. They can be asked to spell out what they want. But they should not mix up 'nation' with 'religious community', all under the same name of 'Quam'. Now, for a long time when this movement was going on we were congratulating ourselves of the fact, whatever else may happen, but Hindu-Sikh clashes are not taking place. We were very happy about that. I suppose we were too premature with that happiness. Now see how far the situation has deteriorated. This is something very painful to see the kind of communal clashes which have been taking place. And now you have to decide. Afterall you are the Government. Don't try to equate yourself with the Opposition. You are the Government. You have the responsibility for administering the country. And if you are serious about the thinking that the Punjab situation should not be allowed to deteriorate for various reasons—for the sake of national integration, national unity and the security of our borders and all the rest of it, then you must be ceaseless in your efforts and initiative to bring about a settlement and not stand on the question of prestige on who will write to whom, who will come where and who will go where. That position has to be firmly upheld that you must be forthright. You must be open hearted in your approach to this question. You are taking affront because we are accusing you of dragging your feet probably for political motivation. At the moment,

as far as I can see : either the Akali leadership nor the ruling party is over anxious for an early settlement. Both of them would like to keep the pot boiling. But this is going to be disastrous for the country. And the worst thing of all is the fact that the communal provocation is now being mounted by both sides. The Defence Minister is here. Of course, we would not speak anything about this in detail, not that we have not to mention anything, but I am very much apprehensive of the emotional impact of these things on the personnel of our Armed Forces. It does not matter whether they are serving personnel or whether they are ex-servicemen. Ex-servicemen have been openly appealed to and have been sought to be mobilised also on some occasions. There are ex-servicemen not only in Punjab, but equally there are ex-servicemen in Haryana—in those districts which are very important recruiting grounds for our Army. And if this communal tension and communal provocation is allowed to be mounted, it will have the most deleterious effect on the nation's security.

But what is the role of the ruling Party in this ? You try to say that the whole blame is to be put on the Akalis. Well, the Akalis, as you say, are a communal party. And if there are extremist elements among them, who thrive on communal provocations, it is not surprising. But what about the Congress Party, which is supposed to be a secular Party, which is supposed to be in charge of this country's entire administration, which swears by so many lofty principles, what are their people doing ? We know what happened in Patiala. Detailed reports have come out. We know who Mr. Pawan Kumar Sharma is. His name has been mentioned many times. Who are the people who incited these riots ? And in some places you say it is BJP who is doing. Well, BJP and certain Congress elements, you have got together in this matter. In Jullundhur riots, what has been happening ? Who are the people, who are the parties ? And you don't want me to mention names here. You don't want me to mention the names of the editors of leading papers who are fanning communal strife and which are the people who are known to be supporters of the Congress (I).

In Punjab, there are so-called dissidents in your Party, whose main purpose is to somehow destabilise the existing Ministry, I mean the Darbara Singh Ministry, may be it is quite useless in maintaining the law and order. I have no doubt about it. If you think so, you should change him. But who are all these people. Who are out to destabilise the Chief Minister belonging to your own Party ? Who are the people who encouraged Bhindranwale, when came to Delhi with all his armed people sitting on buses and lorries ? You want me to name those people who had gone there just to take the dust of his feet, of which there are photographs as proof. I dare not mention those names now, because the situation has become so explosive.

20.00 hrs.

You have created this Frankenstein. And now, this Hindu Raksha Samiti has been formed. You may justify that it is being created as a reaction to Sikh communalism. But why is it being encouraged ? Why is the Prime Minister willing to give it such a prolonged hearing, i e. to the Hindu Raksha Samiti leaders ? There is a Hindu Sanghathan which is also being formed. These are not being decried at all.

We cannot for a moment subscribe, of course, to those Akali people who say that the Akalis are not being allowed to take any part in this country's decision-making process. This is absurd—or that Sikhs are leading a life of slavery in this country. These are absurd things. (*Interruptions*) I do not know whether they are ruling this country. Rashtrapati Ji belongs to that community. The Chief of the Air Force belongs to ft, and the Director-General of CSIR which is a premier scientific research institution in this country, belongs to this community. (*Interruptions*)

There are so many eminent Sikhs in this country. So, for anybody to try to incite Sikhs by saying that they are leading a life of slavery in India is absolutely, patently absurd ; but, nevertheless, they have raised certain demands which are connected with the whole question of Centre-State relations. It is not a matter only for the Punjab. We

are fully in sympathy with this. You have set up the Sarkaria Commission. It is good. But what is its basis ? Under what law or under what Article of the Constitution has it been done ? Simply an announcement has been made on a Commission. I think it is high time that Government should elaborate this question, and give some legal or constitutional basis—and tell us under what Act and under what Article of the Constitution it has been set up, and what are its powers and functions. Are there any further members going to be added to that Commission ? Do you consider that its terms of reference should be more specifically and concretely defined ? Above all, what is its basis in law and in the Constitution ? There is nothing there at the moment. You cannot have a Commission of this type simply by means of an announcement. Anyway, now that you have announced it, it is better that you give it a proper shape, so that it can be useful.

I think Mr Stephen, for all his pessimism, should admit that there are only two outstanding disputes. One is about water, and the other is the territorial dispute. Don't tell me that it is not possible to settle them ; you can, provided you are not anxious to see somehow that the pot is kept boiling till the elections.

SHRI C.M. STEPHEN : It is most unfair, Mr. Gupta. The Opposition friends are here. Would the Opposition agree that their units in Haryana and Punjab come across for a settlement on this ?

SHRI INDRAJIT GUPTA : As far as my party is concerned, I can say yes.

SHRI C.M. STEPHEN : What about your units in Haryana ?

SHRI INDRAJIT GUPTA : What about your units ?

SHRI C.M. STEPHEN : Our position is that if a settlement is possible, it will be done ; otherwise, let us refer it to a commission. This is our stand ; and our people are agreed on that.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Our Punjab and Haryana units are absolutely agreed.

SHRI C.M. STEPHEN : Chaudhry Sahib, the BJP and the Janata Party have to say.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Mr. Sethi will please explain this : when you talk about sharing waters, is it simply a question of referring it to a tribunal ? What about the link canal, and about the construction of the Thein dam ? Without constructing the Thein dam, nothing can be done. You are doing nothing about it for years and years.

About this territorial dispute, my party is not of the view in the conditions of Punjab and Haryana that the village should be taken as a unit on the basis of language, linguistic unit for deciding which village will go where. The simple reason for that is that the Sikhs being, as we all know, very energetic, very mobile people, very adventurous, very enterprising, have gone and settled down in many places ; and if they go and settle down over the years in a particular area or in a village or a group of villages and become a majority there and therefore on the basis of that majority, if it is claimed that that village must go to Punjab, I think, that will create a lot of problems. It is on that basis, for example, that they are claiming part of Ganga Nagar District in Rajasthan, because over the years, Sikhs have gone and settled there ; and in some of the border areas, they are in a majority, not Rajasthanis.

श्री धर्मदास शास्त्री (करोलबाग) : जियोग्राफिकल बात जो आप कह रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : खाली अपोजीशन को गाली देने के बजाय आप इस पर रोशनी डालिए, तो फायदा होगा।

श्री धर्मदास शास्त्री : वह राजस्थान का हिस्सा है, राजस्थानियों की वहां मैजोरिटी है।

SHRI INDRAJIT GUPTA : Along with the border between Haryana and Punjab also, there are some areas like that. But we have

taken the stand that, of course, it is not necessary that the final solution must be according to this, some line of discussion has to be pursued. Chandigarh should go to Haryana. After all, when Chandigarh was constructed, there was no Haryana State in existence ; and the whole idea was that it should be the Capital of the Punjab and Haryana should be given adequate financial assistance and resources to build a separate Capital and that they should quit Chandigarh within a period of five years. Our only contenion is that in the conditions of today there should be some agreement ; and in addition to this, Haryana should be given as compensation some other land or some other pieces of land from the Punjab.

AN HON. MEMBER : Where ?

SHRI CHIRANJI LAL SHARMA : Why don't you say that Abohar and Fazilka should go to Haryana ?

SHRI INDRAJIT GUPTA : But the Award didnot say that automatically when Chandigarh goes to Punjab, then Fazilka and Abohar come to Haryana ; it is not like that. Please read it. It says that Fazilka and Abohar will go to Haryana. When certain other villages on the border have been surveyed and identified, then along with those villages, Fazilka and Abohar can be transferred to Haryana. Now some Haryana people are saying that they do not wait for the last part of the Award. As soon as Chandigarh is given to Punjab, Fazilka and Abohar should come to us. That is being opposed and resisted by the people of Punjab, by the Sikhs. So, if you want to do that, then some land has to be given as compensation. These are the matters on which we cannot go into details here. But my point is that these are not the matters which cannot be settled through a serious discussion and pursuing them, if you really want to settle them. But if you do not want to settle it, then, of course, you can go on drifting and dragging them and letting the situation get worse and worse with more communal clashes, with more communal strife, with more killings and murders and I do not know were we will land up at the end.

I have been saying since last year that Punjab should not be allowed to develop into another Assam. But when I was saying those things, there was no communal clash that had taken place. Now, we have come a long way ; we are, I am afraid, on the wrong side, on the wrong direction and very serious developments are taking place. I would earnestly request the government that they must give up, their Prime Minister must give up this habit of just saying nothing every day in her meetings and statements, etc. except saying that all this trouble is being caused by the opposition. Finished. No other solution is there ; the only solution is to go round the country, accusing the opposition of having created a trouble. I say that the opposition has tried sincerely and honestly much more than the government side has tried to narrow down the differences and to bring about a consensus. (*Interruptions*) It is a fact ; it is recorded on paper.

I am telling you that if you do not like it, then you stick to the consensus arrived at in your tripartite meeting, to which you are also a party. Do not come here and say that we have reached a stage where we cannot progress any further.

SHRI C.M. STEPHEN : What was the consensus ? The consensus was that without involving Haryana no settlement should be arrived at. That was the consensus. (*Interruptions*)

SHRI INDRAJIT GUPTA : You have brought the whole process to a full stop. That means, you are gambling with the future of this country, its security and its integrity. (*Interruptions*)

SHRI C.M. STEPHEN : I must accuse you that you are adding fuel to the fire. (*Interruptions*)

SHRI INDRAJIT GUPTA : You want to simply bypass the real issue and get away by accusing the opposition as if the opposition is in a position to stop you if you want to go ahead with negotiations. (*Interruptions*) You are anxious to keep this tension...

AN HON. MEMBER : Why ?

SHRI INDRAJIT GUPTA : Because elections are coming. (*Interruptions*) You are wanting to mobilise the Hindus support behind you as against the Sikhs.

SHRI C.M. STEPHEN : Hindus have always been with the Congress. (*Interruptions*)

SHRI INDRAJIT GUPTA : That is why, after the BJP has been defeated in Jammu, no less a person than Mr. Malkani, who is the editor of the RSS paper, publicly states that though the BJP has been defeated in Jammu, the platform of the BJP has won. What does he mean by that ? You tell us how you take it. Please do not play this dangerous game by trying to seek political advantage by provoking communal elements. (*Interruptions*)

I think the country expects that from this parliamentary debate some ray of hope will emerge, some way forward will be indicated.

All right, for the time being if I withdraw this allegation that you are doing this for electioneering business, you also kindly withdraw your absolutely baseless allegation that the opposition is creating all the difficulties. Try to work out some concrete formulae, some way forward which you are not bothered about at all, as I see it. (*Interruptions*) I am posing this thing to the Minister because he has still to have the last word. Is he going to come forward with some kind of concrete constructive proposals ? Or is he just going to say something which will only help to perpetuate the present deadlock, which means that our country is really going to face a terrible danger to its whole security and unity.

श्रीमती कृष्णा साही (बैगूसराय) : सभापति महोदया, पंजाब आज हिंसा, संघर्ष और अविश्वास की गिरफ्त में है और सारा देश इससे प्रभावित हो रहा है और हमारे राष्ट्र की एकता खतरे में है और केवल राष्ट्र की एकता ही खतरे में नहीं है बल्कि हमारे समाज का जो ढांचा है और हमारे समाज की जो मान्यताएं हैं, वे भी लुप्त होती जा रही हैं। इसके साथ ही साथ जो परिवार है, वह परिवार भी टूटता जा रहा है। समाज की मान्यताओं में बिगड़ाव तो आ ही रहा है, साथ ही साथ हमारे देश में जो परिवार का ढांचा है, वह भी टूटता सा नजर आ रहा है और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो इससे केवल हमारा जनप्रतिनिधि ही चिन्तित नहीं है बल्कि आम जनता भी इससे चिन्तित है। साथ ही साथ यह एक ऐसा मसला है जिससे केवल पुरुष ही इससे चिन्तित नहीं हैं बल्कि हमारे देश की जो महिलायें हैं, वे इस से और भी ज्यादा चिंतित हैं। वैसे तो अभी इस सदन में जितनी चर्चा हुई हैं वे राजनीतिक चर्चाएं ही हुई हैं। मैं सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहती हूं।

कुछ महीने पहले जब इस तरह की वारदातें बढ़ने लगीं, तो हमारे देश की महिलाओं ने ऐसा विचार किया कि जब इस तरह के खतरे देश पर उपस्थित हो गए हैं, तो जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और समाजसेवी जो महिलाएं हैं, उन्होंने यह विचार किया कि वे पवित्र नगर अमृतसर जाएं और वहां जाकर जो स्वर्ण मंदिर है, वहां पर लोंगोवाल साहब से बात करें कि किस तरह से देश में भाईचारा वापस आए। जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं और समाजसेवी महिलायें वहां गई थीं, वे राजनीति से प्रेरित होकर वहां नहीं गई थीं, बल्कि समाज सेवा से प्रेरित होकर गई थीं। उन समाजसेवी संस्थाओं में तकरीबन 100 के करीब महिलाएं वहां गई होंगीं। वहां जाने के बाद जब हम लोग स्वर्ण मंदिर में गए, तो वहां पर हमें कुछ ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलीं, जिनको देखकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ। जब हम लोग मंदिर में गए और लोंगोवाल साहब के सामने प्रस्ताव रखा कि देश में किस तरह से शांति और व्यवस्था कायम रहे, तो राजनीति से प्रेरित हो कर ये संस्थाएं वहां नहीं गई थीं। जब हम लोग वहां पहुंचे, तो वहां हमने देखा कि श्री सुरजीत सिंह बरनाला वहां उपस्थित थे और राजेन्द्र कौर, जो राज्यसभा की सदस्य हैं, वे भी वहां पर थीं और सबसे बड़ी बात तो हमें यह देखने को मिली कि वहां पर विदेशी पत्रकार बहुत सारे भरे थे और विदेशी पत्रकारों में

केवल पुरुष ही नहीं थे बल्कि महिलायें भी थीं। जब हमने उनको वहा देखा, तो हमने लोंगोवाल साहब से कहा कि जब हम आपके सामने कोई राजनीतिक बातें करने नहीं आए हैं, तो ये जो पत्रकार हैं, जो विदेशी पत्रकार हैं उनको यहां से क्यों नहीं हटाया जाता है। हम लोगों के अनुरोध करने पर उनको वहां से हटाया गया। उसके बाद हम लोगों ने उनसे बातें की और हमें कुछ ऐसा लगा कि उनका रुख शांति व्यवस्था की तरफ नही था और न ही वे यह चाहते थे कि किसी तरह से राष्ट्र की एकता कायम रहे। वे केवल राजनीति की बातें ही करते रहें और प्रधान मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते रहे।

जब हम वहां शहर में पहुंचे और उसके बाद मंदिर में गये तो हमने मंदिर के बाहर और शहर के अन्दर ऐसा वातावरण देखा जिससे ऐसा महसूस हुआ कि वहां सभी वर्ग के लोग, सभी सम्प्रदाय के लोग जो कि अर्थ सम्पन्न हैं, असुरक्षा की भावना से ग्रसित हैं और असुरक्षा की भावना को और भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस असुरक्षा की भावना को इससे और भी बल मिल रहा है कि सिखों के धर्म के सम्बन्ध में नई व्याख्या की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि सिख एक अलग कौम है। हिन्दुओं और सिखों के सम्बन्ध में जो यह व्याख्या की जा रही है उसमे इस प्रकार का वहां वातावरण पैदा हो रहा है। ये सारी बातें हम लोगों के देखने में आई। जब हम मंदिर के अन्दर गए तो श्रद्धा और आस्था का जो भाव मंदिर जाने वालों में होता है तो उस आस्था और श्रद्धा का अभाव हमने देखा। ऊपर से लोग बहुत शांत दिखाई पड़ते थे लेकिन ऐसा लगता था कि एक भय का वातावरण वहां विराजमान है। जब हम लोग अन्दर जा रहे थे तो हम लोगों ने हथियार वाले लोगों को भी देखा। जब हम दरबार साहिब के पास पहुंचे और उनके सामने नतमस्तक हुए तो वहां हमने औरतों को भी देखा। जब हम फेरी लगाने लगे तो लगभग 70-80 महिलाएं और भी फेरी लगा रही थीं।

सभापति महोदय : विस्तार में मत जाइये।

श्रीमती कृष्णा साही : हमने जो वहां देखा है, वही हम बता रहे हैं। वहां पर जहां कि श्रद्धा और आस्था की बात होती है वहाँ हथियार बन्द लोग भी उपस्थित थे। इन सब बातों को देखकर हम समझ नहीं पाये कि यह सब क्यों वहां हो रहा है। आज यह कहा जाता है कि यह जो सब कुछ हो रहा है उसमें विदेशी लोगों का हाथ है। अगर उनका इसमें हाथ नहीं है तो उस मन्दिर में हमें विदेशी लोग देने को कैसे मिले।

सभापति महोदया, आज एक नई बात सुनने में आती है कि सिख एक अलग राष्ट्र है। क्या हमारे देश में अनेक राष्ट्र बसते हैं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं सभी लोगों से, विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों से भी दरख्वास्त करूंगी कि जब इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और हमारे राष्ट्र की एकता को खतरा उत्पन्न हो रहा है तो हम सब लोगों को एकसाथ मिल कर इसका सामना करना चाहिए। आजादी से पहले भी, किस तरह से भारत में मुस्लिम लीग की तरफ से दो राष्ट्रों की मांग आई थी और उसका फल हमें भोगना पड़ा। आज इस देश के कुछ मुट्ठीभर लोग ही सही, सिख राष्ट्र की बात करते हैं। ऐसी बातें हमारे राष्ट्र के टुकड़े-टुकड़े कर सकती हैं।

जैसा कि कहा जाता है कि कांग्रेस की सरकार इनसे टकराव चाहती है। कांग्रेस की सरकार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है। इस बात से यह चीज़ सिद्ध हो जाती है कि हमारी सरकार की यह हमेशा इच्छा रही है बातचीत के द्वारा यह मसला हल हो जाए। इसीलिए सरकार निमंत्रण देती है, लोंगोवाल को भी निमंत्रण देती है कि आकर बातें करो। लेकिन बात तो दोनों तरफ से ही हो सकती है। लेकिन उनकी तरफ से बातचीत के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। हमारी सरकार तो ऐसी परिस्थितियां बनाये रखना चाहती है कि जिससे यह मसला बातचीत के द्वारा हल हो जाये। अगर वे हमारी सरकार को रचनात्मक सहयोग देने को तैयार होंगे तो हमारी सरकार हमेशा ही उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं।

जब अकाली दल सत्ता में था तो उन्होंने कभी इसकी मांग नहीं की, कभी मोर्चा नहीं लगाया। लेकिन हमारी प्रधान मंत्री जी जब पटियाला में कपूरी गांव में केनाल का उद्घाटन करने गयीं तो उसके बाद से यह मोर्चे का तमाशा शुरू हुआ। मैं यह कहना चाहती हूं कि वहां भी लोगों को यह कहते हुए पाया गया कि ये मुट्ठी भर लोग ही यह तमाशा कर रहे हैं और बाकी कोई आदमी यह नहीं चाहता कि देश का बंटवारा हो। वे यह भी जानते हैं कि खालिस्तान से उनको कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। उनको जो आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं वे खालिस्तान और अलग राष्ट्र बनने से मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं कि आरोप-प्रत्यारोप को छोड़कर हम सबको मिलकर राष्ट्र की एकता को बनाने के लिए, अखंडता को बनाने के लिए प्रयास करना है।

MR. CHAIRMAN : Now, Mr. Bahuguna may speak.

The time fixed for the debate was up to 8 O'clock. Now there are about 8 speakers. So would you like to extend the time ?

SHRI H.N. BAHUGUNA : We will continue tomorrow.

MR. CHAIRMAN : No, no. Today only we have to finish it. So, how long the House should sit ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Till it is disposed of.

MR. CHAIRMAN : Up to 10 O'clock. Is it all right ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : How many speakers are there still ?

MR. CHAIRMAN : Eight persons.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Then the Motion will be put at 10 O'clock.

SHRI GEORGE FERNANDES : At 11 O'clock.

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अगर 10 बजे तक हो जाए तो ठीक है नहीं तो और समय बढ़ा देना।

MR. CHAIRMAN : Yes, we will continue.

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : माननीय सभापति महोदया, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने और अपने दल के विचार इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर रखने का अवसर मिल रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए अगर सभी के विचार इस पर आ जाएं तो अच्छा रहेगा।

मुझे इस बात का बहुत खेद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जब इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर इस सदन में बहस हो रही है—जिसके बाबत उनको चिन्ता है और उन्होंने अपनी इस चिन्ता को धरती से लेकर हिमालय की ऊंचाई तक प्रकट किया है, उनकी इस चिन्ता का सुबूत उनकी अनुपस्थिति से कुछ उल्टा ही मिल रहा है। लगता नहीं है कि उनको कुछ चिन्ता है। पहली बात तो यह है कि इतने बड़े राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर सारे विपक्ष की तरफ से कुछ बातें बोली जा रही हों और वे यहां न हों, इससे क्या साबित होता है ? मुझे याद है कि एक बार अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो उन्होंने विरोधी दल के नेताओं पर चार्ज लगाया था कि कई बार सदन में जब हरिजन की बात आती रही है वे लोग सदन में नहीं रहते। मुझे अफसोस है कि प्रधान मंत्री की अनुपस्थिति का यह कोई पहला मौका नहीं है। असम पर चर्चा हुई तब भी वे यहां नहीं थीं। पिछली मरतबा पंजाब की बात हुई तब भी वे यहां नहीं थीं और आज जब पंजाब की बात हो रही है तब भी वे यहां नहीं हैं। अब भारत की जनता समझ ले कि चिन्ता किसको ज्यादा है। 80 साल के बूढ़े चरण सिंह जी को ज्यादा है या 66 साल की प्रधानमंत्री जी को ज्यादा है। इस बात को वे लोग भी समझ लें जो यहां बैठे हुए हैं।

वे यहां होतीं तो दो फायदे होते। एक तो बहस सारगर्भित हो जाती। कोई निर्णय लेने का रास्ता निकलता और मूल बात यह है कि उनको इस समाचार पर जिन बातों का ज्ञान है उसकी जानकारी सदन और देश को होती, क्योंकि शुरू से ही सारे मामले के हर पहलू से उनकी वाकफियत रही है और उनकी जानकारी का लाभ इस सदन को मिलता। हम लोग जहां गलत होते, वह उसको ठीक करतीं और जहां वे समझतीं कि हमारी बात में कोई शक्ति है, उसको वे स्वीकार करतीं। इसलिए मुझे बहुत दुख है कि इतने रास्ट्रीय महत्व के प्रश्न की चर्चा के समय वे अनुपस्थित हैं। उनकी अनुपस्थिति हम लोगों को खटकती है और यह रवैया खटकता रहेगा। जब तक उनका यह रूख सदन के प्रति रहेगा तब तक हमें यह शिकायत उन से बराबर बनी रहेगी।

20.30 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

PROF. N.G. RANGA : There is no question of disrespect or anything. The Home Minister is there.

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : रंगागारू से मैं बहुत प्रभावित हूं और आज से नहीं अपने बाल्य-काल से हूं क्योंकि वह जितनी भक्ति और श्रद्धा देश के प्रश्नों में रखते हैं, विचार यहां बैठे सुनते रहते हैं, उसको देखते हुए मुझे पूर्ण भरोसा है कि वह इन विचारों को सुनने के बाद जो विचार बनाते होंगे या एक दो बुजुर्ग और हैं वे बताते होंगे वे शायद अकेले में प्रधान मंत्री जी को उनकी उप-स्थिति के बारे में भी बताते होंगे। उनकी चिन्ता और सद्भावना देश के प्रति इसकी प्रतीक है। हमारी उम्र वालों को उनसे सबक लेना चाहिए। नेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान मंत्री को अगर वह समझा सके तो जरूर समझा दें। उनके पूज्य पिता जी श्री जवाहर लाल नेहरू जब उनको लकवा भी हो गया था उन दिनों में भी वह यहां इस सदन में मुख्य प्रश्नों के वक्त बैठे रहा करते थे। वह वहां बैठा करते थे। अगर आज वह होते तो उन्हें आज भी उस जगह से बैठा देखते। जब भारत पर चीन का आक्रमण हुआ था, तब उस प्रश्न पर जब यहां बहस हो रही थी और सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था, तब तबीयत खराब होने के बावजूद भी वहां बैठकर वह शख्स बराबर घंटों-घंटों बहस को सुनता रहा, बैठा रहा। उनके नाम पर प्रधान मंत्री को राज मिला है। परिवार के कारण राज मिला है। लेकिन पिता के रास्ते पर चलने का मन नहीं बना है। खैर यह अलग बात थी। मैं कहता नहीं। लेकिन रंगागारू ने याद दिला दिया इसलिए थोड़ा बोलने का मौका मिल गया (**इण्टरप्शंज**)।

उनको मैं लीडरों का लीडर मानता हूं। जब प्रधान मंत्री जी का जन्म राजनीति में नहीं हुआ था तो वह जेल गए थे। उसको आप छोड़ दें। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। बदकिस्मती से प्रधान मंत्री वह हैं नहीं। मैं क्या करूंगा। वह मेरा कसूर तो है नहीं।

मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमारा जरा भी तनिक भी यह मन नहीं है कि हम यह कहें कि उधर का दोष है या इधर का दोष है। एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देश की अखण्डता का नारा हर बार बे-मौके, या अपनी भूल छुपाने के लिए लगाना ठीक नहीं है। कहने में शर्म आ रही है मुझको लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि स्वराज्य के लिए मैं भी लड़ा हूं, शैलानी जी जब बच्चे थे कि 1934 में मद्रास सरकार ने तत्कालीन अंग्रेजी राज्य के जमाने में कृष्णा के पानी को लेकर झगड़ा था। मद्रास राज्य के सामने प्रस्ताव आया कि सैक्रेटरी आफ स्टेट को मामला आर्बिट्रेशन के लिए भेज दिया जाए। तब गवर्नर इन काउन्सिल ने लिखकर भेज दिया कि हमें तुम्हारा फैसला नहीं चाहिए। हम तो फैड्रल कोर्ट के जज से फैसला लेंगे। अंग्रेज की उदारता आप देखिए, गवर्नर इन काउन्सिल का फैसला आप देखिए, सैक्रेटरी आफ स्टेट ने जरा नहीं कहा कि मेरा फैसला मानो, मैं पंच बनूंगा।

1966 में पंजाब का बंटवारा हुआ। प्रधान मंत्री को क्या मालूम नहीं था कि पानी का भी बंटवारा करना है, तब क्या पता नहीं था कि उसका जो कैपिटल है उसका भी निर्णय होना है। पानी के बंटवारे के सिलसिले में भूल जाइये कि लौंगूवाल साहब क्या कहते हैं या अकाली दल वाले क्या कहते हैं। आप याद करें कि आपने क्या किया है। 1956 में एक कानून भारत में बना—इंटर स्टेट वाटर डिसप्यूट्स एक्ट। 1969 में वर्तमान प्रधान मंत्री के नेतृत्व में इस सदन ने उसको एमेंड किया। उसमें क्या यह प्रावधान है कि अगर दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों में पानी के बंटवारे के बारे में झगड़ा हो तो कैबिनेट फैसला करे? यह कहीं नहीं लिखा है। कैबिनेट तो कहीं उसमें आती ही नहीं है। तसवीर में वह आती ही नहीं है। उसका कोई वजूद ही नहीं है। ऐसा हो तो फैसले के लिए उसको जाना चाहिए ट्रिब्यूनल में और ट्रिब्यूनल का कम्पोजीशन भी उसी अधिनियम में दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि केन्द्रीय सरकार चिट्ठी लिखेगी चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट का जज वह नियुक्त करेंगे और दो जज और होंगे जो दोनों सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं और हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं। मंत्री महोदय जब उत्तर दें तो तीन बातें इस सम्बन्ध में मैं उनसे जानना चाहता हूं। 1966 से अब तक इंटर स्टेट वाटर डिसप्यूट एक्ट के मातहत पंजाब और हरियाणा के पानी के विवाद को हल करने के बजाय आप गुत्थी क्यों उलझाते रहे हैं? मान्यवर, मुझे क्षमा करेंगे शासक दल के नेता इतने काबिल हैं कि "इनकी सीस्त देखिये जब सुलझ जाती है गुत्थी, तो फिर उलझा देते हैं यह" मेरा जानना है कि प्रधान मंत्री ने अपने ऊपर यह जिम्मेदारी क्यों ली? वैसे ही बहुत आप पर काम है, सेहत अच्छी नहीं है। इण्टर स्टेट वाटर डिसप्यूट एक्ट में लिखा है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखें। 1966 से अब तक फिर आप अपने अधीन इस मसले को क्यों उलझाए हुए हैं? आपको इण्टर स्टेट वाटर डिसप्यूट एक्ट के मातहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखना चाहिए था कि वह ट्रिब्यूनल बनायें जिसका चैयरमैन सुप्रीम कोर्ट का जज हो और दो जज और चाहे हाई कोर्ट के या दोनों सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं।

दूसरा सवाल यह है जब लोगों की ट्रांसफर आफ जजेज के बाद हाई कोर्ट के जजों के सम्बन्ध में तरह-तरह की मन में धारणाएं बन रही हैं, डरे हुए हैं लोग, तो उस हालत में लॉ में प्रोवीजन है कि

(व्यवधान)

तो मंत्री जी बतायें कि आज इस वाटर डिसप्यूट के लिए जो ट्राइब्यूनल वह सोच रहे हैं उसके लिए वह चीफ जस्टिस को लिखेंगे कि नहीं? चाहें तो तीनों जज सुप्रीम कोर्ट के ही रखिए, चेयरमैन भी और दो मेम्बर भी, या चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का जज हो और मेम्बर हाई कोर्ट के जज हों।

मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि ट्राइपारटाइट कमेटी में जिन बातों पर सब लोगों का मतैक्य हो गया और 30 जून की विपक्षी दलों की मीटिंग में उस दिन के प्रस्ताव में बात बैठ गई कि अब पानी का झगड़ा राजस्थान से नहीं है, हिमाचल प्रदेश से नहीं है, तो आप मान्यवर समझाइये शासक दल को कि कह कहकर वह अकालियों को जबरस्ती याद न दिलायें कि तुम्हारे और भी झगड़े हैं, कुछ और भी झगड़े करो। वह कहते हैं हमको नहीं लड़ना है। राजस्थान से 1955 वाला फैसला आखिरी मानते हैं, ट्राइपारटाइट कमेटी में बात हो गई। और अगर अकाली दल इसको नहीं मानेगा तो सदन के सभी पक्षों की राय उनके खिलाफ होगी। विरोधी दल में कोई नहीं है जो पानी के मसले पर हरियाणा और पंजाब के अलावा बात करने के पक्ष में हो। क्यों है इस पक्ष में? उसका कारण है, इसलिए नहीं कि लड़ाई है...

(व्यवधान)

एक सज्जन कह रहे थे आप तो आग में घी

डाल रहे हैं। हम तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि माननीय चिरंजीलाल शर्मा मेरे मित्र हैं, मैं नहीं देख रहा हूं उन्हें यहां अभी, पानी का झगड़ा इसलिए बोलते हैं, हमारी तरफ से कोई झगड़ा नहीं है, माननीय चिरंजीलाल शर्मा ने आंकड़े पढ़े तो हर बार झगड़ा हरियाणा का पानी का ही होता चला गया। या कहिये हरियाणा और पंजाब के पानी का झगड़ा अगर नहीं है तो कोई क्वान्टिटी एक ही बार में तय क्यों नहीं हो गई ?

दूसरी बात 1976 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो जब सेन्ट्रल कैबिनेट ने इस मुद्दे पर फैसला किया तब तत्कालीन मुख्यमत्री, ज्ञानी जैल सिंह ने, जो आज राष्ट्रपति हैं, क्या उन्होंने पंजाब की ओर से यह नहीं कहा, चिट्ठी लिखकर, कि यह फैसला मुझको मंजूर नहीं है। उनका पत्रक प्रधान मंत्री के सचिवालय में मौजूद है और उसी के आधार पर जब जनता पार्टी का राज्य आया तो अकाली दल वालों ने कहा कि हमारा समझौता नहीं हुआ। मौरार जी भाई ने कहा तुमने आर्मिट्रेशन में दे दिया प्रधान मंत्री के। उन्होंने कहा हमारी तरफ से, पंजाब की तरफ से नहीं गया, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह का विरोध पत्र मौजूद है पानी का बंटवारा अन्यायपूर्ण हुआ है पजाब की दृष्टि से। हमारी समस्या यह है कि हमारे माननीय स्टीफन साहब या दूसरे जो शासक-दल वाले लोग हैं, उनको हरियाणा भी दिखता है, पंजाब भी दिखता है, हमको सिर्फ भारत दिखता है। आप सब देखते रहोगे, सब खो जाओगे, हमको चिड़िया की आंख दिखती है कि भारत रहेगा या नहीं। अगर भारत नहीं रहेगा तो कोई रहनेवाला नहीं है।

सवाल यह है कि पानी के विवाद का एकतरफा फैसला आपने एमरजेंसी में किया। वहां आपके ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका फैसला गलत है। अब आप हमें गाली क्यों दे रहे हैं कि पानी का झगड़ा है ? पानी का झगड़ा है तो हल क्यों नहीं किया ? आप कानून के मुताबिक फैसला करो। सरकार कहती है कि जो मनमानी होगी करेंगे। 'रूल आफ मैन, खत्म करो, 'रूल आफ लाज़' चालू करो। विरोधी दल ने पानी के झगड़े पर कौन सी बात विवादास्पद बोली है, गलत बोली है ? विवाद की जड़ तो उस तरफ बैठी है और इस वक्त गैर-हाजिरी है।

श्री धर्मदास शास्त्री : जब भारत दिखता है तो भारत के लोग ही पानी पी रहे हैं। भारत को देखने वाले पानी को क्यों बांट रहे हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय धर्मदास जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि वह सब को पानी पिला रहे हैं। मेरा कहना यह है कि पानी के विवाद पर आपको यह उत्तर देना होगा कि मुख्य मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने उजरदारी की थी या नहीं ? और की थी तो उस वक्त आपने उस विवाद को सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं भेजा ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपने क्यों नहीं फैसला किया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हमारे यूथ कांग्रेस (आई) के नेता, बाल कांग्रेस के नेता, हमारे मित्र जिनका मैं आदर करता हूं, वह मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं फैसला किया ? मैं तो इतनी ही बात जानता हूं कि उस जमाने में तत्कालीन सरकार कुछ बातों को, मान्यताओं को आधार मानकर चली और जहां मान्यता नहीं मानी उसमें थोड़ी चोट भी खा गई।

श्री गिरधारी लाल व्यास : वहां पर अकाली दल ने माना ही नहीं, इसलिए फैसला नहीं हो पाया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आपको पता नहीं है, मत बोलिए।

उस सरकार ने कहा कि पिछली सरकार ने निर्णय किया है। जब बादल साहब चीफ मिनिस्टर हो गये तो उन्होंने अपनी मिसल में से ज्ञानी

जैल सिंह का पत्र निकाल लिया और मोरारजी भाई को कहा कि पत्र हमारे पास मौजूद है। मोरारजी भाई ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ और सुप्रीम कोर्ट में वह केस चला गया।

1980 में जब भजनलाल जी ने अपनी भजन-मण्डली के साथ इधर का परित्याग कर उधर शामिल हो गए तो उन्होंने दरबारा सिंह जी के दरबार को और अपने दरबार को मिलाकर उस निर्णय को इंदिरा जी के दरबार में ले गये और सुप्रीम कोर्ट से केस वापिस हुआ। एक निर्णय फिर हुआ और उसी निर्णय को अकाली दल ने कहा है कि हमारे साथ ज्यादती है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, ये इतने बड़े नेता हैं, ये इन्दिरा जी का दरबार बोलते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। उनका आफिस होता है, दरबार नहीं होता है। दरबार तो राजा-महाराजाओं का होता। इन्हें यहाँ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा: राजाओं के भी बाप से बेटा और बेटे से बेटा होता है। आजकल तो हम यहां भी दरबार ही देख रहे हैं। हमारे रेड्डी साहब जिस सूबे से आए हैं, उसी सूबे के एक मुख्यमंत्री ने, इंदिरा कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने एक टोपी बनवा ली थी निजाम की तरह की और ऐसा दरबार लगाया था जिसमें माननीय रामगोपाल रेड्डी भी शामिल हुए थे।

(व्यवधान)

बैठो, नहीं तो और बातें भी याद दिलाऊंगा।

दूसरा कहना यह है कि चण्डीगढ़ का विवाद। क्या विरोधी पक्ष ने यह विवाद पैदा किया है यदि हां, तो हम जिम्मेदार हैं। जहां तक पंजाब को बांटने का प्रश्न है उसके लिए प्रस्ताव किसने पास किए थे? क्या विरोधी दल के किस किस दल ने? सी. पी. आई., सी. पी. आई. (एम) सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने? यह सारे का सारा मामला राजनीति से प्रेरित होकर चला और पंजाब का बंटवारा हो गया।

बंटवारा तो हुआ इस देश में कई राज्यों का, मैं अपने बंधुओं से कहूंगा, कुछ कह रहा हूं सुन लो, फिर मौका समझने का नहीं मिलेगा। (**व्यवधान**)

स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने इस देश में कई राज्यों का विभाजन किया, भाषा के आधार पर राज्य बने। मद्रास स्टेट के दो राज्य बन गए—तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। लेकिन उनमें राजधानी के लिए झगड़ा नहीं हुआ। नार्मल शक्ल में मद्रास उसको चला गया। इसी तरह से जब महाराष्ट्र बना तो बम्बई उसके साथ चला गया। लेकिन जब पंजाब और हरियाणा बने तो एक नई बात पैदा हो गई। राजधानी के बंटवारे का सवाल क्यों उठा दिया गया? अगर उठा ही था तो उसी दिन निर्णय कर देते और कह देते कि हरियाणा को देना है चंडीगढ़। लेकिन लोगों का सिद्धांत यह है कि, लोगों में फूट डालो और राज करो, अगर कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा तो दिल्ली को पूछने कौन आयेगा। तो वही लोग झगड़े कायम रखते हैं। हमारा वर्तमान संविधान जो है उसमें इतनी बातें राज्य सरकारों के लिए हैं कि राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में काम करें और हस्तक्षेप दिल्ली से न हो तो दिल्ली कुछ कर नहीं सकती है लेकिन उसके लिए अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री पर काबू रखने के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट रूलिंग पार्टी ने ईजाद किया है जिसको कहते हैं 'डिसीडेन्ट्स'। डिसीडेन्ट्स चीफ मिनिस्टर के पीछे लग जाते हैं जैसे कि किसी की दुम में कनस्तर बंध जाता है और वह फटफट बजता रहता है। चीफ मिनिस्टर दिल्ली आकर कहते हैं कि कनस्तज खोल दो। वरना हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में किसी चीफ मिनिस्टर को रोज-रोज दिल्ली दरबार में आने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय: समय का भी खयाल रखिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : लोगों ने 50-50 मिनट बोला है। मैं एक भी निरर्थक बात नहीं बोलूंगा और कोई बात दोहराऊंगा नहीं। एक ज़माने में मेरी बात पर आप चलते थे। (**व्यवधान**) लेकिन उस वक्त या इस वक्त का सवाल नहीं है। चंडीगढ़ के कैपिटल के मामले पर, जब पंजाब और हरियाणा अलग हुए, उस दिन निर्णय देना था। यह निर्णय विरोध पक्ष को नहीं देना था, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर या उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को नहीं देना था, यह निर्णय भारत की सरकार को देना था जिसको केन्द्रीय सरकार बोलते है हालांकि केन्द्र (सेन्टर) का शब्द संविधान में कहीं नहीं है। वहां पर यूनियन गवर्नमेंट है। यह गलत शब्द प्रयोग में आ गया। जब आ गया तो चल भी गया। यह केन्द्र कहां का है? यह केन्द्र वह है जो विकेन्द्रित करने के लिए बिलकुल तुला हुआ है। टूट-फूट, बिखराव, विघटन करने के लिए तुला हुआ है। वाजपेयी जी बैठे हैं, मैं डरता हूं कहीं गलत शब्द प्रयोग न कर जाऊं।

तीसरा सवाल यह है, जैसा मैंने कहा कि जिस प्रदेश के नाम से राजधानी बनी और शरणार्थियों को मिलने वाले रुपयों से बहुत सारा काम बना और उसके अलावा बोली, पंजाबी भाषा के आधार पर प्रदेश बन रहा था तब चंडीगढ़ की भाषा क्या पंजाबी नहीं थी आज भी अमृतसर के सर्किट हाउस में जितने भी कर्मचारी हैं वे हिन्दू भाई हैं हालांकि सभी पंजाबी बोलते हैं। मैं जिस हिन्दू मित्र के घर में जाता हूं, भाटिया साहब यहां पर आ गए हैं उनके घर में भी आपस में जो वार्तालाप भाई-बहन, भाई-भाई और व्यापारियों में होती है वह पंजाबी में होती है। वह इसको मान रहे हैं। मेरे गढ़वाल के कई लड़के चंडीगढ़ में नौकरी कर रहे हैं, उनसे बात करी तो पंजाबी में जवाब देने लगे। मैंने पूछा आपको क्या हो गया है तो उन्होंने कहा आदत जो है, हम पंजाबी बोलते हैं। इसलिए पंजाब और हरियाणा के बीच में राजधानी का झगड़ा भी उधर की जिम्मेदारी है, इधर की नहीं है।

जहां तक आल-इण्डिया गुरुद्वारा ऐक्ट बनाने की बात है, तो उधर के माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के कह रहे थे कि विरोधी पक्ष वाले कहते हैं कि आल इण्डिया गुरुद्वारा एक्ट बनाओ। श्री निहाल-सिंहवाला जी बोल रहे थे कि अकाली लोग बड़े गड़बड़ हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि सरकार हस्तक्षेप न करे और दूसरी ओर कहते हैं कि हमारा आल इण्डिया कानून बना दो। इनको मालूम ही नहीं जितने हिन्दुओं के मन्दिर हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनाती हैं। इनको मालूम ही नहीं कि कोई ऐसा नहीं है जहां हिन्दू और मुसलमानों के धर्म स्थान के सम्बन्ध में कोई न कोई कानून न बना हो और जहां नहीं बने हैं, जैसे वाराणसी शिव मन्दिर के लिए नहीं बना था तो वहां शिव जी की चोरी हो गई और सारा सोना गायब हो गया। मैं एक बात आपके जरिए उनसे कहना चाहता हूं कि अकालियों का प्रभुत्व जो कुछ भी होगा, वह पंजाब के भीतर है। उत्तर प्रदेश में अकाली पार्टी सिफर हो जाती है। पटना में और बिहार में जाकर सिफर हो जाती है। अगर पटना साहब का या किसी दूसरी जगह का प्रतिनिधि SGPC में जाएगा तो, मैं आपके जरिए श्री अटल जी से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी में पंजाब का एक्स्ट्रीमिस्ट जो सोचता है, उसके सामने कुछ दूसरी समझ के लोग भी सामने हो जाएंगे। पटना से, बम्बई से और नागपुर तथा दूसरे स्थानों से जो इस प्रकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी में प्रतिनिधित्व होगा, वह प्रतिनिधित्व भारत के हर भाग से प्रभावित होगा और देशहित में होगी उनकी राय। यह व्यवस्था सारे देश को एक करेगी। कोई बड़ी भारी मांग वे नहीं कर रहे हैं। उनके कुछ प्रमुख गुरुद्वारे हैं। सरकार ने इस मांग और दूसरी धार्मिक मांगों को मान भी लिया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस बात को सरकार ने स्वयं मान लिया उसके लिए भी सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने विरोधी पक्ष को दोषी बताया और उसकी भी आज आलोचना की है।

मान्यवर, आज सिखों के सम्बन्ध में तरह-तरह की बातें कही जा रही है। मैंने कई बार उनसे वार्तालाप किया है। हमारे जार्ज फर्नाण्डीस

साहब ने बादल साहब का एक पत्र पढ़ा। मेरा कहना यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हिन्दुस्तान में धर्म के आधार पर कोई बंटवारा किसी भी प्रकार का स्वीकार करें। धर्म के आधार पर राष्ट्र बनते नहीं हैं। यह बात मैं यहां नहीं बोल रहा हूं। मंजी साहब दरबार में जहां जाने से निहाल-सिंहवाला डर रहे हैं और कह रहे थे मैं वहां जाने से डरता हूं, जाता नहीं हूं। वहां मान्यवर मैंने भाषण दिया है और उस जगह सारे सिख समुदाय के सामने बोला है कि धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र नहीं बना और दुनिया में वैटिकन को छोड़-कर धर्म पर आधारित एक भी राष्ट्र नहीं है। लोगोंवाल साहब की 14 जुलाई की चिट्ठी है, उसकी एक लाइन मैं पढ़ देना चाहता हूं। कोट— अखबारों में यह खबर छपी है कि सन्त जी ने कहा है कि—

> 'Sikhs are a nation' 'There is no place for Sikhs in India'

तब मैंने उनको लिखा कि सन्त जी इस मामले में आप गलती पर हैं। यह बात सही नहीं है, धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र बन नहीं सकते हैं और किसी दुनिया में भी ऐसा नहीं है। मैंने उनको यह जरूर कहा :—

> "May I appeal to you for counselling all those who are struggling for the just resolution of problems facing Punjab to spread the message of love, compassion and brotherhood while focussing attention on the demands most of which have found solution as indicated in the Resolution adopted on the 30th June and as incorporated in my letter to the Prime Minister a copy of which I had earlier sent to you."

इस पर हमने यह कहा था—

> "As one committed to work for the traditional peace and amity and uninterrupted brotherly relations between the two communities, may I in all humility register with you my views that such statements provide a handle to those who are not interested in bringing about normalcy and solution to the problems raised by your Party."

इसके साथ ही मैंने उनको साफ कहा था कि आपने जो दो नेशन्ज का सवाल उठाया है, यह चलने वाला नहीं है। इसी तरह से हमारा यह भी कहना है कि पंजाब के लोगों के साथ मैंने बातचीत की है, मैं गांवों के अन्दर भी गया, माननीय भाटिया जी का मुझे विश्वास है मेरा समर्थन करेंगे कि वहां आज भी कोई झगड़ा नहीं है। यह कहना कि यू० पी० और बिहार के मजदूर वोटर न हों, वे कहते जो भी हों लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहां सभी वोटर बन गए हैं और सबने वोट डाला है। मैंने गांवों में जाकर देखा, लोगों से बात भी की, उन्होंने मुझे बतलाया कि लोगों ने वोट भी डाला है। जो मजदूर वहां परमानेन्ट रहते हैं वे वोट डालते हैं, लेकिन जो सीजनल हैं, क्रापिंग के समय आ जाते हैं और बाकी समय में नहीं होते हैं, वे नहीं डालते हैं।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : क्या उस पत्र का जवाब आया ?

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : जवाब आया। उनसे बातचीत होने के बाद मेरा दिमाग साफ है। मैं एक बात कहना चाहता हूं— धक्का देकर वर्तमान अकाली नेतृत्व को दूर दीवाल तक मत भेजो। ऐसा न हो कि बाद में पछताना पड़े। हमने बदकिस्मती से वह भी जमाना देखा है— जब नार्थ-वेस्ट फ्रांटीयर, बिलोचिस्तान, जम्मू-काश्मीर, पूरे का पूरा पंजाब का इलाका, सब जगहों पर मुस्लिम लीग हार गई थी—मुहम्मद अली जिन्नाह की मुस्लिम लीग। पर हमने वह जमाना भी देखा है—जब 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास हो गया तो जिन्नाह साहब आराम से बैठ गए और हम लोग प्रचार में जुट गए कि पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। लोगों ने कहा कि क्यों नहीं बनने देंगे ? तब हमने समझाया

कि यह पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जगह-जगह पर भाषण करने गए, बात यह फैली जिसे हम मिटाना चाहते थे। मेरी राय है कि खालिस्तान के खिलाफ लड़ो, लेकिन जब आधा फीसदी आदमी भी खालिस्तान की मांग नहीं कर रहे है तो हम अपने से उसका प्रचार क्यों करें ?

अभी स्टीफन साहब कह रहे थे कि जार्ज साहब ने कहा था — जब अमरीका वाले आये तो प्रधान मंत्री जी ने उनसे क्या कहा, क्या बात बतलाई। मैं एक बात कहना चाहता हूं—हम तो प्रधान मंत्री जी के करीब नहीं हैं, जो करीब है और गलत राय दे रहे हैं, वे जाने, लेकिन जब प्रधान मंत्री जी बाहर के देशों का दौरा करके आयीं—युगोस्लाविया और शायद आस्ट्रिया हो कर आई थीं, आते ही बजाय यह बताने के कि "नाम" के "चेअर-परसन" के रूप में "अंकटाड" में क्या करके आई हैं, उन्होंने यह कहा—"खालिस्तान आंदोलन की जड़ और बुनियाद अमरीका में है।" जब भारत की प्रधान मंत्री यह बोलती हैं तो मैं भारत की प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं—जिस देश में वह इस देश विरोधी आंदोलन की जड़ बतलाती हैं, उस देश के साथ इस देश का संबंध रखकर वह खालिस्तान की मदद कर रही हैं या हम मदद कर रहे हैं ? प्रधान मंत्री जी इस समय हाउस में नहीं हैं, हम जानना चाहते हैं, वे हमको बतलायें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था ? हमारे माननीय इन्द्रजीत गुप्ता जी कह रहे थे कि उनके पास सबूत नहीं कि इस मसले में C I A का कितना हाथ है लेकिन हमारे पास सुबूत है। प्रधान मंत्री ने यह बयान दिया है कि अमरीका में खालिस्तान की जड़ है। प्रधान मंत्री जी से इस सदन में जवाब तलब करना चाहिए—ऐसा करने के बाद भी वह प्रेस-कम्यूनिक निकला सल्टज साहब के साथ दोस्ती वाला कौन सा झूठ है, कौन सा सच है ? इससे आशंका होती है—यह हम जानना चाहते हैं। कहीं सी०आई०ए० का नाम इसीलिए तो नहीं ले रही हैं कि देश वासियों को डराकर रखो। मैं प्रधान मंत्री जी के संबंध में यह बात किसी छेपक के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक रूप में कह रहा हूं। वह मेरी कांस्टीचूएन्सी में गई और सारी जगहों पर सिवाय पंजाब के कोई जिक्र नहीं किया।

21.00 hrs.

मैं पंजाब गया संत लोंगोवाल के पास, हिन्दुओं और सिखों की एकता कराने के लिए अपील करने और मैं इस समय कुछ बोलना नहीं चाहता लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि उसका परिणाम सामने आएगा। इस तरह से आप यह देखें कि मैं पंजाब में गया देश के लिए और प्रधान मंत्री जी मेरे क्षेत्र में गयीं वोटों के लिए। यह बंटवारा उनके और हमारे काम का था और वहां जाकर उन्होंने यह कहा कि पंजाब में गड़बड़ है। वे यहां पर क्यों नहीं बोलतीं कि पंजाब में क्या-क्या गड़बड़ है। यह सदन देश की एक सोवरन बोडी है और यहां पर वे खामोश हैं और बाहर बोलती हैं। वे सड़कों पर बोलेंगी और यहां नहीं बोलतीं, जो सदन में गूंगा बन जाए ऐसा गूंगा प्रधान मंत्री हम को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।

MR. CHAIRMAN : Mr. Unnikrishnan.

SHRI A.T. PATIL : I am on a point of order under Rule 362.

MR. CHAIRMAN : That is a closure motion. I think you were not present then. The time has been extended.

Shri Unnikrishnan.

SHRI A.T. PATIL : Sir, I move :

"That the question be put".

MR. CHAIRMAN : Mr. Patil, there is no point of order.

Shri Unnikrishnan.

SHRI K.P. UNNIKRISHNAN (Badagara) : Mr. Chairman, Sir, for the last six hours or so, we have been debating this motion for an adjournment. It concerns a very vital national issue—an issue of great national significance—for our future and for

the unity and cohesion of this country. But, Sir, as usual, it is our misfortune that while we have been debating this issue of great significance as admitted even by the Prime Minister—the Leader of the House as she is—she is unable to be present in this House to hear our points of view and to rebut them if necessary or challenge us if necessary and to explain to us the points raised. While we welcome the opportunity provided, I know we are going against the stone wall. That is the problem in this country. This is a refusal to accept certain democratic norms and certain facts of life. That is what we see. Deliberate disinformation campaign is going on in this country. The question raised here is in regard to certain demands of the Akalis, in a section of the people in Punjab (*Interruptions*).

Listening to my friends from the other side, with the exception of Shri R.L. Bhatia and Shrimati Brar, I found that there was a woeful lack of understanding ; the kind of their involvement and partisanship can prove that they will be dan aging this country and its future. This is the campaign of disinformation which has been indulged in by the leadership, by no less a person than the leader of the ruling party, the Prime Minister. That is the gravaman of my charge to-day.

I speak with great and deep concern and anxiety about the turn of events in which the Prime Minister and various other anonymous voices behind her have been playing, particularly after the Vijayawada meeting about the elections in Jammu and Kashmir. It was said that it was the Opposition who has been playing a double game with regard to events in Punjab. They have been saying different things on different occasions. (*Interruptions*) Please listen to me for a change. They have been saying different things on different occasions and playing a double game. Few weeks ago, certain Members from that side made that charge. While I do not want to speak on behalf of the Opposition, I want to pose one question with all seriousness. What are the facts concerning the objective situation in Punjab today ? Would the Prime Minister and her spokesmen answer ? Is the situation in Punjab result of a conspiracy between certain people who are making a demand and the national Opposition forces ? If so what is the contribution made by the people who have been talking like this to diffuse the situation and again what has been the role of Hindu and Sikh extremists and the communal organisations of these communities and individuals and media in escalating the crisis in Punjab ? If you say that some people have not been helpful then some people must have been working against the interests in escalating these crisis. Who are these people ? Have you identified them ? Can you name them ?

Mr. Chairman, you will forgive me if I make a point. What has been the result and impact of infighting that has been going on. You say there is a serious situation in Punjab. Is your own party in that State united on this issue ? Unfortunately, one of your leaders, an M.P. and a former Maharaja who is not present here today what has been his role and that of his friends in fanning the flames of dis-content in that State. Has the Prime Minister been able to diffuse her own inner-party crisis in that State leave alone the problem left behind ?

Sir, it is being deliberately encouraged as communal elements are being encouraged to spread and instil poison in the system. There is some method in this madness and I repeat are the Opposition parties responsible for the situation and for this an answer has to come. That is what I call deliberate disinformation.

Sir, before we go to the background of this issue even at this late hour there was an Akali memorandum to the Central Government in 1982 or so and in January, 1983 the Prime Minister called the Leaders of the Opposition to discuss these demands. According to them at that very time there were two sets of demands—one religious and the other political, territorial and so on. Now, I am happy that at least the Minister of Home Affairs, my friend Shri Sethi is here. Even at that time many of us had said that these demands be separated. Even at that time many of us specifically suggested that all political parties in Punjab and not only Akali Dal be called to discuss what are the demands of Punjab as distinct from the

religious demands of a section of Sikh community. I hope, Sethiji, will remember that some of us had warned that blanket acceptance of these demands is likely to have dangerous consequences. For example, about the demand for relay of devotional music from the Golden temple through Jullundhur AIR, I am totally opposed to this demand. If the people in this country demand then you can have a commercial transmitter. Those who want to pay—whether Sikhs or Hindus—you can make arrangements but to allow the use or misuse of this media I am totally opposed to it and I even raised in this House the point about singing of Hindu scriptures in the morning on the AIR. If you accept such a demand then certain consequences will flow from it.

Sir, before we could discuss some of these details we were told that religious demands have been settled or are being settled. We did not realise that this was a petty manoeuvre to keep the other parties divided. Then came the tripartite talks. We do not want to raise these issues at the tripartite talks. If you want to settle something, all right. We do not want to pour oil into the situation. But then it is wrong to say that we are saying one thing there and something else outside. All these parties here have asked for clear-cut definite points of view on religious demands, on territorial demands and nobody has hidden these demands. Our response to these demands when discussed publicly or during the tripartite talks was to try to help. Mr. Bahuguna and others pointed out a little while ago, when we discussed the question of Chandigarh and the River waters, we had made it very clear that we would have to discuss this question with everyone. We tried to evolve a formula after discussions. Even on the question of Akali Dal demand for river waters, all of us opposed their demand to reopen the question of Rajasthan waters. I am sure it would be borne out by those distinguished Ministers who are present here. Then, what is that we are being accused of double game ? Would they tell us ? Is this the method of solving this problem ? Did we change the stand ? Let us be honest about it.

Sir, we discussed for hours and we are discussing this question even with the Chief Ministers and the representatives of the Opposition and I dare say it was on the verge of arriving at a solution. Now, the truth is, I regret to say, that they do not want a solution. That is very crystal clear now and you want to continue with your petty politicking. But the question I want to pose today is : how long can you carry on and mislead the people with Khalistan bogey ? These kinds of tactics are bound to bounce upon you. You cannot continue the bogey of Khalistan and mislead the people for all the time. I am not for a second to justify this small microscopic section of this country supported by certain elements outside who are making this demand. But are you serious enough and can say that the majority of Sikhs, even those who are with the Akali Party, are supporting this demand for Khalistan ? And that is what I mean by this information. Is it not that the bogey that they have raised is for certain ulterior ends ?

Who patronised the hijackers, murderers and anti-social criminals ? I know them and those who continue this activity even now. I know the Congressmen from Punjab. They will tell you if ask them who have been patronising them. Are you prepared for an enquiry ? That is why I want a White Paper. I would demand from the Home Minister to come out with a White Paper on the activities of these extremists, on Dal Khalsa, on those who are advocating for Khalistan and place it on the Table of this House. The House is entitled to know and the conntry is entitled to know these things. We should know who are the people why have been operating and supporting them. That is why I demand a White Paper on this.

My friend, Mr. Indrajit Gupta said that these are the questions of importance which arise and which can turn the entire position, which can make a deep impact on the future course of event. That is why, with great regret, he referred to the problem that many Sikh gentlemen on the roads of Haryana on the eve of the Asiad—I have been a witness to this myself—where decent and honest Sikh gentlemen, had been stopped on the roads by the Haryana Police

and asked them even to remove their 'turbans', the humiliation the Sikhs had to suffer from. You go and ask Mr. Bhajanlal. The humiliation and the insult that were meted out to Sikhs, have completely altered the outlook of many people, those who are nothing to do with the Akali demand, even those who are opposed to Khalistan demand.

Now, who is helping the Hindu Suraksha Samiti ? Who is encouraging them ? Who is Pandit Mohanlal to whom I have a great respect ?

Is he a BJP leader or is he a Congress(I) leader ? Who is Pawan Sharma ? I want my friends from the Congress(I) to please ponder over this very seriously that the lines of demarcation between Hindu communalists and certain sections of Congressmen in Punjab are fast disappearing and there is again a method of madness. In this madness there is a dangerous and devious attempt to improve the sagging electoral fortunes of this ruling Party. That is the new thrust. You can play this game. You can win an election. You can get some votes. That is why, Sir, the President of the Vishwa Hindu Parishad and Mr. Vajpayee's friend, Maharana of Udaipur, has come out with a statement that Shrimati Indira Gandhi alone can fight the anti-national elements. He said this soon after the Meerut riots. Now, he has repeated this again. Who are these anti-national elements ? The anti-national elements, according to the President of the Vishwa Hindu Parishad are the people who refuse to be Hindus who refuse to accept the big protective umbrella of Hinduism. So, he is a serious man and I know he means it seriously. That is why he says the approach behind this is—I regret to say—Hindu-Hindi-Hindustan. This is a concept which Congress had never accepted and opposed. The Nationalist Movement had opposed it, Mahatma Gandhi had opposed it, Jawaharlal Nehru had opposed it and all progressive people in the country and democratic forces in the country had opposed it. But that is exactly the electoral thrust that is being given to the strategy now.

Before I conclude, Sir, I want to say if there is deep-seated fear amongst the sections of minorities—whether they be Muslims or the Sikhs—even if it be wrong, it is the duty of those secular leadership, the national leadership, to see that they do not suffer from these infirmities.

SHRI MANI RAM BAGRI : In Punjab Hindu is in minority.

SHRI K.P. UNNIKRISHNAN : There is a genuine feeling among the section of Sikhs, whether it is right or wrong, that their distinctiveness and character may be threatened and overwhelmed. It may be wrong, but the feeling is more important.

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude.

SHRI K.P. UNNIKRISHNAN : Therefore, we have to solve the question of deep-seated fear. Similar is the question of language and script. These are important. If some people refuse to say—as Indrajit Gupta accepted the fact—that their mother tongue is Punjabi they are only contributing to the communal factions in the State.

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude.

SHRI K.P. UNNIKRISHNAN : Please don't disturb.

Similarly, about the question of the All India Gurudwara Act. Here I don't agree with Shri Bahuguna. Sir, Pratap Singh Kairon, the greatest leader Punjab had produced in the 20th century, the great statesman that he was, he had once made a suggestion—Mr. Buta Singh may remember—regarding the S.G.P.C. He said clearly that all political activists, whether they belong to Congress or Akali Party or any other Party, be debarred from holding any post in SGPC. The whole system of regulating the Gurudwaras under the Act of 1925 is a kind of anomaly in the context of our nation being a secular State. And to add more and take on more responsibilities can only mean getting involved in more future complications. Sir, I wish to say it was a tragic misunderstanding on the part of the States Reorganisation Commission not to have solved these questions then. And since, as somebody pointed out now, you even refused to accept or that

you have forgotten the Sacchar formula which can solve many of these questions. We have continued and we continue to be loaded with other territorial questions.

There is no question ; I regret to see how the Prime Minister could think even for a moment of dividing Chandigarh which is, above all, an internationally-accepted architectural concept to destroy which, for the sake of some kind of a political demand is a disastrous thing.

21.20 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

I would again appeal to the Home Minister. I was happy to read what he said yesterday in the Rajya Sabha. I want to repeat what I said earlier : the events in Punjab have reached a point when there is a perilous drift to the precipice. It can fracture our national cohesion, and endanger our national unity and national security. I only hope that small political considerations will not come in the way of making another serious attempt to solve this problem once and for all.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now Mr. Sultanpuri.

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जब हम पंजाब पर बहस कर रहे हैं तो सोचना पड़ेगा कि यह मसला क्यों शुरू हुआ। पंजाब से ही हरियाणा निकला, हिमाचल का कुछ हिस्सा पंजाब में से निकलकर मिला, लेकिन कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई कि हिन्दू और सिख कभी लड़े हों। लेकिन बदकिस्मती यह है कि कुछ लोग इसको उकसाते हैं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। प्रधान मन्त्री को बदनाम करना तो इनका काम रहा ही है, लेकिन अब तो होनहार नेता, श्री राजीव गांधी को भी बदनाम कर रहे हैं। इस तरह की बेबुनियाद बातें करना इनको शोभा नहीं देता।

जहां तक देश की हालत को बेहतर करने का सवाल है अगर पंजाब में कोई गड़बड़ होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर तो आती है, लेकिन आपका भी फर्ज होता है कि वहां के लोगों को बहकाएं या उकसाएं नहीं। आप अपने नेताओं से कहिए कि इसको बन्द करें। हमारे पंजाब के अन्दर हिन्दू और सिख कभी नहीं लड़ते थे। लेकिन आज जो हालत खराब हो रही है वह चिन्ता का विषय है। यह उग्रवादी कहां से पैदा हो रहे हैं। यह 1970 के बाद पैदा हुए। पटियाला और ईस्ट पंजाब एक स्टेट थी और उसमें आठ रियासतें शामिल की गई थीं और शिमला से लाहौलस्पीति तक सारा पंजाब में था। सन्त फतेह सिंह ने अपनी आहुती देने की बात कही एक करार रखकर, लेकिन कामरेड राम किशन की सरकार ने और कैरों साहब ने यह नहीं होने दिया। माननीय सेठी जी आप होशियार हो जाइए, यह सारे देश का मसला है और इसके लिए सख्ती से भी पेश आना पड़ा तो झिझकना नहीं चाहिए। आपको कामयाबी तब तक नहीं मिलेगी जब तक सख्त कदम नहीं उठाएंगे। सभी उग्रवादी लोगों को खत्म किया जाए चाहे वह किसी दल के हों। इसमें हमारी सुरक्षा है। कोई आदमी नहीं पकड़ा जाता है, सब गुरुद्वारों में चले जाते हैं। 3 आदमी मोटर साइकिल पर चढ़ कर निकल जाते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं। जो पकड़े जा रहे हैं, वे सबके सब गुरुद्वारे में बैठे हैं। ऐसे धार्मिक स्थान हमको नहीं चाहिए जिसमें क्रिमिनल रहते हों, कत्ल करने वाले रहते हों। यह कोई ढंग नहीं है कि इस तरह के आदमियों को टौलरेट किया जाए। मैं सरकार से अपील करूंगा कि जहां और बातें हैं, वहां उनको भी समझना है लेकिन जो दुश्मन ताकतें हैं जो गुरुद्वारों में छिपने की कोशिश करती है और उनको बदनाम करती हैं सारे संसार में, उनसे आपको निबटना पड़ेगा, यह आपका काम है। जो बयान सरकार ने दिया वह काबिले-तारीफ है और प्रधान मंत्री जी भी इस बात के लिए चिंतित हैं कि किस तरह से इसे हल किया जाये।

आप अप्पू जयसिंह के पीछे पड़े रहे, कि वह आयेंगे तो मसला हल करेंगे। इनका अपना परिवार ठीक नहीं है। 18, 18 कुनबे का परिवार है।

जब मैं युगोस्लाविया में था तो लन्दन से वाजपेयी जी का बयान आया कि हम साउथ इंडियन को प्रधान मंत्री बनाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि इन्होंने बयान दिया होगा या अखबार वालों ने अपनी मर्जी से दिया मगर अखबार वाले इनके हैं। इसलिए जो यह कहते हैं वह वे छापते हैं। मैं यह समझता हूं कि जब वे साउथ इंडियन को बनाना चाहते हैं तो कहीं कुछ करना चाहते हैं और कहीं कुछ प्रचार करते हैं और इससे इस तरह का वातावरण देश में पैदा करना चाहते हैं। इस बात को इन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर देश को आगे ले जाना है तो एकता के साथ।

हमारी सरकार ठीक कदम उठा रही है। इनको 20-सूत्री प्रोग्राम भी अच्छा नहीं लगता, प्रधान मंत्री और एम०पी० भी अच्छे नहीं लगते। ये समझते हैं कि जो काबलियत इनमें है और किसी में नहीं है। आज हमारे देश के लोग इस हाउस से यह आशा रखते हैं कि यहां से इन्साफ मिलेगा, पार्लियामेंट को सबसे बड़ी ताकत समझा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से आपके बारे में बराबर कहा जाता रहा है। यहां सबके सब खड़े हो जाते हैं। मेरा कहना है कि डिप्टी स्पीकर को सारे हाउस ने बनाया है, 2-4 आदमियों ने नहीं बनाया। ये सब तरफ से एजीटेशन करना चाहते हैं, इस हाउस में भी एजीटेशन करना चाहते है, पंजाबी सूबे के बारे में भी एजीटेशन करना चाहते हैं, प्रधान मंत्री के खिलाफ भी एजीटेशन करना चाहते हैं। कोई काम इनके पास इसके अलावा नहीं है। ये कहते हैं कि कारखाने बन्द कर दो और एजीटेशन के लिए तैयार हो जाओ। यही सबक ये सारे देश को देते हैं और बाकी कोई काम इनके पास नहीं है।

हिमाचल प्रदेश हमारे बार्डर का सूबा है जिसके साथ चाइना का बार्डर मिलता है और पंजाब का बार्डर भी मिलता है। भारत सरकार इस तरफ ध्यान दे कि जितने कारखाने हैं वह सब अकाली दल के जो लोग हैं वह हमारे हिमाचल प्रदेश में भी घुस रहे हैं, हमें तो इनसे बचायें। ये चीजें बार्डर के एरिया में ठीक नहीं हैं। इससे हमारे हिमाचल प्रदेश की इकनामी कम होगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि वार्डर एरिया को छोड़कर ऊपर के इलाके में इन्डस्ट्री लगनी चाहिए ताकि ये बड़े-बड़े मोटे मोटे लोग वहां जाकर गड़बड़ पैदा न करें।

मेरा कहना यह है कि पठानकोट का इलाका, नारायण गढ़ी का इलाका हिमाचल प्रदेश में मिलना चाहिए। उनकी भाषा एक मिलती है, हमारे पहाड़ी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं।

मैं आशा रखता हूं कि जहां यह बात इन्होंने की है, धार्मिक स्थानों को खराब करने की कोशिश हो रही है, सरकार उसका मुकाबला करे। देश के लोग ऐसी आशा रखते हैं, वह पूरी होगी। आज सुबह से अभी तक बहस हो रही है, इसका यही नतीजा है कि इनके पास काम, प्रोग्राम नहीं है। ये अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। सरकार कठिनाइयां कम करना चाहती है लेकिन ये कठिनाइयां बढ़ा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि देश की एकता को आप मजबूत करेंगे और देश को आगे बढ़ाने के लिए साथ देंगे।

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Sir, I do not propose at this stage to trace the basic aspects and the genesis of the problem. But it is necessary for the House to understand the real issues. I know that certain basic issues are to be mentioned. Broadly speaking, the Punjab problem today hinges around three or four basic issues—territorial dispute, sharing of river waters, Centre-State relations and the religious demands of the Sikh community, a very important community of our nation.

So far as the above three issues are concerned, I have to make it abundantly clear that these three issues contain democratic contents because these relate to the economic issues of the people of the Punjab. These democratic contents correspond to the general and common interest of the

people of the Punjab as a whole irrespective of their religious feelings. Therefore, if any impression is created that the demands of the Akali Party are wholly meant for a particular religious community or a particular section of people, I think, it will not be a just assessment of the situation. These are not only in correspondence with the general hopes and aspirations of the people of the Punjab as a whole having different religious faiths but also are in conformity with the general democratic principles of the democratic movement of our country, because re-distribution of States on linguistic basis and proper share of water for every State are not the demands for a particular community having particular religios beliefs. Therefore, the House should dispel this impression that the demands are not democratic. If you have this impression, then the House will not do justice with the Akali agitation.

There are reasons even now to believe that there are accepted norms to work out solution to these issues, namely, the territorial disputes and water disputes. So far as the linguistic redistribution of the States is concerned, there are accepted norms for it. These accepted norms have been utilised also in the past in several other regions. Those accepted norms are language contiguity and village as a unit. If these principles were accepted in the case of other territorial issues belonging to other regions, why this basic principle should not be applied in the case of the solution of the territorial disputes of Punjab ?

So far as the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 is concerned, it is another available tool in the hands of the Government to bring out a solution of the water dispute. This is also an accepted norm. Can we accept it as a norm. The question of the Centre-States the question of autonomy of the State, is not the question of Punjab alone, the Akalis alone, it is an issue which is of national significance and which has the sanction of a vast section of the people in our country. That problem can also be solved as the Sarkaria Commission has been appointed. Of course, I hold the view that certain modifications are necessary for the Sarkaria Commission. Additional chits are also to be given so that each recommendation might have some statutory or legal sanction. Therefore, these are the major democratic issues and there are norms available for the solution of them, there are tools available for the solution of them. As a matter of fact, the tripartite outlook or the consensus which emerged from the tripartite was based on this basic norm, accepted norm. It was not just by way of give and take. We discussed things on the basis of certain accepted norms which were also accepted by the Akali Party. Equally the 30th June meet of the Opposition has also formulated certain recommendations on the basis of these accepted norms that if there are accepted norms available, if there are tools available for the solution, then what was the reason that this solution has not yet been arrived it ? The answer has been given by me. The answer is that the ruling party does not want a solution. We say that the solution lies in the dialogue, solution lies in negotiations and that solution can be worked out. It is possible to be worked out and in order to work out a solution consensus is there of the tripartite. Recommendations of the Opposition Parties are also there. You may start negotiations, you may resume dialogue and you can find out a solution. But if you find that there are certain objections to it, you may find out some other solution. Therefore, you cannot say that we have reached a point of no return. As I have understood, Mr. Stephen said that this far we have been able to advance, after that there is no scope for further advancement. With all humility I will say the situation is very critical. The Punjab issue is not only the issue of the people of Punjab alone, it is a national issue today. It relates to the very fundamental question of national unity and integrity. Therefore, it is necessary that utmost efforts are made to work out a political solution of the problem and to work out a political solution of the problem, dialogue is the only way, negotiation is the only way.

Of late I find that a campaign is being mounted against the Akali Party because of certain observations made by certain leaders of the Akali Party. It is to be made clear that we do not agree with certain observations made by them. But it

is also to be borne in mind that repeatedly they announced publicly that they are second to none in defending the unity and integrity of the country. They have repeatedly said that they are against violence ; they have repeatedly said that they are no less patriotic than anybody of us here. Therefore, if certain observations have been made by certain quarters, it should not be made the main issue, it should not be made the plea or pretext not to resume talks with them.. Because, if you want to have a solution, the only way out for working out a solution is dialogue ; there is no other way out.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Therefore, you can conclude now.

SHRI CHITTA BASU : Now I would say that the Government of India pursued a policy of drift and, because of that policy of drift, the situation has been made all the more complicated. So, if the situation is not dealt with as early as pos ible, I am afraid, it would have more dangerous dimensions. Let it may become further complicated, it is necessary that the Government should abandon the policy of drift.

The last point is the phenomenon of extremism. I agree that extremism or extremist activity has brought about certain difficulties. But the question arises...

AN HON. MEMBER : How to solve the problem.

SHRI CHITTA BASU : No, who created the condition. They have created the problem and they have to find a solution. The extremism has been the creation from their side. Instances are not to be repeated. They have to fight the extremist elements. But we want to know simply one thing from the Home Minister. Are you prepared to publish a white paper on the activities of the extremists ?

SHRI C.M. STEPHEN : Why not red paper ?

SHRI CHITTA BASU : Then it will become red rag to you.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You must be knowing better the activities of the extremists.

SHRI CHITTA BASU : I know everything. There is no doubt about it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You tell him, help him ; he will take action.

SHRI CHITTA BASU : Unless you publish a white paper about the extremist activities, who are the traitors, what are the different agencies involved, how your partymen were involved, unless these things are known, how can we explain them to the people so that they know how to fight the extremists ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : So, the Home Minister should give a white paper on these lines.

SHRI CHITTA BASU : I do not know whether he will give it, but he will try his utmost to conceal all these activities, as he has been doing all these years. Therefore, the last point is...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Already you have said "last point" ; perhaps that was the last but one.

SHRI CHITTA BASU : This is the last point. The Government should come out with a white paper so that the people can understand more clearly which are the forces behind these extremist elements. Therefore, instead of dilly dallying, Government should immediately take the initiative to resume dialogue so that a suitable political solution can be worked out in the larger interests of the unity and integrity of the country.

*SHRI N. SOUNDARARAJAN (Sivakasi) : Hon. Mr. Deputy Speaker, Sir, participating in the discussion on Punjab situation, I would like to express my views on behalf of my party, the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam.

During the past eleven months the State of Punjab has been engulfed in an environ-

* The original speech was delivered in Tamil.

ment of agitations and unsettled conditions. The Akali Dal has raised certain demands and is arousing mass frenzy to get them fulfilled. Ours is a democratic country. The people living in a democratic country, the political movements and the political parties have their constitutional right to voice their demands and to work for their achievement. I would like to take this opportunity to say that when p litical rights are sought to be justified, the democratic means should be adopted for vindicating them. In a democracy violence cannot be the means to get the grievances redressed.

Mahatma Gandhi resorted to non-violent means based on the age-old ethics of this great country and he was successful in sending out the Englishmen and securing freedom for the country. The world's greatest peace exponent, Pandit Nehru laid the foundation for the progress of this nation of which Punjab is an inalienable part. As a citizen of this great country, I have to regretfully point out that Akali Dal seems to be fanning the flames of violence and is sowing the seeds of anarchy in the State. I am even afraid that probably the extremists and anti-social forces have taken hold of the Akali Dal.

I have to repeat that our Father of the Nation used to frequently assert that while one claims the justness of his ideal, he should also bear in mind that justness of means in translating that ideal into action has equal force to reckon with.

Our hon. Prime Minister is showing monumental patience in resolving the Punjab tangle. She has conceded the religious demands of the Akali Dal and has initiated energetic steps for implementing them. But the political demands of Akali Dal cannot be so easily accepted because the rights of neighbouring States are involved. The Akali Dal must give some reasonable time to our Prime Minister for finding a lasting solution. It is unreasonable on the part of Akali Dal to demand the removal of the popularly elected Chief Minister as the first step for reconciliation. Here I am reminded of the violent attack on 21.7.1983 by the extremist youth elements of D.M.K. at Madras on the popularly elected Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.G.R. I have to say that democracy is the best forum for reconciling political differences. If violence is resorted to, then the whole edifice of democracy crumbles down. The entire House should unanimously condemn such violent demands and vicious attacks on the life and person of Chief Minister for resolving political differences.

Punjab is a border State and such unsettled conditions should not be prolonged indefinitely. It is not in the interest of sovereignty and integrity of the country to have the border State in perpetual chaos. Therefore I request the hon. Prime Minister to invite personally Sant Longowal for personal talks so that mutually acceptable solutions can be found. This alone will serve the best interests of the nation. In saying this, I have voiced the sentiments of my beloved leader, Thiru M.G.R. who has unassailable faith in democratic traditions of this country and who has dedicated himself to the integrity and unity of India. With these words, I conclude my speech.

श्री रामनगीना मिश्र (सलेमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो आपने मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, हमने विरोधी दल के सारे नेताओं के विचार सुनें। माननीय विरोधी दलों की ओर से जब पंजाब के मसले पर यहां प्रस्ताव आया तो हमारे जैसे गांव में रहने वाले साधारण आदमी ने यह सोचा कि विरोधी दल वाले जो यह प्रस्ताव लाए हैं उसके माध्यम से वे लोग यहां ऐसे विचार प्रस्तुत करेंगे जिससे कि पंजाब में जो आज आग लगी हुई है उसको शात करने में सरकार को सहायता मिलेगी। लेकिन ठीक उसके विपरीत हमने देखा कि विरोधी दल के किसी भी नेता ने ऐसा विचार व्यक्त नहीं किया जिससे कि पंजाब में शांति स्थापित करने में मदद मिलती। यह सही है कि पंजाब की स्थिति से सभी लोगों में नाराजगी है लेकिन जो आग आज पंजाब में लगी हुई है, उसमें घी डालने का काम आज विरोधी दलों ने किया है जिससे कि आग और भी प्रज्वलित हो जाए।

यहां पर अखबारों से बहुत से कोटेशन दिए गए। हमने भी एकाध अखबार पढ़ा है जिसमें लिखा था कि स्वर्ण मन्दिर में अल्लाहो अकबर के नारे लगे और उनमें मुसलमान लोग भी शरीक हुए। लेकिन यह बात किसीने कोट नहीं की। मान्यवर, इतना ही नहीं, यह बात भी सही है कि बहुत से लोग पाकिस्तान के भेष बदलकर यहां साम्प्रदायिक दंगे करा रहे हैं। यह बात अखबारों में बहुत-सी जगह निकली है। इसको भी यहां कोट नहीं किया गया।

मान्यवर, धर्मनिरपेक्षता की दुहाई सभी देते हैं। मैं अपने अपोजिशन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या विश्व में ऐसा कोई भी देश है जिसमें इतनी धर्मनिरपेक्षता हो जितनी कि गांधी के इस देश में है, श्रीमती इन्दिरागांधी के इस राज्य में है। यह धर्मनिरपेक्षता बढ़ती ही जा रही है। आप किसी भी देश का नाम बता दीजिए जहां इस प्रकार से सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को स्वतन्त्रता हो। यह कांग्रेस की सरकार में, इन्दिरा गांधी के हिन्दुस्तान में ही सभी धर्मों के मानने वालों को ऐसी सुविधा मिली हुई है कि चाहे कोई मन्दिर बनाये, गुरुद्वारा बनाये या चाहे मस्जिद बनाये। यहां सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर मिले हुए हैं।

मान्यवर, लोग कहते हैं कि पंजाब के मसले को इसलिए बनाए रखा जा रहा है जिससे कि देश को प्रभावित करके वोट ले लिये जाएं। हमें यह कहते हुए संकोच लगता है कि जब इलेक्शन होता है तो कौन-सा ऐसा दल है जो मेजोरिटी कम्युनिटी के केन्डीडेट को चुनाव में खड़ा नहीं करता हो। विरोधी दलों में कौन-सा ऐसा दल है जो कि ईमानदारी से क्षेत्र में जाकर यह कहता हो कि हम फलां धर्म के मानने वाले हैं, हमें आप वोट दो। मैंने बंगाल के लोगों से, कम्युनिस्ट लोगों से जब बात की तो वे भी वोट लेने के वक्त यह नहीं कहते हैं। यहां पर धर्मनिरपेक्षता की बात बहुत की जाती है, माइनोरिटी का वोट लेने की बात कही जाती है।

श्री हरिकेश बहादुर : गढ़वाल में ठाकुरों के वोट अधिक हैं। बहुगुणा जी को उन्होंने वोट दिया। जबकि ठाकुरों का बहुमत देखते हुए कांग्रेस ने ठाकुर केन्डीडेट को खड़ा किया था।

श्री रामनगीना मिश्र : मैं उनकी बात का जवाब न देते हुए अपनी ही बात कहता हूं।

हरिकेश जी जिस दल के हैं उस दल के नेता के बारे में भी सब जानते हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि बहुगुणा जी ने अपने स्वार्थ के लिए कई दल बदले। चीफ मिनिस्टर रहकर एक नाटक किया। क्या आप इलेक्शन लड़कर के चीफ मिनिस्टर हुए थे। क्या आपने विधायकों की नुमाइन्दगी की थी। तो जो पद्धति आज है, वही उस समय थी। क्यों आपने उस समय इस पद्धति को अपनाया था।

जार्ज फर्नाण्डिस इस वक्त नहीं हैं। एक दिन अखबार में देखा कि उन्होंने चौधरी साहब का विरोध किया है और दूसरे दिन ही उनके पास चले गए। ऐसे लीडर हैं जो आज कुछ कहते हैं और कल कुछ कहते हैं। क्या जनता इतनी मूर्ख है जो यह सब कुछ नहीं समझती। आज जो लोग राजनीति की बात कर रहे हैं क्या कोई विरोधी दल का नेता ऐसा है जो पंजाब में गया हो और अकाली दल के नेताओं से कहा हो कि तुम खालिस्तान की बात क्यों करते हो। (**व्यवधान**)

एक ही वाक्य है—मारो, मत जाने दो और मारो मत, जाने दो। इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। इसी तरह से पूरब को पश्चिम और पश्चिम को पूरब सिद्ध करने में विरोधी दल के लोग सक्षम हैं। क्या जो नेता स्वर्ण मन्दिर में गए, उनको पता नहीं है कि वहां खालिस्तान का दफ्तर है। उस स्वर्ण मन्दिर में पंजाब के अपराधी निवास करते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : क्या आपके नेताओं की आंखें देख नहीं रही हैं। उनको वहां से निका-

लते क्यों नहीं हैं। (व्यवधान)**

MR. DEPUTY SPEAKER : I do not know why he is provoked.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : It should be expunged.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will go through the record.

(*Interruptions.*)

श्री रामनगीना मिश्र : हमें इस बात की खुशी है कि दवा कारगर हो रही है। दवा कड़वी है इसलिए माननीय सदस्य बौखला रहे हैं और असंतुलित हो रहे हैं। (**व्यवधान**)

हमारे सारे अपोजीशन के नेता यह जानते हैं कि अकाली दल के नेता क्या हैं। एक भोजपुरी कहावत है कि "कहिए सुकर्म—करिए कुकर्म" अर्थात बातें तो सब अच्छी कहिए, लेकिन करिए सब कुकर्म।

22.00 hrs.

वे कहते कुछ हैं, अखबारों में कुछ देते हैं और करते दूसरा हैं। क्या उग्रपंथियों के पीछे अकाली दल का हाथ नहीं है, खालिस्तान की मांग के पीछे उनका हाथ नहीं है, स्वर्ण मंदिर में अपराधियों को रखने के पीछे उनका हाथ नहीं है? क्या हमारे विरोधी दलों के लीडर यह सब कुछ जानते नहीं हैं? अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें कि क्या सचमुच में यह सही नहीं है? क्या वे ईमानदारी से इस सबको महसूस नहीं करते हैं कि अकाली इसमें कहां आते हैं? वहां जाकर राजनीति कौन नहीं कर रहा है? आज विरोधी दल वाले क्यों बौखला उठे हैं? इस वास्ते कि ये देश के सामने नंगे हो गए हैं, इनकी तस्वीर जनता ने देख ली है, बौखला इसलिए रहे हैं कि देश की जनता को ये क्या जवाब देंगे? प्रधान मंत्री ने कह दिया है कि देश का ये बंटवारा करना चाहते हैं, टुकड़े करना चाहते हैं। पंजाब में ये आग लगा रहे हैं। आज इनकी अकल खराब हो चुकी है। जब कोई बौखलाता है, तो दिमाग का संतुलन ठीक नहीं रहता है और मुंह से आवाज भी ठीक नहीं निकलती है।

एक ओर आपने कहा कि हमारे मुख्य मंत्री रहे ज्ञानी जैल सिंह तो उन्होंने कुछ नहीं किया। किन्तु जब आप पावर में आए तो आपके भी मुख्यमंत्री थे और केन्द्र में भी आपके मंत्री थे। क्यों नहीं तब आपने इस मसले को तय कर लिया। आपको तय कर लेना चाहिए था। जब आप गद्दी से उतर गए तो ज्ञान की बात आपको सूझ गई। मुझे एक कहानी याद आ गई है। एक चरवाहा जंगल में जाता था। वह जब सिंहासन पर बैठ जाता था तो उसको ज्ञान की बात नहीं सूझती थी और जब उतर जाता था तो सूझने लग जाती थी। गद्दी पर जब ये थे तो इनका ज्ञान लुप्त हो गया था। अब गद्दी से उतर गए हैं तो इनको ज्ञान आ गया है। अगर मेरे मित्रों ने मुझको उभाड़ा नहीं होता तो मैं यह सब कुछ नहीं कहता। दो चार बार और मुझे इसी तरह से टोकेंगे तो शायद जो मुझे नहीं भी कहना चाहिए वह भी मुझसे कहलवा लें।

विरोधी दल के मित्रों से मैं कहूंगा, विरोधी दल के नेताओं से मैं कहूंगा कि इस देश के मसलों को, इस राष्ट्र के मसलों को निजी स्वार्थ की दृष्टि से न लेकर राष्ट्र के हित में देखें और उन पर विचार करें। वह बहुत बौखला रहे हैं हमारी प्रधान मंत्री जी के बयान पर। अगर आपने सचमुच में सहयोग दिया होता तो कभी ऐसी बात नहीं कही जा सकती थी। जब तक आपने सहयोग दिया हमारे गृह मंत्री ने आपकी तारीफ की। लेकिन जब से आप आग में घी डालने लगे तो मजबूरन इस बात को कहना पड़ा कि आप आग में घी डाल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सभी मिल कर इसके बारे में प्रयत्न करें, इसका समाधान निकालने की कोशिश करें ताकि देश का, राष्ट्र का भला हो। मैंने तो सोचा था कि हमारे विरोधी

**Expunged as ordered by the Chair.

दलों की तरफ से आज प्रस्ताव आएगा और इस मामले में सब एक मत होंगे कि शासन को विश्वास दिया जाए कि वह जो भी उचित समझे करे ताकि राष्ट्र की एकता कायम रहे, पंजाब में शांति हो और सब मिलकर काम करें, सब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। किन्तु यह बात नहीं आई।

हमारे ऊपर विरोधी दल आरोप लगा रहा है लेकिन यह आरोप उनके ऊपर लगता है। मैं धर्म निरपेक्षता की बात कह रहा हूं। किसी भी विरोधी दल के नेता ने नहीं कहा कि गुरुद्वारों में क्रिमिनल्ज को न रखा जाए। साथ ही एक लाख स्वयं सेवक भर्ती किए गए हैं। अखबारों में आया है और आपने वहां जाकर देखा और सुना भी होगा इसके बारे में कि एक लाख स्वयं सेवक बलिदान के नाम पर भरती किए गए हैं। अब अगर यह काम मंदिरों और मस्जिदों में भी होने लगे तो क्या होगा? विरोधी दल वालों को प्रस्ताव पास करना चाहिए था कि सब धर्मों के साथ समान व्यवहार हो, जैसे अन्य धर्मों के साथ व्यवहार होता है उसी तरह से सिख धर्म के साथ भी होना चाहिए, जैसा व्यवहार मंदिरों और मस्जिदों के साथ होता है, वैसा ही गुरुद्वारों के साथ भी हो। कोई भी वहां क्रिमिनल न रहे। अगर रहे तो पुलिस को अधिकार होना चाहिए और शासन को विरोध पक्ष का सहयोग होना चाहिए ताकि उनको जाकर पकड़ा जा सके। अगर किसी के द्वारा कोई कटु बात हो गई हो तो उसको भुलाकर राष्ट्र की एकता के नाम पर सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास करें और सरकार को आश्वासन दिया जाय कि जैसे भी पंजाब में शांति स्थापित हो तथा राष्ट्र की एकता कायम रहे उस लक्ष्य से सरकार काम करे जिसमें विरोधी दल सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम करेंगे।

यही मुझे कहना है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष जी, आज जो बहस इस सदन में पंजाब की समस्या पर हुई है उससे यह बात साबित हो गई कि पंजाब की समस्या केवल पंजाब और हरियाणा की ही नहीं है बल्कि सारे देश के लोग इस समस्या से चिंतित हैं और यह एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। यहां शासक दल की तरफ से कहा गया कि विरोधी दल के लोगों ने आज कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिये इस बहस में। यह बहस पहली बार नहीं हुई, इसी सदन में 2, 3 बार पहले भी हो चुकी है और बहुत रचनात्मक सुझाव इस सदन में पहले दिए जा चुके हैं। सवाल यह नहीं है कि सुझाव आज इस सदन में दिए गए कि नहीं, सरकार ने जब त्रिपक्षीय वार्ता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था तो विरोधी दल के नेताओं ने बैठकर जो कुछ उन्हें कहना था, जो भी सुझाव देने थे, कई बैठकों में बैठकर के अपनी राय दी थी। गृह मंत्री जी मौजूद हैं, वह साक्षी हैं कि जो कुछ भी वहां बात हुई अकाली दल के प्रतिनिधि मंडल से या पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकारों के प्रतिनिधियों से या विरोधी दलों के नेताओं से, उनमें ज्यादातर बात विरोधी दल के प्रतिनिधियों ने ही की। सरकार के प्रतिनिधि समय समय पर उसमें जरूर हस्तक्षेप करते रहे, लेकिन ज्यादातर बात विरोधी दल के लोगों ने ही उनसे की। सभी जानते हैं कि 45 मांगों का मांग-पत्र लेकर अकाली दल आया हुआ है। हमारे स्टीफन साहब ने कहा कि आखिर 45 मांगों का मांग-पत्र था, उसको लेकर करीब करीब दो मांगों तक सीमित कर दिया गया। बाकी सबका हल हो गया था। क्या सरकार की नीयत का सबूत नहीं है कि सरकार चाहती थी कि उसका हल हो। हम सरकार की नीयत पर हमला नहीं करते। लेकिन यह बात माननी पड़ेगी कि विरोधी दल के प्रतिनिधियों ने अकाली दल के प्रतिनिधि मंडल से बार-बार कहा कि ऐसी मांगें कभी हम किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते, उस पर चर्चा भी करने के लिए तैयार नहीं हैं, इन मांगों को निकालिए। जैसे हिमाचल प्रदेश की जमीन की मांग है, या राजस्थान की जमीन की मांग है। इन लोगों को उन्होंने निकाला। बहुत सी मांगों के बारे में हमने कहा कि हम चर्चा करने को तैयार नहीं है, और विरोधी दलों के दबाव पर उन्होंने उन मांगों को

छोड़ा। मुझे ताज्जुब हुआ गढ़वाल के दौरे पर प्रधान मंत्री ने कहा, अगर अखबारों में वह बात सही छपी है, कि पंजाब की समस्या को विरोधी दल उलझा रहे हैं। पंजाब की समस्या को, अकाली दल और वहां के खालिस्तान की मांग करने वाले देश को तोड़ना चाहते हैं। पंजाब में अकाली दल राजस्थान की पानी की मांग को उठा रहा है। मुझे अफसोस है, अगर उन्होंने यह बात कही है तो उनको यही जानकारी नहीं है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है। यह सभी जानते हैं कि सरकार के कहने पर नहीं, सरकार की कैबिनेट के प्रतिनिधि मंडल ने चंडीगढ़ में जाकर जो बात की उसके कहने पर नहीं, बल्कि विरोधी दलों के कहने पर ही कि राजस्थान के पानी की समस्या को आप छोड़िए, उसको न उठाइये, उस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा रेगिस्तान है, इस पर अकाली दल मान गया। राजस्थान के लोगों के लिए पीने के पानी की समस्या है। मेहरबानी करके राजस्थान की समस्या को छोड़ दीजिए।

मुझे यह कहते हुए खुशी है कि विरोधी दल के अनुरोध को मानकर अकाली दल के प्रतिनिधि-मण्डल ने राजस्थान की पानी की समस्या को बिल्कुल छोड़ दिया। आज उसको यहां कहा जा रहा है। श्री बहुगुणा जी ने ठीक कहा कि दो राज्यों की समस्या है, उसको हल करने की कोशिश कीजिए, खामखाह तीसरे राज्य को क्यों शामिल कर रहे हैं? उसके लिए उन्होंने अपने आपको अलग कर लिया है।

हमारे हिमाचल प्रदेश के मित्र ने कह दिया कि हमारे शिमला को मांग रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को मांग रहे हैं। जब उन्होंने उस बात को छोड़ दिया तो क्यों उस बात को आप बढ़ाना चाहते हैं? हमारे भाटिया जी ने कहा कि आइसोलेशन की स्थिति में, चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो, देश हो, ऐसी बात भी करता है जो बहुत उचित नहीं होती। यहां यह बात लागू नहीं होती है। अगर आप समझते हैं कि अकाली दल बिल्कुल आइसोलेशन की स्थिति में है, फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में है तो आप बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि आइसोलेशन और फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बात कहने के लिए विचार किए जाएं जो और इस देश के लिए घातक सिद्ध हों?

मैं समझता हूं कि लौंगोवाल ने जो आज भेजा है, जिसकी चर्चा वाजपेयी जी ने की है, हम इस पुस्तक से सहमत नहीं हैं। हम इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि भारत मल्टी राष्ट्रीय देश कहा जाए। हमारे देश में राष्ट्रीयता की परिभाषा एक ही है, हम सारे भारत को राष्ट्र मानते हैं। हम भारत को कई राष्ट्र मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इनकी बात हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

हम यह भी समझते हैं कि उन्होंने जो पर्सनलला की बात उठाई है, वह बहुत-सी बातें गुस्से में कह रहे हैं। बहुत-सी बातों को उन्होंने मान लिया था जिससे ज्यादा आगे बढ़कर वह बातें कह रहे हैं, शायद इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें अब विश्वास नहीं रह गया है कि उनके साथ इन्साफ होगा।

मैं यह कहना चाहता हूं, पहले कहा गया कि अकाली दल का आंदोलन बिल्कुल निराधार है, उनकी मांगों का कोई औचित्य नहीं है। अगर यह बात ठीक है तो प्रधान मन्त्री ने उनकी बहुत-सी मांगें क्यों मान लीं? क्यों प्रधान मंत्री ने उनकी सारी की सारी धार्मिक मांगों को मान लिया और क्यों उनका डंका पीटा जा रहा है कि हमने उनकी सारी बातों को मान लिया?

त्रिपक्षीय वार्ता हो रही थी, बात चल रही थी। मुझे ठीक याद है तो संसद का अधिवेशन चल रहा था, मगर प्रधान मंत्री ने गुरुद्वारे में जाकर घोषणा की। क्यों उन्होंने गुरुद्वारे में जाकर घोषणा की? क्या प्रधान मंत्री संसद् में उस बात की घोषणा नहीं कर सकती थीं, प्रेस कांफरेंस बुलाकर घोषणा नहीं कर सकती थी या कार्यालय से विज्ञप्ति जारी करके घोषणा नहीं हो सकती थी?

लेकिन प्रधान मंत्री को राय दी गई कि अकालियों का आंदोलन धार्मिक आंदोलन है, धार्मिक बातें हैं आप इनको स्वीकार कर लीजिए, आंदोलन फेल हो जाएगा: असफल हो जाएगा। इसीलिए प्रधान मंत्री ने सीसगंज के गुरुद्वारे का स्थान इसके लिए चुना। फिर उन लोगों के मन में शक हुआ कि प्रधान मंत्री हमारे सिखों के आधार को तोड़ना चाहती हैं। राजनीतिक आधार के लिए उनके मन में अविश्वास पैदा हुआ। मैं समझता हूं कि उसका औचित्य है। मेरा कहना यह है कि प्रधान मंत्री जी ने वह बात अच्छी नहीं की।

गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह अपना पिछला भाषण निकलवाकर पढ़ दें। मैं नहीं पढ़ना चाहता, उन्होंने इस सदन में यह कहा था कि मैं विरोधी दल के नेताओं का आभारी हूं, जिन्होंने त्रिपक्षीय वार्ता में बैठकर बातें कीं, निदान के लिए प्रयास किया, हमारा सहयोग किया और बहुत हद तक मतभेद कम हुए।

> He said that it was, to a large extent, narrowed down.

यह तो गृह-मंत्री जी कहते हैं कि विरोधी दल के बारे में और बाहर प्रधान मंत्री जी कहती हैं कि सारा विरोधी दल जिम्मेदार है, यह सारे देश को तबाह करना चाहता है, देश को तोड़ने वाली शक्तियों की मदद कर रहा है।

मैं समझता हूं प्रधान मन्त्री को यह बात शोभा नहीं देती है। चुनाव होते और कांग्रेस के नेता की हैसियत से वे कहतीं उस वक्त हम समझते कि चुनाव हो रहे हैं लेकिन आज चुनाव नहीं हैं। आज प्रधान मन्त्री प्रधान मन्त्री हैं और उनको विरोधी दल के लोग अपना सहयोग देना चाहते हैं। हमारे लिए यह आसान काम नहीं था। हम ऐसी बातें कहते थे जो अप्रिय बातें थीं। यहां पर वाजपेयी जी ने बहुत-सी बातें कहीं है जिसके लिए स्टीफन साहब ने उनको बधाई दी है। वाजपेयी जी ने अपनी पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं की कि वे नाराज हो जाएंगे, उन्होंने राष्ट्र के हित में जो उचित समझा उसको जिम्मेदारी के साथ यहां पर कहा है। जब आज इस तरह की भावना से विरोधी दल के नेता एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए और अपना सहयोग देने के लिए आगे हैं तब यदि उनपर यह आरोप थोप दिया जाता है कि आप देश को तोड़ना चाहते हैं—यह कहां तक उचित है?

एक दूसरी बात और भी है जिस पर मैं समझता हूं प्रधान मंत्री को बड़ी गम्भीरता के साथ सोचना चाहिए। आजकल उन्होंने अपने भाषणों में एक और बात कहनी शुरू कर दी है कि रीजनल पार्टीज आर एजेंट्स आफ डेस्ट्रक्शन ऐंड डिसइण्टिग्रेशन। यह क्या बात है? आज रीजनल पार्टीज क्यों पैदा हो रही हैं, किसलिए पैदा हो रही हैं, यह सोचना पड़ेगा। तेलुगु देशम् से वे खुश रहें या नाराज रहें लेकिन आंध्र प्रदेश की जनता ने उनको चुना है।

22.16 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

डा० फारूख अब्दुल्ला से वे खुश रहें या नाराज रहें लेकिन कश्मीर की जनता ने उनको चुना है। यह रीजनल पार्टीज कब से एजेंट्स आफ डेस्ट्रक्शन ऐंड डिसइंटिग्रेशन बन गई हैं? कांग्रेस पार्टी ने जब तमिलनाडु में रीजनल पार्टी, डी० एम० के या ए० आई० ए० डी० एम० के० से हाथ मिलाया था तब वह एजेंट आफ डेस्ट्रक्शन ऐंड डिसइन्टिग्रेशन नहीं थीं? त्रिपुरा में दो साल पहले, प्रधान मंत्री ने जिस पार्टी को देशद्रोह की शक्तियां बताया है, उनके साथ समझौता किया था। यह क्या है? जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त प्रधान मंत्री ने राष्ट्र के हित में अपने मुख्य मंत्री को सत्ता से हटा कर शेख अब्दुला को सत्ता सौंप दी थी। उन्होंने सोचा था कि इससे राष्ट्र का हित होगा और आज उसी रीजनल पार्टी को वे एजेंट आफ डेस्ट्रक्शन ऐंड डिसइंटिग्रेशन कह रही हैं। प्रधान मंत्री की इस बात से देश कमजोर होगा। यहीं पर शक होता है

कि आज प्रधान मंत्री अपनी पार्टी के हित को प्राथमिकता दे रही हैं, राष्ट्र के हित को प्राथमिकता नहीं दे रही हैं।

स्टीफन साहब ने पूछा, क्या विरोधी दल के लोग चाहते हैं कि हरियाणा के हितों का कोई ध्यान रखे बिना पंजाब को सब दे दिया जाए? उन्होंने पूछा, क्या विरोधी दल चाहते हैं हरियाणा बिल्कुल अलग रहे और वहाँ के विरोधी दलों की कोई राय न ली जाए। विरोधी दल के लोगों ने कहा था कि न केवल पंजाब और हरियाणा बल्कि राजस्थान के विरोधी दल के लोगों को भी बुलाया जाए, सारी पार्टियों के लोगों को बुलाया जाए और उनके साथ अलग अलग बैठकर बातचीत की जाए। इस सिलसिले में समय भी बढ़ाया गया और बैठकें बढ़ाई गयीं और हमने पूरी कोशिश की कि कोई रास्ता निकले। सारे रास्ते निकल भी चुके थे केवल दो चीजों पर समझौता रह गया था---पानी का समझौता और चंडीगढ़, अबोहर फाजिल्का का मामला। हरियाणा के लोग भी सही कहते हैं कि चंडीगढ़ भी दे दिया जायेगा और उनको कुछ नहीं मिलेगा तो वे हरियाणा की जनता को फेस नहीं कर सकेंगे। उनकी बात की सच्चाई और उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के सुझाव और फार्मूले पेश किए गए जिन पर चर्चा हुई थी और आज कहा जाता है कि विरोधी दल के लोग क्यों नहीं मान लेते कि दोनों चीजें कमीशन के पास भेज दी जाएं। सेठी जी, आखिरी मीटिंग में जब पानी के ट्रिब्यूनल की बात की गई उस वक्त चंडीगढ़ के बदले में कुछ गांवों की चर्चा चल रही थी उस वक्त हमने कहा था कि शेष चीजों को कमीशन को दे दिया जाए जैसे कि टेरिटरी का सवाल है। आपकी तरफ से कहा गया कि टेरिटरी के सवाल को कमीशन में मत जाने दीजिए, उसका भी बैठकर हल निकालिए, तो अच्छा है और केवल पानी के सवाल को ट्रिब्यूनल में जाने दीजिए, लेकिन आज कहा जा रहा है कि सारी समस्याओं को भेज दीजिए। हमको इसमें ऐतराज नहीं है। अगर पंजाब के लोग अकाली दल और हरियाणा के लोग इन सारी समस्याओं को भेजना चाहते हैं, तो भेज दीजिए। मगर हम सुझाव देते हैं, तो उसके ऊपर आपकी इतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए कि सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम वह बात करें जो आपके राजनीतिक लाभ की हो, तो यह नहीं हो सकता है। हम उसी बात को कहना चाहते हैं, उसी बात का समर्थन करना चाहते हैं, जिस बात से इस समस्या का हल निकले। मैं कहना चाहता हूं कि इस समस्या से चिन्ता सिर्फ इस देश के अन्दर ही नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के लिए यह चिन्ता ब्याप्त है। आप भी अभी पिछले दिनों बहुत से देशों में गए हैं। जहां भी भारतीय किसी देश के अन्दर हैं, वे सबसे पहला यही सवाल पूछते हैं कि इस समस्या का हल निकलेगा या नहीं। पंजाब के लोग बहादुर हैं, हिम्मतवाले हैं, और मेहनत करने वाले हैं, जोखिम उठाने की शक्ति है, देशभक्त हैं और दुनिया के तमाम देशों के अन्दर फैल कर मेहनत से पैसा कमाते हैं। आप उन सब के मन में चिन्ता पैदा मत करिए। मैं कहना चाहता हूं कि अकाली दल को ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए, वह एक ऐसे बिन्दु पर पहुंच जाए कि फिर वहां से वापिस आना मुश्किल हो। यह समस्या बहुत गम्भीर समस्या हो गई है।

देश के अन्दर अन्तरराष्ट्रीय शक्तियां ऐसी हैं जो भारत को मजबूत नहीं देखना चाहती हैं। यदि समस्या का समाधान नहीं होगा, उसको टाला जाएगा, उसको लटकाया जाएगा, उसको राजनीतिक लाभ का हिस्सा बनाया जाएगा तो नुकसान होगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस समस्या का हल सिर्फ एक ही है। कल ही कांग्रेस के एक प्रमुख नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि अकाली दल के लोगों को अगर हम चांदी की तस्तरी में सूरज और चांद रखकर उनको पेश कर दें तो भी वे नहीं मानेंगे, जब तक कि पंजाब में हम उनके राज करने की स्थिति पैदा नहीं कर देते।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल सही है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं नहीं कहता कि यह गलत है। अकाली दल एक राजनीतिक पार्टी है। शायद उनके दिमाग में यह बात हो कि वे अकेले नुमाइन्दे हैं सिख सम्प्रदाय के, इसलिए वे पंजाब में राज करने के अधिकारी हैं। मैं समझता हूं कि अगर यह उनकी समझदारी है, तो उनकी गलत समझदारी है। अगर पंजाब के लोग उनको चुन देते हैं, तो वे राज करें और फिर उनको कौन रोकता है राज करने से। दूसरी तरफ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी यह समझती है कि अगर पंजाब में अकाली की समस्या का समाधान करना है तो उसका समाधान इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को हो। कांग्रेस पार्टी भी अपनी राजनीति खेल रही है और अकाली दल भी खेल रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री का यह मूल्यांकन हो गया है कि अगर इस समस्या का समाधान निकल भी जाएगा तो एक न एक समस्या खड़ी करके अकाली दल आने वाले चुनाव तक अपना आंदोलन चलाता रहेगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान निकालिए। इसका निराकरण करिए। उसके बाद अगर कोई समस्या उठाकर आंदोलन करे तो अलग से आप उसको डील करिए। लेकिन आज यह मसला गृह मंत्री या सरकार की कोई टीम के बस का मसला नहीं है। जब तक प्रधान मंत्री जी की यह समझदारी बनी रहेगी तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी इस समझदारी को बदलिए। प्रधान मंत्री जी इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझें। प्रधान मंत्री जी समझती नहीं हैं कि इस समस्या का हल निकालना चाहिए। इस समस्या का हल करीब-करीब निकल गया है। इसका हल हरियाणा और पंजाब के लोगों के साथ बैठकर करें। अगर इसमें विरोधी दल की सहयोग की आवश्यकता है तो हम वह सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस काम रोको प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

PROF. SAIFUDDIN SOZ (Baramulla) : Mr. Speaker, Sir, I was indeed delighted to hear the speeches of many Members throughout to-day, like Chaudhury Saheb, Mr. Fernandes, Shri Bahuguna, Shri Stephen and, a moment before, Shri Chandrajit Yadav. My mind was really enlightened on Punjab after hearing them.

Although Chaudhri Sahib's speech was on Hindu ethos yet he spoke from his soul and I could feel he was very much concerned that the tangle of Punjab should get solved. But on the conclusion of his speech I expected that he would put forth some kind of a solution which he did not do and when from the Treasury benches Mr. Bhatia spoke he gave a very good narrative and I was very much impressed that he would also suggest some solution. He did not do so. But out of these speakers I have a marginal difference of opinion with my revered colleague Shri Vajpayee and on the side of Congress (I) I have a fundamental difference of opinion with Mr. Stephen. Shri Atal Bihari Vajpayee made a laudable contribution in his chaste Hindi and suggested solution of the Punjab problem but at one point with due deference to his eminence, I differ when he came down to describe meaning of 'nation'. In fact, last month when I had the privilege of attending the Opposition meet, Mr. Tohra was there and Mr. Balwant Singh was there and they explained in unequivocal terms that the Sikhs as represented by Akali Dal do not want to be treated as a separate nation.

Now, the Anandpur Resolution says 'quom' and the connotation of that 'quom' do not suggest a separate nation. Perhaps, that cannot be allowed. It is co-mingling of communities that makes a nation, and that is, Indian nation and we cannot allow any other nation alongside Indian nation. You are very much correct when you disagree with the Akali Dal on that but when they say they do not want to be treated as a separate nation then why should we put words into their mouth. Perhaps it is good for the Congress party to dub Akali Dal as a separatist political party or a secessionist party but there was no reason for Vajpayeeji to feel that Sikhs want to be a separate nation and if they want to be a separate

nation perhaps we can denounce their demand any time in future but as of now they do not want to be a separate nation. The word 'nation' could be translated as a 'Millat'. The word 'quom' as mentioned in Anandpur resolution has the connotation of community and 'quom' in that sense is used for various communities based on traditional castes and religion, for example, Goojar quom, Bakarwal quom, Jat quom, etc. This was only a marginal difference of opinion and we do not differ in our point of view on Punjab so far as Bajpaiji's speech is concerned.

But I have a fundamental difference of opinion with Mr. Stephen. He did not exhibit a kind of understanding of this problem. He raised two issues. One was that he expected Central Government to arbitrate while Haryana and Punjab settled their issues bilaterally. This is not correct. This is absolutely wrong because in effect it means that Punjab and Haryana would continue to fight each other.

The second thing is that although some other speakers from that side also said like that, in Punjab they perhaps feel that Akali Dal is a religious organisation. Maybe it was a religious organisation long before. But as of now, it is a political organisation and they feel that Akalis do not represent all Sikhs in Punjab. I differ on this point not because I am a supporter of Akali Dal, but I feel that from Kanyakumari to Kashmir every citizen in India feel that Punjab is in turmoil. Punjab is in turmoil. Is it not because Akalis are disgruntled who have raised specific demands in Punjab ? Who have created this problem in Punjab ? If you think that your Government is running in Punjab, it is absolutely wrong. I beg to differ with you on this issue. Only a week before, I came to know, maybe that position obtains even now, that no Minister of Punjab Government went to Malarkotla, not to speak of Central Ministers going there. They are mortally afraid of talking to people in Punjab ; they are mortally afraid of having a dialogue with the people ; they are mortally afraid of putting forth your point of view there. (*Interruptions*).

SHRI R.L. BHATIA : I may point out that Mr. Joginder Pandey, Health Minister, went there. (*Interruptions*)

PROF. SAIFUDDIN SOZ : I did not disturb when you spoke. So, Sir, I feel that this is not a correct thing to say that Akalis do not represent all Sikhs. Such a thinking is detrimental to the interests of the country.

Now, I come to the basic question. The National Conference vis-a-vis the problem of Punjab. You know that Punjab has a long border with Jammu and Kashmir and it is our supply line and over a period of time it has become a life-line for Jammu and Kashmir. As a neighbouring State, through which passes our supply line, our leader, Dr. Farooq Abdullah, was very much concerned about Punjab and for another reason and that was more important one that weighed heavier in his mind and he had a fund of sincerity with him for his country, for its integrity. He would talk of Punjab and he would go to Amritsar, go to Chandigarh, talk to people there with one aim that nothing should happen against the integrity of this country. He will continue to make efforts in this direction. But he was misunderstood by my friends who are sitting here (Cong. I). He will however continue to do his duty which he owes to this country and as long as we are here, we also owe it to our country. We shall wish and pray that there is peace and progress in Punjab because that will ultimately be conducive to the development and progress of the whole country.

Now, so far as the solution to the problem is concerned, there are two main issues. One is that of Chandigarh and the other is the distribution of river waters.

As far as Chandigarh is concerned, we are of the opinion that it must go to Punjab, not at the cost of Haryana, because, as was resolved in the Opposition Parties' meet, Haryana should have a capital and it should have proper funding for that. As long as there is no commitment for that, there should be no question of Chandigarh going to Punjab. But ultimately—it may be tomorrow, or after a month or after the elections are held next time, for which some people feel solution of Punjab is

being delayed, whatever be the time—Chandigarh will have to go to Punjab. But on this question a lot of fuss has been created. Personally speaking I was educated by a Sardar Sahib, who travelled with me in a plane from Srinagar to Delhi once two months ago. He was not an Akali ; he was a Sikh Gentleman. He told me that the problem was basically a psychological one, because when Chandigarh is transferred to Punjab, it would not happen that the roads will be transported or PGI will be transported or Punjab University will be transported to some other land. Explaining this problem, he said that the Sikhs were, over a period of time, very magnanimous in certain respects. That we should not forget. It does not mean that whatever he said I agreed with, but he enlightened my mind. He told me that in PGI 95% staff was non-Sikh ; and 90 to 92% staff in the Punjab University was again non-Sikh. But Punjab Sikhs never raised a slogan for proportional representation, on the basis of population in these two big institutions because, as the Sikh Gentleman explained, they always stressed that the doctors or the technical staff or Professors should be selected through a national competition and they would continue to do that. So, physically there would not be any problem. It is a psychological problem. Yet I posed a question to him : When it is a psychological problem, why do you want to have Chandigarh ? You would not be grabbing or getting anything. Therefore, you decide that it remains capital for both the States. But, to that he had an answer, rather an emphatic and positive one. He said when Punjab was created as a State Chandigarh was created as a capital for Punjab and it has gone down into the minds of the Sikhs. Therefore, the best solution is that Chandigarh goes to Punjab and Haryana gets an adequate compensation, border adjustment will also be there. Abohar and Fazilka and other adjustments can be there if there is a will to resolve the problem.

Sir, I feel the Prime Minister should have been here, not for the fact that she would listen to my maiden speech, but because Punjab is a very important problem. Opposition parties selected Punjab out of various ticklish problems and accorded priority to it. Therefore, we deserved her presence here.

Why I brought the Prime Minister's name when I was discussing Chandigarh was that I have a belief that the Prime Minister, Mrs. Gandhi, has the capacity and acumen to resolve this crisis. And when she does not appear here, I feel that there is some element of truth in the allegation that Government of India does not want an early solution to the problem.

So far as water disputes are concerned, I was reading a pamphlet that was circulated here yesterday. They have now said that they would accept the verdict of a Supreme Court Judge. But if we invoke the provisions of the Inter-State Water Disputes Act, they could accept the verdict of a Supreme Court sitting Judge or a retired Judge. That does not make any difference. The principle of arbitration is there.

Now, before I conclude, I would refer this august body to their demand at item 7 of the pamphlet circulated here the other day.

Sikhs want recruitment to the Army on the basis of merit, as upto 1974. Restrictions imposed on the basis of population are violative of Article 16 of the Constitution. Perhaps ; I do not know whether it is a policy that recruitment into Army would be made on the basis of population. I would feel happy, and I request the Akali Dal to restrict its demand for Sikhs alone and don't bring Article 16 at all. But, I am not sure whether there is a written or verbal policy ; but as far as Sikhs' demand that their entry into Army should be based on merit, is concerned, I would support it because they have opted for Army from times immemorial. So, it must be their first choice, and if they want to exercise it, of course, merit is their right when they say that restrictions imposed on the basis of population are violative of the Constitution, I want to know whether entry into Army would be on the basis of the proportion of population. If so, perhaps Muslims would get about 11% in the Army ; but can they get it ; is there any policy ?

When the hon. Home Minister rises to

speak any time, he must make it clear because they say Article 16 will be violated because of shift in the policy—but that contention pre-supposes that there is a policy that entry into Army—and the inference is that in Police also—will be based on the proportion of population.

Before I conclude, I would request that the Prime Minister, in order to resolve this crisis immediately—and this will not lower her dignity ; this will enhance her prestige—should send a direct invitation to Mr. Longowal and his colleagues, and invite them to Delhi for direct talks with Mrs. Indira Gandhi. That is the solution to the problem.

PROF. K.K. TEWARY (Buxar) : Mr. Speaker, Sir : When I came to the House, I had no intention to make a speech on the Punjab issue, because Punjab has been discussed on several occasions ; and I saw in the list that there were very many capable people who could handle this issue and give guidance to this House, and through this House to the nation at large. But when I heard a couple of speeches of very important Members of the Opposition, I felt a little provoked, and a little tempted to share my views also, with this House.

MR. SPEAKER : Don't get provoked.

PROF. K.K. TEWARY : If you scan or go through the speeches of the Opposition Members, including—I emphasize—Mr. Bahuguna and Mr. Fernandes, you will discover that an attempt seems to be under way to simplify the whole issue and to lay the blame at the door of the Congress(I) and more at the door of the Prime Minister. With due respect to the members of the Opposition, the leaders on that side, and also keeping in view the real seriousness of the problem, I would like to tell them that it has been an exercise which is not only futile, but it has also been attempt to park at the wrong lane.

Madam Gandhi and the Congress do not need any certificate from any one of you regarding secularism and the love for the integrity of this great nation.

PROF. MADHU DANDAVATE : *Vice-versa.*

PROF. K.K. TEWARY : Particularly on issues like the integrity of the country.

I would not like to go into details of the credentials of each member concerned and the party concerned, but I would certainly touch upon a few points. I wish the views expressed by Mr. Bahuguna and Mr. Fernandes go to the country and to the people of this country and they know in details what views they hold about the integrity of the country and the problems which threaten our national security. Mr. Vajpayee also spoke about it. We are familiar with the views of Mr. Vajpayee on this issue. I am sorry to say that, even on such a matter with which they claim to be deeply concerned, profoundly concerned, Mr. Bahuguna, landed into his usual tirade against the Prime Minister, because, somehow, it is for the opposition to realise the implication of all that Mr. Bahuguna has said and the way he is going about this problem. He might be, he is and he has been feeding himself the facts on ancient and recent grudges against Madam Gandhi ; and it will be a sad day for this country if one man's prejudice, if one man's bias prejudices the whole issue, the issue which concerns not only the opposition's unity for which they have been labouring so hard sometimes, but it has been a mere feckery, an absolutely false attempt. When the whole country is concerned with it, Mr. Bahuguna should not display his dubious credentials in this manner.

Mr. Unnikrishan is not here. Since this is a serious matter, therefore, whatever I say, I am not motivated by any partisan or a polemical point of view. I do not want to enter into polemics on such an important matter. I speak from Bihar and I want and request you to take up the matter in that perspective, in that light. He said, when the conclave started with a big thunder in Vijayawada, Madam Gandhi perhaps got unnerved. I submit to this House that this phenomena is not something very novel ; it is not something very new. Your exercise of unity, disunity, this process of archetypal perhaps, life, death perhaps, re-birth and so on, this has been going on with the opposi-

tion ; and this engulfs the whole political scenario. The Punjab has become the pivotal point : it has become the focus of our attention today ; because it threatens the integrity of the nation. The whole perspective of the political life of this country got vitiated, got distorted, the day you started attacking at Madam Gandhi as an individual and you forgot all the Congress Party, its ideologies, its government, the whole thing. It started just after she took over the government. I will not go into that history, but you ask yourself about your conclave, Vijayawada. References had been made to Vijayawada. Vijayawada is starting with a big bang. When the Vijayawada conclave took place, the whole country was expecting that something would come out of it and an alternative was sought to be projected before the nation which, perhaps, would have led to the solution of Punjab, Assam and all the other problems which you have been detailing. But what happened ? (*Interruptions*) They did not agree. We do not, as a party with a history of 100 years, a party which has given light in the field of liberation movements all over the world and a majority of the countries of the Third World owes for their independence or at least inspiration to launch the freedom movements to the Indian National Congress and the leadership provided by this country, treat any individual on that side or any political party as a pariah. To us none of you is a pariah. None of you is an untouchable. But what happened ? Mr. Vajpayee, you cannot share the same seat with Mr. Ramavatar Shastri or Mr. Indrajit Gupta. But the only issue on which all of you come under one banner at Vijayawada—on burning issues, you have no solutions—that Mrs. Gandhi is responsible for everything. About Punjab the second conclave—I put it to you Mr. Fernandes and Mr. Bahuguna... (*Interruptions*).

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : What is the subject he is speaking of...(*Interruptions*) He is juggling with words. (*Interruptions*) He should stick to the subject. (*Interruptions*).

PROF. K.K. TEWARY : They have shed copious tears over Punjab and tried to project that Madam Gandhi—this is an insidious propaganda which has recently emerged in the political circles of India—is trying to prolong this Punjab tangle because, somehow in their calculation, in their bizarre calculation of political mathematics, this will help Congress(I) to win the next parliamentary elections. I am not going into that. I am just trying to point out to you that you gathered here in Delhi and the purpose was one point. (*Interruptions*) The purpose was to find a solution to the Punjab tangle. What happened ? Mr. Bahuguna, perhaps, tried to steal the thunder and convened a meeting. This is the degree of unanimity of the opposition on a matter as serious as Punjab that when Mr. Bahuguna convened the conclave, the major opposition political parties like Mr. Fernandes' new party to which he has migrated, depriving Mr. Charan Singh of his company, Janata Party and BJP led by Mr. Vajpayee boycotted. Even Chowdhary Charan Singh who has waxing eloquence about Punjab, said he is not going to that conclave, he has nothing to do with it. Imagine, Sir ! The national parties in their state of crippled inactivity, paralysis, need creches and the creches were provided by Dr. Abdullah from Kashmir and N.T. Rama Rao, with his *krishma*, with his magic, was requisitioned to persuade the national parties to join that conclave... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : Why are you interrupting ? Please sit down....(*Interruptions*).

PROF. MADHU DANDAVATE : Ask your partners in the Kerala coalition..... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : Mr. Tewary, if you are saying somebody is obsessed with, why should you be obsessed with Mr. Bahuguna also ?

PROF. K.K. TEWARY : Is it the way they approach the national issues ? The whole attempt is farsical. This occasion and this time of the House should have been utilised for reaching unanimity, should have been utilised for diagnosing the real issue. The whole question has been diverted against the same syndrome and the anti-Indira Gandhi campaign. Some of them have quite a professionalism in this muck

raking but this will not take us anywhere. Even Mr. Chandrajit Yadav, our erstwhile colleague, now the present colleague in Parliament also seems to have been swayed by propaganda offencing of Mr. Fernandes and Mr. Bahuguna. I put it to Mr. Bahuguna and the Opposition Leaders that they decided to go to Punjab. A delegation of the Opposition was to go to Punjab..... (*Interruptions*).

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Hou many times he migrated ? I want to know his political alliances. Hc is sermonising.

PROF. K.K. TEWARY : This is shameful....(*Interruptions*).

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Why shameful ? You are doing character assassination and what is your character ? ...(*Interruptions*).

MR. SPEAKER : Professor, I am no longer interested in this cavalcade of going and coming. I am already fed up with this.

PROF. K.K. TEWARY : Sir, I will speak only on few points. The Opposition was saying that the Government has failed. They say that they want a solution and the entire united Opposition was to send a delegation to Chandigarh and to Amritsar and they were proposing to meet Sant Longowal and all others and find out a solution. What happened ? Why only Mr. Bahuguna went ? Why did other friends of Mr. Bahuguna threw him like a hot potato ? This House is entitled to know as to why the national Opposition, the Opposition Parties of India, sit together, hammer out a solution and then when it comes to the crunch, when it comes to the negotiations, only Mr. Bahuguna goes ? And what does he talk to Longowal, who knows ? Mr. Bahuguna is in search of a constituency. He has no love for anything. As usual, he has no love for principles and not much love for the integrity of this country. Therefore, I charge, this is my charge that the whole thing is being brought to the level of a small petty dispute.

23.00 hrs.

Sir, have the Government of India closed the doors on negotiations ? The doors of the Government of India are open for negotiations. Only the other day the hon. Home Minister in the Rajya Sabha extended an invitation and stated that the doors are still open, from our side we are prepared to talk with the Akalis and reach a solution. So, attempts have been made.

The last point which I would like to mention is one which will provoke them, I am sorry to say. I cannot help it. This is how you are projecting yourself ..(*Interruptions*). The Punjab issue has to be approached very dispassionately. You are getting impatient. You are talking of communal issues. You want votes. The Indian National Congress has been winning all these decades ; since 1952 we have been winning. Shri Bahuguna was also part of our outfit for many years. Fortunately or unfortunately, many of you were in our party. Do you honestly believe that it is only the communal votes that were responsible for our victory ? Are you speaking the truth ?

On this issue, I would once again very humbly make a fervent appeal. Whether it is Punjab or Assam, if you view it in the correct perspective, our problems are getting internationalised ; insidious attempts are being made to internationalise even the small problems of India. There is a definite attempt by outside forces, with the help of their allies and stooges inside India, to dismember this country. I think some of the people who are now going round as pedlars of democracy, as pedlars of free democratic political process, they are hand in glove, they are in league, with outsiders, who want to dismember this country, who want to bring down Mrs. Gandhi, because they know that the continuance of Mrs. Gandhi alone will ensure the unity and integrity of this country. Therefore, I vehemently oppose this adjournment motion. I would not like to lambast anybody or pillory anybody, but I would make a humble request to the hon. Members opposite to do some bit of introspection. Shri Bahuguna is beyond redemption but even now, at this stage, something can come about from introspection. I hope they will do it.

MR. SPEAKER : I also hope that in

future whenever any member speaks, he will address the other members in the proper way, and not by names. It is better that they refer to the handbook.

PROF. K.K. TEWARY : Now that two or three leaders remain present in this House, I put it to them, after how many months Shri Bahuguna has come to this House ; similarly, after how many months Shri Jagjivan Ram and Shri Chandrasekhar have come to this House.

MR. SPEAKER : It is their responsibility.

PROF. K.K. TEWARY : It should be known to this country.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : On how many occasions the Prime Minister is present in this House ?

SHRI H.N. BAHUGUNA : Sir, on a matter of personal explanation.

MR. SPEAKER : No aspersion has been cast on you.

SHRI H.N. BAHUGUNA : He has cast an aspersion on me by asking how many times I was present in the House.

MR. SPEAKER : It is not an aspersion.

SHRI H.N. BAHUGUNA : The hon. Shri Tewary has spoken about it...(*Interruptions*) He referred to it in the context of the dignity of this House. Whether we remain here or not, the Leader of the House should be in the House at least on important occasions.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : Sir, I am grateful to you that after 11 hours of debate you have very kindly asked me to get up.

MR. SPEAKER : I am also thankful for your patience, please.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDAR : No, it will be 9 hours of debate.

MR. SPEAKER : That amendment I will accept.

SHRI P.C. SETHI : I also amend it, Sir, accordingly.

Sir, originally the House is aware that I wanted to make a *suo moto* statement on Punjab so that we could discuss the Punjab situation dispassionately and through the joint wisdom of this august House we could reach some conclusions which would be beneficial for resolution of the Punjab question. But, Sir, the Opposition Members were keen not to solve the Punjab tangle, but they were keen to censure the Government, they were keen to admonish the Government. Their real anxiety was censuring of the Government and not the solution of the Punjab problem. Therefore, ultimately, although it had come on the agenda paper that I have to start by making a statement, you agreed to their representation and you allowed the adjournment motion. And, therefore, as far as we are concerned, we have to go by what you say and we accepted the situation. But this does not mean that we are supporting the adjournment motion.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : How can you do it ?

PROF. MADHU DANDAVATE : You are not willing to censure yourself.

SHRI P.C. SETHI : Sir, as far as the Punjab problem is concerned, the hon. Members are aware of the fact that whenever the Akali Party was in power right from 1962 many a time in Punjab, and from 1977 to 1980 even in the Centre, they were in the coalition, any problem about Punjab territorial dispute or water dispute did not arise and even if they wanted to speak about it, the then Prime Minister, Shri Morarji Desai, refused to talk about it. I have come to know that once when Mr. Morarji Desai, the Prime Minister, visited Punjab and Mr. Badal wanted to say something on this issue, he refused to talk to him. But when Mrs. Indira Gandhi came to power and the Akalis lost power in Punjab, then all the problems started. But Akalis also know it that it is only Indira Gandhi who is prepared to talk to them with sympathy and who is in a position to resolve the situation. Sant Longowal himself has said it and Mrs. Gandhi was

magnanimous enough to invite them for talks. They came here. During the talks they were progressing well, but before the talks could be finalised, the Akali Dal had made up their mind that they would boycott the talks and that they would not disclose even to the press, and this is how the talks broke at that point of time. But even then, the Prime Minister continued with the efforts, she appointed a Cabinet Committee to go into the whole matter and we again invited the Akali Dal leaders to Delhi for talks. They refused to come to Delhi for talks, they wanted Chandigarh to be the venue for the talks, and not once but twice—one on 11.1.1983 and the second time on 18.1.1983. The Cabinet Committee and all the Members of the team went to Chandigarh to talk with them. We were able to talk dispassionately on all the subjects and all the points including the religious demands. The talks were, however, inconclusive and we wanted to resume the trend once again in Delhi. But we found reluctance on their part. At that point of time a suggestion came from the leaders of the opposition, if we can be helpful in solving the problem then we should also be made a party to it. Shrimati Gandhi immediately agreed to this suggestion and she said that there should be a tripartite talk and we requested the opposition leaders representing all the groups to come for tripartite talks.

Some hon. Members have quoted me by saying that during the last debate on Punjab I have said in this House that to some extent on certain issues the opposition parties were helpful in reducing the arena of differences and to come to certain conclusions. There was some sort of consensus. It is true that Anandpur Sahib Resolution they did not accept. It is also true that when the Rajasthan Question of water dispute came, they also said that this question cannot be re-opened. Akalis were also good enough to leave their demand as far as Himachal Pradesh and Ganganagar of Rajasthan is concerned. It is not that portion of the opposition that is to be blamed for. That I have already spoken in the House and I am again repeating it. But of recent the trend of the opposition parties and some of the leaders of the opposition parties has completely changed. Now, as far as Shri Atal Behari Vajpayee party is concerned, we are unable to understand where do they stand ? Sometimes he supports the gurudwaras and sometimes he talks of the temples. We are unable to know whether he is preferring to choose to go to heaven or preferring to choose in between the heaven and hell. The situation, as far as B.J.P. is concerned, is absolutely fluid. They do not want to commit anything anywhere.

Chaudhari Charan Singh was very clear right from the beginning that we should not be soft with the Akalis and we should deal with them firmly. He was a complete supporter of the Haryana demands. Even today he has supported what the Shah Commission had given the verdict with regard to Haryana i.e. the Kharar Tehsil and Chandigarh should be a part of Haryana. But I do not know what made him agree to go to the meeting of the conclave which was held in Delhi. It was said, as he himself agreed here that on the request and pressure from the friends and friendly parties he agreed to go there. However, he was a party to whatever was said there. But the next day he was again good enough to repudiate what was decided.

As far as the talks are concerned, we try to hold the situation. We made it very clear that we cannot resolve this problem without consulting the people of Rajasthan and the people of Haryana. Thereby we want that the ruling Party of Rajasthan and Haryana and the Opposition Leaders of Rajasthan and Haryana have to be consulted. The Akalis refused to sit with them. But the Opposition Leaders agreed to sit with them and we discussed the whole problem with these Parties and the leaders of Haryana and Rajasthan. There was some exchange of view and ultimately, as I said, during the tripartite talks, the conclusions or consensus have been reached on certain points.

Again, ultimately when the question of territorial demands came, the Akalis decided to boycott the talks. First of all, it would

have been much better if the Akalis would have said that their high-power team would talk or participate in this tripartite conference so that the issues could be clinched because they have to always consult the Amritsar people any they have not been in a position to clinch the issue. However, it was left to them to send whatever type of team they wanted but we wanted that all these things should be resolved in an amicable manner.

Now, with regard to the position which the Akali Dal has taken and the stand which the Opposition Leaders have taken, it has also completely changed. When they say that Chandigarh should be transferred to Punjab, immediately they quote Mrs. Indira Gandhi's award. They forget that Mrs. Gandhi's award has two parts. One portion is that Chandigarh will go to Punjab and the second portion is that Abohar and Fazilka will go to Haryana. The second portion is conveniently forgotten and immediately the question of transfer of Chandigarh came. Sir, Mrs. Gandhi, all the Congress Party people and the Cabinet were completely against the division of Chandigarh. But some friends approached us stating that the Akalis could agree to 40 : 60 division of Chandigarh and asked should they carry out the negotiation. We gave them the signal, "Yes, you can carry out the negotiation with them". But even on this, though the Akalis had agreed to those friends who had approached us in private talk, they ultimately refused and backed out of this.

Now, with regard to the papers circulated to the hon. Members by Sant Longowal today, I would like to say that it is not only the religious demands but on many things he has gone back. He has raised a separate nation theory, multi-nation theory for India. As I have said in the other House when one hon. Member from the DMK Party was speaking, India may be multi-lingual, India may be multi-racial and India may be multi-cultural but India is one nation and the Indian people have sacrificed for keeping India as one nation and we shall continue to make all sacrifices to keep India as one nation. (*Interruptions.*) These pamphlets which have been circulated to the hon. Members have shown many things on which they have gone back.

Now, as far as the river water dispute is concerned, they have also gone back on this. They have brought in the idea of Riparian rights in the context of water dispute which is recognition of equal rights to the use of water by all owners of land. As far as the question of riparian rights is concerned, this phrase is used in the international arena whenever there is a dispute between two separate countries with regard to the sharing of water. As far as the doctrine of riparian rights is concerned, it used to be invoked in the resolution of water disputes between different sovereign States. This doctrine, however, has become somewhat archaic and is being progressively replaced by the doctrine of equitable apportionment. This doctrine has been widely accepted and connotes that waters of an inter-State river are not the absolute monopoly of one co-riparian State alone and that each State has a vital interest in the waters and must so use the water with the minimum of detriment to the other States.

This doctrine does not accept either the riparian right theory or the Harmon doctrine. Even if we go by the question of riparian States, then, as a matter of fact, Kashmir and Himachal Pradesh are the real riparian States wherefrom all the rivers flow.

PROF. MADHU DANDAVATE : That controversy has ended already. Why rake it up again ?

SHRI P.C. SETHI : Because it has been raked up again.

It would be pertinent to point out that the principle of equitable apportionment was followed by the Indus Commission which had been appointed by the Governor-General under Section 131 of the Government of India Act, 1935, in a dispute between Punjab and Sind. The recommendations of the Indus Commission revealed that it did not uphold the Harmon doctrine whereby upper riparian State could dispose of the water in her territory as she liked irrespective of the injury to the lower riparian State,

It may not be correct to invoke the principle of riparian rights in a dispute between two or more States in India. Such a dispute, if it is a water dispute within the meaning of Section 2(c) of the Inter-State Water Disputes Act, 1956, is to be dealt with according to the provisions of the Act. Nor can the doctrine of riparian rights be invoked to resolve the dispute relating to the vesting of the control of headworks which may be located in a particular State of the Union. It would be plausible to say that the dispute relating to the control of waters of an inter-State river is a water dispute and as such should be resolved in the manner laid down in the Act.

By virtue of Section 3 of the Act, a State Government, if it appears to a State Government that a water dispute with another State has arisen or is likely to arise, can request the Central Government to refer the water dispute to a Tribunal for adjudication. I think, Mr. Bahuguna also raised it as to why this particular question was not immediately handed over to a Tribunal. In the Act itself it has been provided. As envisaged by Section 4 of the Act, the Central Government has to, in the first instance, make efforts for settling the dispute by negotiations. If the negotiations do not reach a conclusion, it is only in that case that according to this Act a river water dispute is to be handed over to a Tribunal.

Now, if the Punjab people or the Akali Dal leaders are prepared to stick to what was agreed to in the tripartite talks, that is, if they do not want to touch the question of Rajasthan waters as agreed between India and Pakistan in 1956, then we have made this offer that, as far as the river water dispute is concerned, we are prepared to hand it over to the Tribunal under this Act. As far as the Chairmanship of the Tribunal is concerned, we are prepared to have it decided by discussion. They want it to be handed over to the Supreme Court. But according to the Act, it has to go to a Tribunal. It cannot go to the Supreme Court.

During the debate some hon. Members have raised some points which I must necessarily reply. I am sorry to say that particularly Mr. Bahuguna has raised the question of the Prime Minister not being present here, thereby trying to prove that not only she is not giving proper attention to this problem but also not paying respect to this House. This is most improper. The entire Cabinet and I myself who is responsible to answer this debate are present here and we represent the Government...

SHRI H.N. BAHUGUNA : You are not the Leader of the House.

SHRI P.C. SETHI : ....and, therefore, it is not necessary that she should be physically present here. But she has been hearing the debate in her room.

PROF. MADHU DANDAVATE : What is the good of that ? Can you point out to me a single important debate when Pandit Nehru ever remained absent ?

SHRI P.C. SETHI : I do not know whether you were there or not.

PROF. MADHU DANDAVATE : I was very much there in the country.

SHRI P.C. SETHI : Now, some of the Hon. Members have.....

SHRI H.N. BAHUGUNA : What is the view you take on this ? May I know what the Home Minister's view is, whether the Leader of the House has or has not been in the House ? She is not only the Prime Minister but she is the Leader of the House also.

PROF. MADHU DANDAVATE : He said that she is listening from her own room. Is it a substitute for the Chamber of the Parliament ?

SHRI P.C. SETHI : I am trying to explain that it is not necessary for her to be present.

(*Interruptions*)

Don't try to make an issue of it.

I am also sorry to say that some Hon. Members have said that the ruling party is

responsible for the divisive forces and Chowdhary Saheb went to the extent of saying that Panditji used to attend some functions of the Kashmiri Pandits. As far as the Kashmiri Pandits' social functions are concerned, it might be possible that Panditji might have gone there but, he never attended any caste function as far as the Kashmiri pandits or any other caste is concerned. I think most of the Opposition leaders who have got respect for Shri Jawaharlal Nehru, even now although they are in Opposition, would realise the situation that he was the only man who was above caste and who was above religion and who was.....

SHRI RAVINDRA VARMA (Bombay North) : What about Mahatma Gandhi ? Why do you say that Shri Jawaharlal Nehru is the only man ?

(*Interruptions*)

SHRI P.C. SETHI : This accusation was made because Panditji happened to be Prime Minister. Mahatma Gandhi was never Prime Minister.

(*Interruptions*)

SHRI RAVINDRA VARMA : Why do you say he is the only man ?

SHRI P.C. SETHI : It was also unfortunately mentioned here that Prime Minister wants to make her son Shri Rajiv Gandhi the Prime Minister of India. It is cent per cent wrong because she herself.... .

(*Interruptions*)

She herself has said that she does not want to thrust anybody. It is for the people to choose and the Indian people, through this system of voting and democracy, have displayed a very wide wisdom. Wherever they wanted the Congress Party to come, the Congress Party has come. Whenever they wanted the Congress Party to go, the Congress Party has gone. Therefore, this type of question which is raised in this House, is not only trying to destroy the whole situation but disrespect shown to the integrity and wisdom of the Indian people and the democratic forces in the country.

(*Interruptions*)

Mr. George Fernandes again tried to come very heavily on Mr. Gandhi. From what he has said, he is quoting from one newspaper 'National Herald'. But, my own information is—and it is authentic information—that Mr. Gandhi never said that the Akali demands would not be accepted. What he said was that demands would never end and they would keep on taking new ones for their political survival and, therefore, if some newspaper has misprinted it or the real version has not come, then, it was not proper for Mr. Fernandes to.....

(*Interruptions*)

I would not rely on Mr. Bahuguna on anything unless it is verified.

AN HON. MEMBER : Including Mr. Bahuguna, you need not rely.

SHRI P.C. SETHI : Therefore, Sir, as far as the present trend of the Opposition parties is concerned, they have actually, by today's debate, not helped in any manner in the solution of the Punjab tangle. As far as we are concerned, we have given a positive formula.

SHRI H.N. BAHUGUNA : Do you need our help in any manner ? Indicate that.

SHRI P.C. SETHI : Mr. Bahuguna, if you were able to resolve this issue, then we would certainly need your help. But I know you are absolutely helpless to resolve this.

(*Interruptions*)

As I have pointed out, we are prepared to resolve both the disputes. As far as the water dispute is concerned, we are prepared to hand it over to a Tribunal which can be presided over, as the hon. Members have said, either by a Supreme Court judge or by a retired Supreme Court judge.

श्री मनीराम बागड़ी : आपने ट्रिब्यूनल को दे दिया है। लेकिन एस० वाई० एल० की खुदाई होगी या नहीं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अभी ट्रिब्यूनल को दिया नहीं है।

We are prepared to give. But at the same time it was agreed during the tripartite talks also that the digging of the SYL canal would start and the Akalis would not obstruct it. Therefore, subject to this condition, we are prepared to hand over the water dispute between Haryana and Punjab excluding Rajasthan—as far as the water dispute is concerned.

(*Interruptions*)

With regard to the religious demands, I have already said that the Prime Minister has announced that the religious demands have been accepted and in principle even the Gurudwara Act has been accepted. But we cannot accept the Gurudwara Act without the consent of the respective Gurudwaras and the respective States. This we had made clear even at that time and we are making it clear even now. Therefore, we have got to obtain the consent of the respective States as well as the respective Gurudwaras. Formally we have not yet received even the names of those Gurudwaras. Informally, originally they said five ; now they are saying twelve. But, as a matter of fact, they are more than 95. Therefore, all those people have to be consulted.

As far as relay of the kirtan is concerned, we accepted one hour in the morning and half an hour in the evening which was their original demand, but unfortunately when our people from All India Radio went there, they went back on it and they said, 'No, now we want it for three hours'. We had also said that for whatever time it is relayed, they would have to pay for it. But when they pressed that they would not like to pay for it, that would not appear good, the Prime Minister was good enough to accept this and said, 'Allright : you may not even make the payment'.

As far as kirpan is concerned, originally six-inches kirpan including the handle was accepted. Although during the tripartite talks we did not discuss this issue, outside their representative said, 'No ; the blade length should be six inches and the handle could be any length'. We ultimately agreed that the blade could be of six inches, and the handle would be three inches. Otherwise, the handle could be a much bigger one in order to make it very forceful. Therefore, that demand was also met.

As far as the Amritsar question is concerned, we agreed to this and they also agreed to this that the precincts round about the Golden Temple and the precincts round about the Durgiana Temple will be treated as holy places and there sale of liquor, meat, tobacco, would not be permitted. But on that we raised this point at that point of time that supposing by chance somebody is found smoking there, then quarrels will start and recently one of the cases of this type has happened and the quarrel started on this when one gentleman was found smoking there. Therefore, the religious, demands have been by and large met by us.

As far as Centre-State relationship is concerned, as have already announced the appointment of the Sarkaria Commission. Now it was asked by Mr. Indrajit Gupta as to what is the progress of the Sarkaria Commission. Name of another Member has been announced ; the third one is likely to be announced very shortly and the terms of reference have been finalised. He has been given Cabinet status and the necessary staff and the Secretary whom he wanted have been appointed. He has been provided with accommodation not only for his living but for his office also.

We have made it very clear that the Sarkaria Commission would start its work in the right earnest and the concerned States are free to raise the points before them and we have even said that if they want to raise even constitutional issues before it, they are free to do so and it is for the Sarkaria Commission to consider all those points raised by the States or individuals.

With regard to the extremists, I must make it clear that we have been right from the beginning condemning the extremists and their violent activities. It is unfortunate that some of the parties in the beginning did not do this and in spite of our repeated requests as far as the violent activities are concerned, the Akali Dal

absolutely disowned them and never condemned any sort of violence which occurred in Punjab. Now recently we have started taking some more measures.

Law and order arrangements have been strengthened in Punjab. Nakabandhi and Police patrolling have been organised to prevent violent crimes. The intelligence machinery has been geared up and the police set up has been re-organised. A ban on pillion riding on motor cycles has been imposed in all districts of Punjab. Restriction on carrying of fire arms has been put. A ban on plying of and above 3.5 hp. motor cycles has been imposed in certain areas. A special drive to unearth unlicensed arms and ammunition has been started and the Police officers have been asked to take steps to protect known targets of extremists. The peace and communal harmony committees have been activated in all districts and all places of Punjab. Powers of judicial magistrates have been given to executive magistrates for speedy trial of cases against extremists and other elements. Therefore, really a drive has been started and in this connection, I would like to mention that as yet about 1101 persons have already been arrested till 15th July 1983 and 483 cases have been registered against them. Therefore, as far as the extremists and violent activities are concerned, we have started a drive. We would certainly like you to condemn violence and also help in seeing to it that violence at any cost is stopped and the communal harmony between the Hindus and the Sikhs in Punjab is maintained at all costs.

I, therefore, strongly reject and oppose the adjournment motion.

श्री मनीराम बागड़ी : गुरुद्वारों में क्रिमिनल लोग हैं यह आपका बयान राज्य सभा में आया। और भिन्डरावाला का यह बयान है कि कोई भी क्रिमिनल गुरुद्वारों में नहीं है। दोनों में कौन-सा ठीक है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : राज्य सभा में मैंने जो कुछ कहा था उसके बारे में मेरी गैरमौजूदगी में मेरे साथी श्री वेंकटसुब्बय्या ने कहा यह कोई अल्टीमेटम नहीं था···

श्री मनीराम बागड़ी : अल्टीमेटम नहीं। आपने कहा गुरुद्वारों में क्रिमिनल और ऐक्सट्रीमिस्ट्स पनाह ले रहे हैं। लेकिन भिन्डरावाला का कहना है कि कोई भी क्रिमिनल और ऐक्सट्रीमिस्ट गुरुद्वारों में नहीं है। तो दोनों में कौन सत्य है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सत्य हम हैं। बागड़ी साहब, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि सत्य हम हैं।

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : Mr. Speaker, Sir, may I have one clarification ? I think he has already stated that. But, I would like him to state it categorically and, with necessary emphasis, that the Akali Dal, even till to-day, refused to condemn violence on the part of these extremists. (*Interruptions*)

SHRI P.C. SETHI : Sir, on this point, I said that they have not categorically denounced this. (*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : I would like to know whether you would condemn police action. If violence is to be condemned, then why are you not condemning a few atrocities by the police ? (*Interruptions*)

SHRI P.C. SETHI : Prof. Chakraborty, I would also request you to condemn violent activities which are taking place in Bengal.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : We do condemn violence everywhere and even the violence perpetrated by your party. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Now, the Professor should sit down. The question is :

"That the House do now adjourn".

Those in favour may say 'Aye'.

SOME HON. MEMBERS : 'Aye'

MR. SPEAKER : Those against may say 'No'

SEVERAL HON. MEMBERS : 'No'

MR. SPEAKER : The 'Ayes' have it, the 'Ayes' have it...

AN HON. MEMBER : The 'Noes' have it.

MR. SPEAKER : Let the Lobbies be cleared...

SHRI SATISH AGARWAL : We are not challenging this.

MR. SPEAKER : When they say that they want it, I have to do that. Even if one Member wants it, I have to do that. I cannot help it.

Lobbies have been cleared but the decision has not been challenged. The question is :

"That the House do now adjourn."

The Motion was negatived.

MR. SPEAKER : The adjournment motion is negatived. The House will now take up item No. 24 of the agenda. Rao Birendra Singh.

23.46 hrs.

THE NATIONAL OILSEEDS AND VEGETABLE OILS DEVELOPMENT BOARD BILL

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : Sir, I beg to move*

> "That the Bill to provide for the development under the control of the Union of the oilseeds industry and the vegetable oils industry and for matters connected therewith, be taken into consideration".

MR. SPEAKER : You may continue tomorrow. The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. tomorrow.

23 47 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July, 27, 1983/ Sravana 5, 1905 (Saka)

---

*Moved with the recommendations of the President.